HVS/GB/2

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

21 मार्च, 1995

खण्ड 1, अंक 10

अधिकृत विवरण

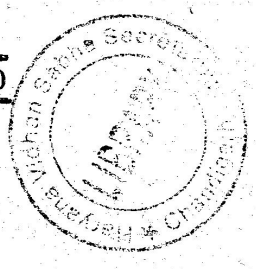

Haryana Vidhan Sabha Secretariat * Chandigarh

विषय सूची

मंगलवार, 21 मार्च, 1995

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(10)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(10)32
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(10)37
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–	
समस्त जिला फरीदाबाद में प्रदूषण सम्बन्धी	(10)38
वक्तव्य—	
उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी	(10)39
वाक आउट	(10)43
वर्ष 19995–96 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(10)44
वाक आऊट	(10)71
वर्ष 1995–96 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(10)72
बैठक का समय बढ़ाना	(10)83
वर्ष 1995–96 के बजट पर सामान्य, चर्चा (पुनरारम्भ)	(10)83
बैठक का समय बढ़ाना	(10)89
वर्ष 1995–96 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(10)89

मूल्य :

193 00

ERRATA

To

Haryana Vidhan Sabha Debates Vol. 1, No. 10, dated the 21st March, 1995

Read	For	Page	Line
पूछें	पूछें	7	5
एलजी	एलजीं	7	6
गवाह	ग्वाह	9	6
बैंक	बक	10	31
सफाई	सफाइ	12	23
31.7.94	31.4.94	27	4
कितलाना	कतिलाना	27	22
पहलादगढ़	पेहलगांवगढ़	27	22
दादरी	दादरो	27	25
चिता	चिता	32	29
Reservation	Reserveration	38	
Read	Read	38	26
संयन्त्र	संयंत्र	39	29
पोल्यूशन	पोलयशन	41	21
मेरी	मरी	43	32
महोदया	महोदय	45	1
मैनीफस्टो	मैनीस्फटो	45	34
एडवर्टाईजमेन्ट्स	एडवर्जिमैन्ट्स	49	19
झूठे	झठे	54	5
बढ़ेगी	बढ़गी	56	19
की	के	62	25
माध्यम	माध्मम	69	9
धर्मेन्द्र	धमेन्द्र	71	30
उपक्रमों	उपक्रमों	79	35
महोदय	महीदय	80	6
प्रो0 राम बिलास शर्मा	प्रो0 राम बिलाश शर्मा	81	23
चौधरी भजन लाल	चौधरी भजन लाल	82	8
ठीक	ोक	85	10
इसका	सका	85	16
टैक्नीकल	टक्नीकल	86	21

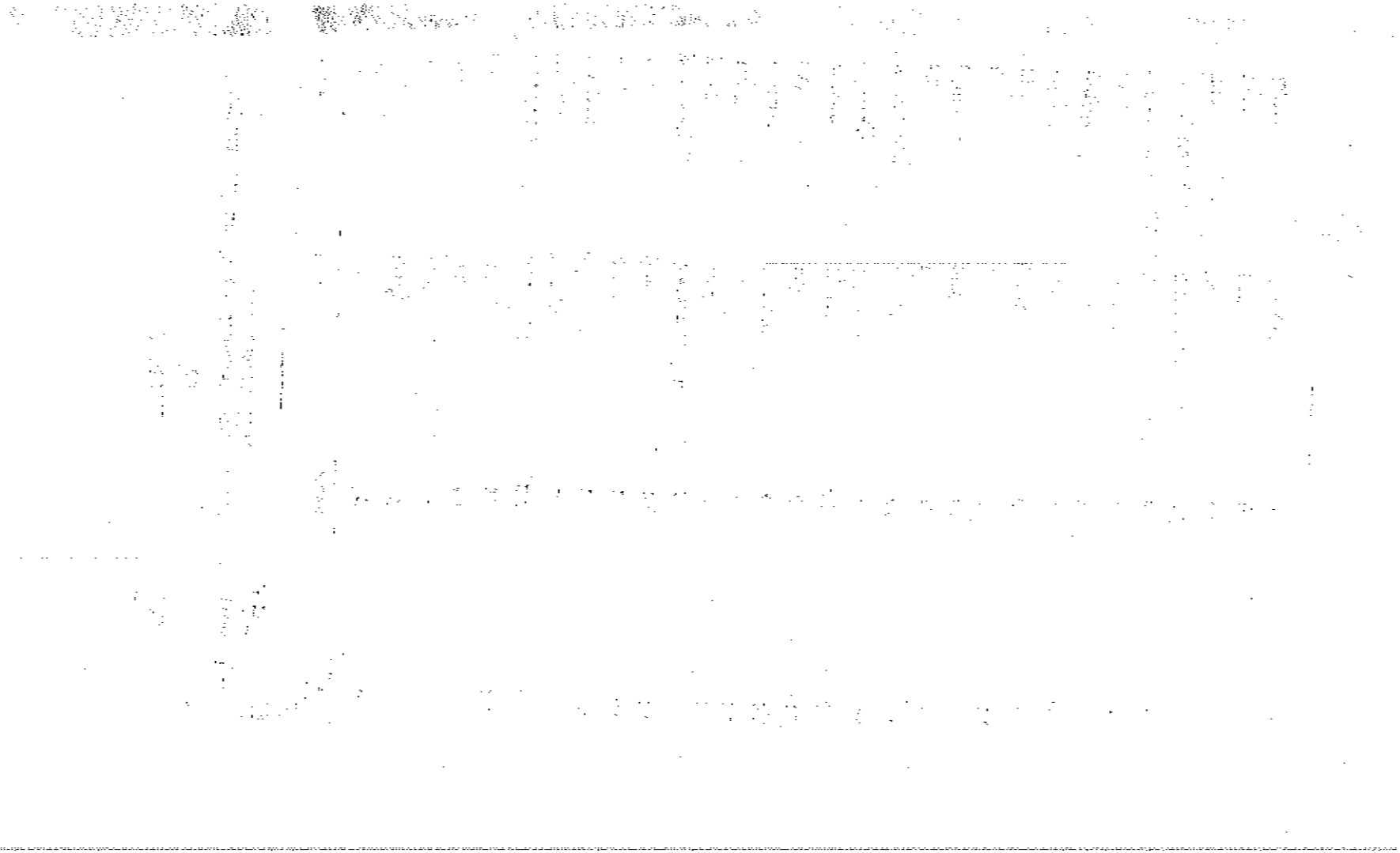

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 21 मार्च, 1995

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर- 1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (चौधरी ईश्वर सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : मैम्बर साहेबान, अब सवाल होंगे।

Repair of Dam

*1137. **Shri Krishan Lal :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) whether the Dam on Yamuna River in village Tamsabad, district Panipat at Burji No. 2 and 3 is in damaged condition; and

(b) if so, the time by which the said Dam is likely to be repaired ?

Irrigation Minister (Ch. Jagdish Nehra) :

(a) Yes. The bund along River Yamuna in village Tamsabad in reach RD 1600 to 2300 was damaged during floods of 1994.

(b) The bund will be repaired before monsoon of 1995 on availability of funds.

श्री कृष्ण लाल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि तमसाबाद बांध का काम कब तक हो जाएगा ? अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने सवाल के जवाब में यह बताया है कि तमसाबाद डैम 1994 में टूटा था, क्या सरकार को अब तक उसको ठीक करने की सुध नहीं आई है ? अध्यक्ष महोदय, बुर्जी 1600 से 2300 तक यह बांध टूटा है। मन्त्री जी ने दूसरा जवाब दिया है कि धन की उपलब्धि पर इसको बनवाया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, 10-12 गांव इससे बिल्कुल बरबाद हो रहे हैं क्योंकि बांध में 100 से 200 मीटर तक के कट लगे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या वर्तमान बजट में इस बांध के लिए कोई पैसे का प्रावधान किया गया यदि किया गया है तो कब तक इस बांध को कम्पलीट करवा देंगे ?

चौधरी जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने अर्ज किया है कि इस बार की मौनसून जो कि जुलाई महीने तक आएगी, इसको इस साल कर दिया जाएगा । स्पीकर सर, जैसे मैंने माननीय साथी को बताया कि यह बांध 700 फुट तक लगातार काफी टूट गया है । 26-7-1993 को यमुना रिवर में 93 हजार क्यूसिक पानी आ गया था जिसकी वजह से यह नुकसान हुआ है। दिनांक 2-2-1995 को फ्लड कण्ट्रोल बोर्ड की मीटिंग में इस मामले को रखा गया था । इस फ्लड कण्ट्रोल बोर्ड के चेयरमैन माननीय मुख्य मन्त्री जी हैं, उन्होंने इस बांध के लिए 50 लाख रुपये का प्रावधान किया है । जल्दी ही सारा पैसा मिल जाएगा और 740 फुट बांध जो टूट गया है या जो उसमें कटाव हुए हैं, उनकी रिपेयर हो जाएगी । जो कटाव आए हैं, उनके लिए 3 स्टड्ज बनाने के लिए तथा मुरम्मत के लिए 50 लाख रुपये मानसून के शुरू होने से पहले-पहले इस काम को करने के लिए खर्च कर दिए जाएंगे ।

श्री कृष्ण लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक दूसरा सप्लीमैंटरी है जो बहुत ही जरूरी है । मैं कहना चाहता हूं कि जब कहीं बान्ध टूट जाता है तो फसल बिल्कुल बरबाद हो जाती है जिसका मुआवजा किसानों को दिया जाना चाहिए । मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि इस बांध के टूटने से जिन किसानों की फसलें बरबाद हुई हैं, क्या उनको मुआवजे के रूप में कोई राशि दी गई है; यदि दी गई है तो कितनी राशि दी गई है ?

चौधरी जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि फसलों के लिए किसानों को मुआवजे के रूप में कोई राशि नहीं दी गई है । अध्यक्ष महोदय, बांध के टूटने से किसानों की फसल कुछ खराब हुई है । इस बांध के टूटने का कारण यह है कि यू0पी0 साईड में उन्होंने स्टड्ज काफी बड़े-बड़े बनाए हैं । हमने इस बारे में सी0 डब्ल्यू 0 सी0 में अपना एतराज भी दर्ज किया है । इसकी वजह से बांध टूटते हैं और लम्बे स्टड्ज की वजह से हमारा नुकसान होता है क्योंकि रिवर जो है, वह रास्ता बदल लेती है, यह एतराज हमने दर्ज करवाया है । दूसरे माननीय श्री कृष्ण लाल जी ने यह पूछा है कि किसानों को कोई मुआवजा दिया गया है या कि नहीं ? मैं उस बारे में इनको बताना चाहूंगा कि इसके लिए किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है ।

श्री0 राम विलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी को यह बताना चाहता हूं कि बाढ़ के समय महेन्द्रगढ़ जिले में तीन जगह से बांध टूट गया था । मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या वे प्राथमिकता के आधार पर इसको ठीक करवाएंगे ?

चौधरी जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल का मेन सवाल से कोई सम्बन्ध नहीं है । जो ये कह रहे हैं वह यमुना का ऐरिया है । स्पीकर सर, जहां

का ये कह रहे हैं हम पूरी कोशिश करेंगे कि जहां–जहां बांध टूट गया है उसको ठीक करवाया जाये ।

Upgradation of School of village, Singwal

*1048. **Shri Bharath Singh** : Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the school of village Singwal to 10+2 system school in District Kaithal ; and

(b) if so, the time by which the aforesaid school is likely to be upgraded ?

शिक्षा मन्त्री (चौधरी फूल चन्द मुलाना) :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री भरथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने जवाब दिया है कि प्रश्न ही नहीं उठता । मन्त्री जी तो कोई काम करके राजी नहीं हैं। स्पीकर साहब, 10–12 गांवों के लोगों की डिमांड है कि गांव सिंगवाल के स्कूल को अपग्रेड किया जाए । सिंगवाल, अदकन, नयोधार, भालूत खेड़ीशेरखां, सीसर, ढाकल, थोह, बदड़याना आदि । इन गांवों के लोगों की यह डिमांड है कि इस स्कूल को अपग्रेड किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि लोगों की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए, क्या सिंगवाल के स्कूल का दस जमा दो में दर्जा बढ़ाया जाएगा ?

चौधरी फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस स्कूल के बारे में पूछा है वह नार्मज पूरे नहीं करता है। इस स्कूल में नौवीं कक्षा में 23 बच्चे और दसवीं कक्षा में 26 ही बच्चे हैं । इतने बच्चों पर दस जमा दो नहीं बन सकता है ।

Cases of Rape/Murder etc. registered in the State

*1093. **Prof. Sampat Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of cases of murder/rape, kidnapped/abducted registered in the State during the year 1994-95 to date ;

(b) the number of cases out of those referred to in part (a) above relate to minors and the persons belonging to Schduled Castes and Backward Classes ;

[Prof. Sampat Singh]

(c) the number of cases out of those referred to in part (a) above remain unsolved and the number of cases in which arrests have not been made so for ; and

(d) the number of cases ; if any, out of those referred to in part (a) above have been handed over to C.B.I. togetherwith the details thereof ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : विवरण तालिका सदन के पटल पर रखी है ।

"स्टेटमैंट"

भाग (क)

अपराध का शीर्षक	दर्ज किय गये मुकदमें :	
	1994	1995 (28-2-95 तक)
हत्या	661	78
बलात्कार	254	46
अपहरण/अपनयन	350	75

भाग (ख) उपरोक्त भाग (क) में से

	अवयस्क		अनुसूचित जातियां		पिछड़ी श्रेणियां	
	1994	1995	1994	1995	1994	1995
हत्या	18	3	35	1	13	1
बलात्कार	82	9	36	4	26	9
अपहरण/ अपनयन	57	9	39	2	12	1

भाग (ग) 1. हल न हो सके मुकदमों की संख्या :

	1994	1995 (28-2-95 तक)
हत्या	48	1
बलात्कार	8	1
अपहरण/अपनयन	15	—

2. मुकदमों की संख्या जिनमें गिरफ्तारी नहीं हुई है

	1994	1995 (28-2-95 तक)
हत्या	83	16
बलात्कार	11	4
अपहरण/अपनयन	68	15

भाग (घ) सी0बी0आई0 को दिये गये मुकदमों की संख्या तथा ब्यौरा :

	1994	1995
हत्या	1	1
बलात्कार	—	—
अपहरण/अपनयन	—	—

1. सतिन्द्र सिंह सेखों की हत्या से संबन्धित मुकदमा नं 89 दिनांक 16-7-94 धाराधीन 302/34/449/120-बी. भा0द0स0 तथा 25/30/54/59 शस्त्र अधिनियम थाना सदर अम्बाला, दिनांक 12-8-94 को सी0 बी0 आई0 को दिया गया जो जेर समायत है ।

2. रणबीर सिंह सुहाग की हत्या से सम्बन्धित मुकदमा नं0 5 दिनांक 9-1-95 धाराधीन 365/302 भा0द0 स0 थाना सिविल लाईन रोहतक दिनांक 22-1-95 को सी0बी0आई0 को दिया गया जिसमें तफतीश की जा रही है ।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी ने बताया कि सूचना सदन के पटल पर रखी गई है और सूचना के मुताबिक 28-2-95 तक मर्डर केस 739, रेप केसिज 300 और किडनैपिंग/ऐबडक्शन के 425 केस हुए हैं । इसमें मोस्टली मर्डर, रेप और किडनैपिंग वगैरह माईनर्ज कलासिज के केस हैं जो एस0सीज0 और बी0सीज0 लोगों के साथ हुए हैं । मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मर्डर के कितने ऐसे केसिज हैं जो पुलिस कस्टडी में हुए हैं या जिनमें पुलिस के लोग इन्वाल्वड हैं ? रेप के कितने ऐसे केसिज हैं, जिनमें पुलिस के लोग इन्वाल्वड हैं । किडनैपिंग/रैनसम के कितने केसिज हैं ?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सवाल तो कुछ और पूछा था और अब कुछ और ही पूछ रहे हैं । ये इस बारे में अलग से पूछ लें तो हम अलग से बता देंगे । इन्होंने तो टोटल नम्बर पूछे थे और वे हमने इनको बता दिए हैं । इस बारे में ये जवाब को पढ़ कर देख लें ।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने सप्लीमैंटरी पूछी है और उसमें मर्डर केसिज के बारे में पूछा है। ग्रुप्स में झगड़ा हो जाए तो मर्डर के केस होते हैं। पुलिस थानों में मर्डर के केसिज होते हैं और किडनैपिंग के बाद मर्डर केसिज होते हैं। मैं तो इनसे यह पूछ रहा हूं कि पुलिस कस्टडी में कितने मर्डर केसिज हुए हैं ?

श्री अध्यक्ष : सम्पत सिंह जी, आगे भी इसी तरह का प्रश्न आ रहा है और उसमें यह पूछा गया है। अब आप बैठ जाएं।

Prof. Sampat Singh : I am asking supplementary, Sir.

Mr. Speaker : No. Please take your seat.

Prof. Sampat Singh: Why the Chief Minister is trying to hide the facts ? (interruptions)

Mr. Speaker : You may kindly give a separate notice.

Prof. Sampat Singh : But this supplementary arises out of this question. (Interruptions) Why the Government is trying to hide the facts ? If the Government is not prepared to reply to my supplementary, then the Government can say that they will reply afterwards. If the Government is ready, the reply should come now.

Mr. Speaker ; Sampat Singh Ji, please take your seat.

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, 1994 में हत्या के 661 केसिज हुए हैं जिनमें 22 केसिज कैंसिल हुए, 48 केसिज अंदमपता हैं, 472 केसिज में चालान हुए और उनमें से 435 केसिज न्यायालय में विचाराधीन हैं। इसके इलावा, 119 केसिज जैरे-तफतीश हैं। हमने इनको टोटल आंकड़े बताए हैं लेकिन ये पूछ रहे हैं कि किस थाने में कितने लोग मारे गए।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, मैं थानों के बारे में नहीं कह रहा हूं बल्कि मैं तो पुलिस कस्टडी के बारे में पूछ रहा हूं। आप ही बताएं कि फिर सप्लीमैंटरी क्या हो सकती है ?

बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) : स्पीकर सर, इन्होंने केवल रजिस्टर्ड केसिज के बारे में पूछा है कि कितने केसिज रजिस्टर्ड हुए हैं, कितने कत्ल हुए हैं इसलिए इससे तो सप्लीमैंटरी अराईज ही नहीं होती।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, मैं रजिस्टर्ड केसिज में से ही पूछ रहा हूं। ये तो टोटल फिगर्ज हैं मैं इनमें से ही पूछ रहा हूं। पुलिस थानों के अन्दर जो लोग मारे जाते हैं वहां पर 302 का ही केस बनता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसे केसिज कितने हैं ?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने टोटल केसिज पूछे हैं और टोटल केसिज के ही हमने आंकड़े दे दिए हैं ।

प्रो0 सम्पत सिंह : स्पीकर सर, इनका टोटल आंकड़ों के बारे में रिटन जवाब आ गया है, यह तो मैं भी जानता हूं ।

श्री अध्यक्ष : आप केवल प्रश्न पूछें ।

प्रो0 सम्पत सिंह: सर, पुलिस वालों की बात से तो इनको एलर्जी है । इसलिए मैं अपना दूसरा सवाल यह पूछना चाहता हूं कि फिरौती यानी रैनसम के कितने केसिज हुए हैं ? (Interruptions) He is well prepared to reply but he is hiding the facts. सर, मैं इसमें यह पूछना चाहता हूं कि इन केसिज में से कितने केसिज के चालान पुट–अप हो चुके हैं ? इसके अलावा, मैं इसमें यह भी पूछना चाहता हूं कि एम0डी0 यूनिवर्सिटी के अन्दर जो प्रो0 रणबीर सिंह सुहाग का मर्डर हुआ था, उस केस में अब क्या प्रोग्रेस है ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, 1994 में 661 मुकदमें कत्ल के दर्ज हुए, जिनमें से 22 केसिज कैंसिल हो गए । 48 केसिज अदमपता हैं और 472 केसिज में चालान हो गए, जिसमें से 37 बरी हो गए और 435 केसिज न्यायालय के पास विचाराधीन हैं । इसके अलावा, 119 केसिज जैरे तफतीश हैं । इसी तरह से 1995 में कत्ल के 78 केसिज हैं, जिनमें दो केसिज कैंसिल हो गए, एक अदमपता है और सात केसिज में चालान हो गए हैं । इसी तरह, से अध्यक्ष महोदय, 1994 में हत्या के 254 केसिज थे जिनमें से 14 केसिज कैंसिल हो गए, आठ अदमपता हैं और 225 केसिज में चालान हुए जिनमें से एक केस में सजा हो गयी है और 14 बरी हो गए तथा 210 केसिज कोर्ट में विचाराधीन हैं और चार केसिज जैरे तफतीश हैं । इसके अलावा, अपहरण और दूसरे अन्य केसिज 350 है जिसमें 81 केसिज कैंसिल हो गए, 15 अदमपता हैं और 173 केसिज में चालान हुए, 12 बरी हो गए और तीन में सजा हो गयी एवं 158 केसिज कोर्ट में विचारा–धीन हैं और 81 केसिज जैरे तफतीश है । इसी तरह से 1995 में हत्या के 78 केसिज थे जिनमें से दो केसिज कैंसिल हो गए, एक अदमपता है तथा 64 केसिज में चालान हुए। इसी तरह से बलात्कार के 46 केसिज थे, जिसमें दो कैंसिल हो गए, एक अदमपता है । तीन केसिज के चालान हो गए। तीन केसिज कोर्ट में विचाराधीन हैं और चालीस केसिज जैरे तफतीश हैं । अध्यक्ष महोदय, यह आंकड़े मैंने इनको दिए हैं । इसके अलावा, रणबीर सिंह सुहाग के बारे में भी इन्होंने कहा है । अध्यक्ष महोदय, यह केस सी0बी0आई0 के जैरे तफतीश है। सी0बी0आई0 इसकी जांच कर रही है । आप जानते हैं कि जब सी0बी0आई0 केस ले लेती है तो आगे की कार्यवाही भी वही करती है । हम उनसे कोई भी इंफर्मेशन लेते या देते नहीं हैं ।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, मैं एक बात इन से कैटेगरीकली पूछना चाहता हूं । पुलिस कस्टडी में लेखू हत्याकांड के बारे में जैसा कि पुलिस के वर्शन में आया है कि जब अपराधी को ले जा रहे थे तो रास्ते में कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया और दो लोगों को मार दिया । स्पीकर सर, जिन दो लोगों को हमला करके कुछ लोगों ने मारा है क्या उस केस में कोई गिरफतारी हुई है या नहीं हुई है ? उस केस की अब क्या प्रोग्रेस है ? वह केस तो आपकी पुलिस के पास ही है । सर, यह भी बड़ा सीरियस मामला है क्योंकि जब वे लोग पुलिस कस्टडी में जा रहे थे तो उसके बावजूद भी कुछ लोगों द्वारा उन पर हमला हुआ और वहां दो लोग मारे गए । सर, पब्लिक में यह धारणा है कि ये लोग फाल्स एनकाऊंटर में मार दिए गए थे और अगर वे लोग इस तरह से नहीं मारे गए हैं तो उस केस की प्रोग्रेस के बारे में मुख्य मंत्री जी हमें बता दें कि क्या उस केस में कोई गिरफतारी हुई है या नहीं हुई है ?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, उसमें बाकई दो आदमी मारे गए । उसकी जांच एक सीनियर डी०एस०पी० कर रहे हैं । अभी तक तफतीश जारी है । पूरी तफतीश होने के बाद हम बताएंगे कि इस केस में किसका फाल्ट है, कैसे हुआ, कौन मुलजिम है ? सही मामला पूरी तफतीश के बाद सामने आएगा, तब बता दिया जाएगा ।

श्री अध्यक्ष : आपने जो यह डैथस इन पुलिस कस्टडी और इन एनकांटर पूछा था आगे इस बारे में 24 मार्च, 1995 को श्री छतर सिंह चौहान का क्वैश्चन आ रहा है जो यह है :—

> "Will the Chief Minister be pleased to state the total number of deaths, if any, occured in Police custody and in encounter with the police during the period from July, 1991 todate in the State togetherwith the detaills thereof"

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, रैनसम के बारे में जवाब नहीं आया, किडनैपिंग रैनसम के लिए हुई है । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: उसके लिए आप अलग से क्वैश्चन दें ।

प्रो० राम विलास शर्मा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन्होंने अपने लिखित जवाब में 1994 में जो मुकदमें हल नहीं हो सके, उनकी संख्या इस प्रकार बताई है :—हत्या के 48 मामले हल नहीं हो सके, बलात्कार के 8 और अपहरण के 15 मामले हल नहीं हो सके । इसी तरह जिन मुकदमों में गिरफतारी नहीं हुई उनका ब्यौरा भी दिया है । हत्या के 83 मुकदमें ऐसे बताए हैं, जिनमें गिरफतारी नहीं हुई, बलात्कार के 11 और अपहरण के 18 मुकदमें ऐसे बताए हैं, जिनमें गिरफतारी नहीं हुई । मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हत्या जैसे जघन्य अपराध में और अपहरण व बलात्कार के

इतनी बड़ी संख्या में मुकदमें हैं, जिनमें गिरफतारी नहीं हुई, जो हल नहीं किए जा सके, इसके क्या कारण हैं ?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इसके कई कारण हैं । बड़ा कारण यह है कि एक हत्या हो गई और मुलजिम को किसी ने देखा नहीं । मुलजिम का एफ0आई0आर0 में नाम दर्ज नहीं करवाया । पुलिस तफ़तीश करती है । हत्या हो गई लेकिन कोई ग्वाह नहीं, कोई बताने वाला नहीं । अध्यक्ष महोदय, कई ऐसे केसिज भी हैं जिनमें शिनाख्त नहीं हो सकती । शिनाख्त नहीं हो तो गिरफतारी नहीं की जा सकती । इन हालात में जब तक सामने कोई सबूत न आएं, 302 के मामले में सजा होना बड़ा भारी मुश्किल है ।मुलजिम वही पकड़ा जाना चाहिए जो सही माने में मुलजिम हो । सबूत बाकायदा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों, तभी गिरफतारी की जाती है, चाहे वह केस बलात्कार का है, चाहे हत्या का है।

Irregular Supply of Drinking Water

***1100. Shri Dhir Pal Singh** : Will the Minister for Public Health be pleased to state—

(a) the number of villages of Jhajjar and Bahadurgarh Sub-Divisions which are facing drinking water problem; and

(b) if so, the steps taken or proposed to be taken to provide regular supply or drinking water in the villages as referred to in part (a) above ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमती शान्ति देवी राठी) :

(क) उप–मण्डलवार गांवों का ब्यौरा जहां पेयजल समस्या गम्भीर है निम्न–लिखित हैं :

झज्जर उप–मण्डल	= 27
बहादुरगढ़ उप–मण्डल	= 4
	31

(ख) इन गांवों में पीने के पानी की कमी का मुख्य कारण नहरी पानी का अपर्याप्त मात्रा में, उपलब्ध होना है । फिर भी जून, 1995 के अन्त तक 14 गांवों में स्वीकृत अनुमानों के अन्तर्गत कम गहराई वाले नलकूप लगाकर पेयजल उपलब्ध कराने की संभावना है । झज्जर उप–मण्डल के शेष 13 गांवों में पेयजल समस्या केवल पर्याप्त मात्रा में नहरी पानी उपलब्ध होने पर ही दूर की जा सकती है क्योंकि इस क्षेत्र में

[श्रीमती शान्ति देवी राठी]

भूगर्भ जल स्त्रोत खारा होने के कारण कम गहराई वाले नलकूप लगाना संभव नहीं है।

जहां तक बहादुरगढ़ उप-मण्डल का सम्बन्ध है, दो गांवों में पेयजल व्यवस्था स्वीकृत अनुमान के अन्तर्गत कम गहराई वाला नलकूप लगवाकर प्रदान करने की संम्भावना है, परन्तु शेष 2 गांवों में नहरी पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने पर ही सुधार होगा।

श्री धीर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री साहिबा ने यह स्वीकार किया है कि झज्जर उप-मण्डल में 27 और बहादुरगढ़ उप-मण्डल में 4 गांव ऐसे हैं, जहां पेयजल की समस्या गम्भीर है। उनका टोटल 31 बनता है। इसी तरह की आशंका मैंने कल भी जाहिर की थी, मैं तो यही कहूंगा कि झज्जर सब-डिवीजन में व बहादुरगढ़ सब-डिवीजन में सरकार ने नहरी पानी का स्वयं ही बेड़ा गर्क कर दिया है, सारा पानी हमसे इन्होंने छीन लिया। लोग पानी के लिये तरस रहे हैं। पानी का गम्भीर संकट इन इलाकों में आ गया है। मैं मुख्य मन्त्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि 1991 से पहले का ये रिकार्ड उठा कर देख लें तब आज के अनुपात से पानी ज्यादा आता था। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री महोदया से जानना चाहता हूं कि जो इन्होंने अपने जवाब में माना है कि 14 गांवों में जून, 1995 तक शैलो ट्यूबवैल्ज लगाकर पेयजल उपलब्ध कराने की सम्भावना है, यह स्कीम किन-किन गांवों की है और इन पर कितनी राशि लगने की सम्भावना है ?

श्रीमती शान्ति देवी राठी : अध्यक्ष महोदय, झज्जर उप-मण्डल के 27 गांवों में से 10 गांवों में कम गहराई वाले ट्यूबवैल्ज लगाये जा चुके हैं और उन पर खर्चा आया है 3.52 करोड़ रुपये। शेष 9 गांवों में हमारी जो योजना है, वह विभाग के अनुसार जून, 1995 तक की है लेकिन मैं इस हाउस में कहती हूं कि जुलाई-अगस्त 1995 तक इन गांवों में कम गहराई वाले ट्यूबवैल्ज लग कर तैयार हो जाएंगे जिन पर लागत आएगी लगभग 1.65 करोड़ रुपये। शेष जो 8 गांव और बच गए हैं, उनकी समस्या तब हल हो जाएगी जब कि सिंचाई विभाग पीने के पानी का पूरा प्रबन्ध करेगा। अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अपने विभाग के बारे में दो-तीन बातें विस्तार से कहना चाहूंगी। जहां तक जन स्वास्थ्य विभाग का सम्बन्ध है, यह अन्य दो विभागों पर डिपैन्ड करता है। वैसे हमारे अपने बहुत सुयोग्य इंजीनियर्ज हैं और पैसे का भी विशेष अभाव नहीं है क्योंकि वर्ल्ड बैंक की सहायता हमें मिल रही है। हरियाणा के अन्दर जो विकास के कार्य हो रहे हैं, वैसे तो अध्यक्ष महोदय आप पूरी तरह से जानकार हैं। इस बारे में, विकास के प्रतीक आदरणीय मुख्य मन्त्री महोदय से यह कहूंगी कि अगर वे इस बात को सुनिश्चित कर दें कि जहां-जहां हमारा कैनाल बेस्ड सिस्टम है, उसके

अन्तर्गत सिंचाई का पानी कहीं आये या न जाए लेकिन स्वच्छ पानी लोगों तक अवश्य ही जाएगा । इस के साथ-साथ सिंचाई विभाग को भी वे कड़े आदेश इस बारे में दे दें कि कैनाल बेस्ड स्कीम्ज के तहत पानी टेलों तक अवश्य जाना चाहिये । जो गाद नहरों में जम गई है, उसको तुरन्त ही निकलवाया जाए ताकि सभी टेलों तक आगे पानी जा सके । मुख्य मन्त्री जी, दूसरी बात यह है कि आप बिजली विभाग को कड़े आदेश दें कि जैसे ही हमारा ट्यूबवैल तैयार हो या जल घर तैयार हो तो वे हमें फौरन कनैक्शन दे दें । कंडक्टर हमारा अपना विभाग देता है और खम्भे वे लगाते हैं। वे फौरन खम्भे लगा दें। (शोर)

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, यह मन्त्री जी कैसा जवाब दे रही हैं ? यह तो इनकी कैबिनेट का मामला है । (शोर)

Mr. Speaker : Shanti Devi ji, please take your seat. All the departments of the Government are one and different departments are not water tight compartments. This is a matter of coordination of the functions of the Government.

श्रीमती शान्ति देवी राठी : मैं अपने आदरणीय मुख्य मन्त्री जी से अनुरोध कर रही हूं कि अगर ऐसा हो जाए तो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी और लोगों को पीने का पानी मिल जाएगा ।

चौधरी जिले सिंह जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदया से जानना चाहता हूं कि इन 27 गांवों में पानी की कमी कब से है ? इसके अलावा, जिन गांवों में मीठा पानी है, क्या उनमें भी ऐसे ट्यूबवैल्ज लगाने की कोई स्कीम विचाराधीन है ?

श्रीमती शान्ति देवी राठी : ऐसे गांवों की डिटेल आपके पास हो सकती है। अगर आप कुछ गांव सुनिश्चित कर दें कि इनमें मीठा पानी है तो विभाग वहां ट्यूबवैल लगा देगा । जहां तक यह बात है कि 27 गांवों में पानी की कमी कब से है, यह आपकी सरकार के समय की समस्या है । हमने तो दस गांवों का समाधान कर दिया है और 9 गांवों में ट्यूबवैल लगा दिए हैं । बाकी के गांव कैनाल वाटर बेस्ड हैं ।

चौधरी जिले सिंह जाखड़ : स्पीकर साहब, आज हालत यह है कि वाटर सप्लाई स्कीम की जगह पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं ।

श्रीमती शान्ति देवी राठी : यह तो अच्छी बात है कि बच्चे क्रिकेट खेलते हैं । (शोर)

श्री धीर पाल सिंह : स्पीकर साहब, मन्त्री महोदया ऐसा ***** जवाब दे रही हैं । आज विरोधी पक्ष के हल्कों में वाटर सप्लाई स्कीमें सूखी पड़ी है और वहां पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं । और ये कहती हैं कि अच्छी बात है कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं ऐसी बात कहते हुए इनको **** आनी चाहिए । (शोर)

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया ।

श्री अध्यक्ष : ये शब्द रिकार्ड पर न लाये जाएं

10.00 बजे

श्री धीर पाल सिंह : स्पीकर साहब, मंत्री महोदया ने जिन 9 गांवों में शैलो ट्यूबवैल लगाए हैं, उनके नाम बताए हैं और यह भी बताया है कि इतने गांवों में और लगाने हैं। स्पीकर साहब, पिछले सैशन में भी मैंने यह आपत्ति जाहिर की थी, उस समय कंवर साहब इस विभाग के मंत्री थे और आज भी मैं बहन जी को यह जानकारी देता हूं कि खुगाई गांव की पंचायत ने अपने पैसे से वहां पर ट्यूबवैल लगाया हैं और उस ट्यूबवैल की बिजली का खर्चा खुद गांव के लोग उठा रहे हैं। उस समय मुण्डा खेड़ा गांव के बारे में यह आश्वासन दिया गया था कि दो महीने के अन्दर उस गांव में पीने के पानी की व्यवस्था कर दी जाएगी लेकिन आज 8 महीने हो गए। उस गांव में आज तक पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की गई है। उस गांव के साथ एक इसमाईलपुर गांव है। वहां पर शैलो ट्यूबवैल है। उसके साथ उसको कनैक्ट किया हुआ है, लेकिन उस ट्यूबवैल का बिजली का कनैक्शन न मिलने के कारण काम अधूरा पड़ा है। उस ट्यूबवैल को बिजली का कनैक्शन नहीं मिल पा रहा है। मंत्री महोदया ने जिन 9 गांवों में शैलो ट्यूबवैल लगवाए हैं, उनके बारे में मंत्री महोदया यह बता दें कि किस-किस गांव में कब-कब शैलो ट्यूबवैल लगवाएं हैं और उनको बिजली का कनैक्शन कब तक दिला कर पीने का पानी मुहैया करवा देंगे ?

श्रीमती शांति देवी राठी : स्पीकर साहब, मैं माननीय सदस्य को उन 27 गांवों के नाम बता देती हूं। वे हैं सिलानी, फिर सिलानी, सिलाना, कछरौली, घिराना, खेड़ी होसदरपुर, हसनपुर, कछरौली, कालीवास, घिराना, मरोट, खेड़ी होसधरपुर, हुसनपुर, रणखेड़ा, खुगाई, बजीदपुर, उखल चना, टम्बाखेड़र, उसमानपुर, नीयोला, गवालीसौन, मरोट, सुभाना, खानपुर, खेड़ी होसादपुर, गिजरोध और हसनपुर गिजरोध।

श्री सूरजमल : स्पीकर साहब, बहादुरगढ़ में वाटर सप्लाई स्कीम के म्यूनिसिपल कमेटी के दो टैंक हैं उनमें दो-दो अढ़ाई अढ़ाई फुट गाद जमी हुई है। उनकी सफाई नहीं हुई है। तकरीबन वन-थर्ड पानी उनमें कम आता है। इसी तरह से जो हुड्डा की नहर गुड़गांव जाती है, उसमें भी गाद जमी हुई है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि उस नहर की और उस दोनों टैंकों की सफाई कब तक करवाने का प्रावधान है, क्या उनकी सफाई करने का कोई सिस्टम बना रखा है ? जो हुड्डा की नहर गुड़गांव जाती है क्या उसका पानी बहादुरगढ़ शहर के लोगों को पीने के लिए मिलेगा, अगर मिलेगा तो कितना हिस्सा मिलेगा ?

श्रीमती शांति देवी राठी : स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने इस बात को स्वीकारा है कि नहर में गाद काफी जमी हुई है, उसकी वजह से जल स्तर कम हुआ है और पानी पूरी मात्रा में नहीं आ रहा है। जहां तक उनकी सफाई की बात है वह हमारा विभाग अवश्य करवा देगा, क्योंकि उसमें पानी आना अनिवार्य है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारी जो कनाल बेस्ड वाटर सप्लाई स्कीम्ज हैं, उनकी

गाद निकाली जाए ताकि पानी पूरी मात्रा में आए। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि पिछले दिनों गाद निकालने का काम युद्ध स्तर पर हुआ है। मेरे खुद के हल्के की राजपुरा माईनर में गाद जमने के कारण टेल पर पानी आने में दिक्कत थी, लेकिन अब उसकी सफाई कर दी गई है और अब उसकी टेल पर दो फुट पानी आता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि चालू वित्तीय वर्ष में गाद निकालने का काम युद्ध स्तर पर हुआ है।

श्रीमती चन्द्रावती : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया ने माना है कि पीने के पानी के लिए नहर के पानी पर निर्भर करना पड़ता है। मैं मंत्री महोदया से जानना चाहूंगी कि जहां पर मीठा पानी है, क्या वहां पर बोरिंग वैल के जरिए पानी लोगों को मुहैया करवाएंगी ?

श्रीमती शांति देवी राठी : सरकार का यह दायित्व है कि प्रत्येक नागरिक को पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध हो। बहन जी जहां-जहां पर बोरिंग वैल्ज की लिस्ट देंगी और वहां पर मीठा पानी होगा, ऐसी जगहों पर बोरिंग वैल्ज लगाने का काम युद्ध स्तर पर करके लोगों को पानी उपलब्ध करवाएंगे।

श्री राम भजन अग्रवाल : क्या मंत्री महोदया बताएंगी कि स्टेट में शैलो ट्यूब-वैल्ज कुल कितने हैं ? दूसरे मैं यह जानना चाहूंगा कि जिन गांवों के लोगों ने अपने खर्च पर शैलो ट्यूबवैल्ज लगा रखें हैं, क्या सरकार उनका खर्च वहन करेगी ?

श्रीमती शांति देवी राठी : सरकार ऐसे ट्यूबवैल्ज का खर्च वहन नहीं करेगी। नहरी पानी का जहां तक सवाल है, जहां पर भी गाद होगी उसको निकलवाने का काम पूरा करेंगे और टैंकियों की भी सफाई करायेंगे।

चौधरी जिले सिंह जाखड़ : वैसे तो यह सारे हरियाणा की समस्या है। क्योंकि जो पानी की टैंकी है, उसका टेल पर पानी नहीं पहुंच पाता। क्या वहां पर पानी पहुंचाने का प्रबंध सरकार करेगी ? दूसरे किन-किन गांवों में मीठा पानी है, क्या उनका सर्वे सरकार करवायेगी ?

श्रीमती शांति देवी राठी : टेल पर पानी पहुंचाने के लिए हम सुनिश्चित करेंगे। सरकार यह भी पता लगवा लेगी कि कहां-कहां पर मीठा पानी है।

श्री धीर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, बहादुरगढ़ में 9 गांव ऐसे हैं जहां पर शैलो ट्यूबवैल्ज नहीं और ये गांव कैनाल वाटर पर आधारित हैं। मेरा कहना यह है कि हुड्डा की जो गुड़गांव कैनाल है क्या उससे इन गांवों को सामूहिक रूप से पीने के पानी का कनैक्शन दिया जायेगा ?

श्रीमती शांति देवी राठी : इस समय तो मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे पूरी जानकारी इस स्कीम की नहीं है। यदि होने वाली बात हुई तो हम पानी उपलब्ध करवाएंगे।

Amount spent on Desilting of Canals in Bhiwani District

***1028 Prof. Chhattar Singh Chauhan :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state the yearwise and canalwise amount spent on the desilting of Canals in Bhiwani District during the period from 1990 to July, 1994?

सिंचाई मन्त्री (चौधरी जगदीश नेहरा) : नहरों में से गाद निकालने का कार्य वर्ष 1990-91, 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 और 1-4-94 से 31-7-94 तथा 1-4-94 से 28-2-95 में किया गया। प्रत्येक नहर पर किए गए खर्च की राशि का ब्यौरा निर्धारित तालिका में संलग्न एनैक्सचर-1 में दर्शाया गया है।

अनैक्श्चर–1

जिला भिवानी में पड़ने वाली प्रत्येक नहर से प्रतिवर्ष गाद निकालने का खर्चा

क्रमांक	नहर का नाम	गाद निकालने पर किया गया खर्चा रु0 लाखों में					
		1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95 1-4-94 से 31-7-94	1-4-94 से 28-2-95
1	2	3	4	5	6	7	8
क.	यमुना जल सेवाएं परिमण्डल भिवानी						
	भिवानी जल सेवाएं मण्डल भिवानी						
1.	भिवानी डिस्ट्रिब्यूटरी	2.26	0.87	0.59	0.05	—	3.99
2.	दादरी ,,	3.35	0.38	—	0.77	—	1.14
3.	सुन्दर ,,	3.90	0.93	0.30	1.29	—	0.18
4.	बौन्द ,,	1.04	0.17	0.18	—	—	0.45
5.	गुजरानी माईनर	3.20	0.19	0.21	0.59	—	2.27
6.	उमरा ,,	—	0.89	0.20	—	—	—
7.	बवानी खेड़ा ,,	0.45	0.80	0.30	—	—	—
8.	खनक ,,	0.39	0.25	0.18	—	—	2.02
9.	तालू ,,	0.82	1.75	0.28	1.05	—	—
10.	बलियाली सब ,,	0.20	0.31	—	0.14	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	भुरताना माईनर	0.74	1.01	0.32	0.48	—	—
12.	धमाना ,,	0.49	0.72	—	0.10	—	—
13.	कैसे ,,	0.77	0.30	—	—	—	—
14.	तिगड़ाना सब माईनर	0.20	0.05	—	0.05	—	—
15.	बापोड़ा ,,	0.24	0.15	0.10	0.02	—	—
16.	मँणी माहु ,,	0.15	0.20	—	—	—	—
17.	कुसम्भी ,,	0.19	0.23	—	—	—	0.20
18.	फोगाट ,,	0.12	—	—	—	—	—
19.	सांगा ,,	0.31	0.13	—	—	—	0.74
20.	वहलवा ,,	0.19	0.14	0.16	—	—	0.25
21.	भांभवी ,,	0.18	—	—	—	—	—
22.	डांग ,,	3.61	0.63	0.95	0.25	—	1.50
23.	सुई सब माईनर	0.12	—	0.06	0.01	—	0.10
24.	पालूवास ,,	0.04	—	—	—	—	0.05
25.	मानहेरू ,,	0.50	0.16	—	—	—	1.70
26.	साझरवास माईनर	0.46	—	0.12	0.56	—	1.58
27.	भागेसवरी ,,	0.13	—	0.16	—	—	0.47
28.	हालूवास ,,	0.08	0.72	0.12	0.14	—	0.20
29.	1 एल डांग	0.29	—	—	—	—	0.26
30.	रनकौली सब ,,	0.06	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	खरक कलां माईनर	0.19	0.14	—	0.59	—	0.26
32.	बामला ,,	0.68	0.86	0.28	1.41	—	1.01
33.	मिसरी ,,	0.12	—	—	0.07	—	—
34.	पुलपुरा ,,	0.05	—	—	—	—	—
35.	राजपुरा सब ,,	—	0.11	0.06	0.01	—	—
36.	खगड़ ,,	—	0.25	0.17	—	—	—
37.	भैणी भैयो माईनर नं0 1	—	0.10	—	—	—	—
38.	दादरी फीडर	—	0.88	—	—	—	0.05
39.	बड़ेसरा माईनर	—	0.25	—	—	—	—
40.	रिवासा ,,	—	0.24	—	0.24	—	—
41.	मिथाथल फीडर	—	0.02	—	0.17	—	0.66
जल सेवाएं मण्डल भिवानी							
1.	जुई फीडर	0.59	0.35	—	—	—	0.96
2.	जुई कैनाल	0.86	0.66	0.24	—	0.54	—
3.	बहल डिस्ट्रीब्यूट्री	0.86	0.39	—	0.20	1.03	1.66
4.	मालावास माईनर	—	—	—	0.08	—	0.07
5.	घोराना ,,	0.60	0.40	0.02	0.31	—	0.18
6.	देवसर सब ,,	—	9.20	0.16	—	—	—
7.	केहरपुरा ,,	0.18	0.15	—	—	—	—

[चौधरी जगदीश मेहरा]

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	1 एल माईनर	0.11	—	0.09	—	—	—
9.	टिटानी ,,	—	0.26	0.09	0.51	—	0.15
10.	1 आर सब माईनर	0.11	0.08	—	—	—	—
11.	चैनपुरा माईनर	0.22	0.16	0.11	0.14	—	—
12.	नकटा ,,	0.27	0.19	0.10	0.25	—	—
13.	लेघा ,,	0.41	0.37	0.18	0.15	—	3.27
14.	शिमलीवास सब माईनर	0.03	0.07	0.00	0.06	—	—
15.	ढांगर माईनर	0.26	0.13	0.09	0.13	—	0.11
16.	खारीयावास ,,	0.99	0.89	0.13	0.34	—	0.53
17.	2—आर सब ,,	0.04	—	—	—	—	—
18.	पाथरवाली ,,	1.02	0.89	0.37	0.08	—	0.58
19.	ढाभढाणी सब ,,	—	0.12	—	—	—	—
20.	लालावास ,,	0.64	0.43	—	0.12	—	—
21.	श्रोबेरा	0.18	0.48	—	—	—	—
22.	बिजियाना सब ,,	0.22	0.17	—	0.08	—	—
23.	बरथु सब माईनर	0.08	—	0.30	—	—	—
24.	देवरासा सब माईनर	0.09	0.17	0.09	0.10	—	—
25.	गोकलपुरा ,,	0.19	0.19	—	0.13	—	—
26.	बिदनोई सब ,,	0.14	0.18	0.20	0.12	—	—
27.	कासनी ,, ,,	0.10	0.09	—	0.05	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	3 आर सब माइनर	0.27	0.15	—	0.17	—	—
29.	सुरपुरा माईनर	0.09	0.27	0.31	0.09	—	—
30.	सिरवा ,,	9.03	—	—	—	—	—
31.	निगाना फीडर	0.92	0.37	—	—	—	—
32.	निगाना कैनाल	0.47	1.11	0.28	0.39	—	—
33.	खड़कड़ी डिस्ट्रीब्यूट्री	—	—	0.05	—	—	0.08
34.	निगाना ,,	0.66	0.29	—	0.73	—	—
35.	निगाना हिल ,,	0.42	0.27	0.20	—	—	0.13
36.	दुलहेड़ी ,,	0.17	0.33	0.12	—	—	0.22
37.	माहू डिस्ट्रीब्यूट्री	0.40	0.50	—	0.25	—	0.26
38.	गुभा ,,	0.20	0.11	0.06	—	—	—
39.	झावेरी ,,	—	0.18	0.08	—	—	—
40.	सरल ,,	0.10	0.20	0.14	—	—	0.12
41.	आलमपुर ,,	0.19	—	—	—	—	—
42.	दादम ,,	0.44	0.40	—	0.19	—	—
43.	दादम हील ,,	0.27	0.19	—	0.12	—	0.04
44.	बालावास ,,	0.85	0.72	—	—	—	—
45.	सागवान माईनर	0.20	0.25	0.15	—	—	0.72
46.	मानसरवास ,,	0.15	0.07	0.04	—	—	—
47.	बागनवाला ,,	0.36	0.30	—	0.16	—	0.05

1	2	3	4	5	6	7	8
48.	कांवारी माइनर	0.54	0.20	—	—	—	0.17
49.	कांवरी सब ,,	0.35	0.16	—	0.23	—	0.54
	सिवानी जल सेवाएं मण्डल भिवानी						
1.	सान्धवास डिस्ट्रीब्यूट्री	0.32	0.40	0.38	—	—	—
2.	भरीवास माईनर	0.40	0.59	—	—	—	—
3.	बदौला ,,	0.51	0.40	—	—	—	—
4.	हसन डिस्ट्रीब्यूट्री	0.15	0.59	—	—	0.38	—
5.	साहलेवाला माईनर	0.19	0.20	—	—	—	—
6.	सलीमपुर डिस्ट्रीब्यूट्री	—	0.79	—	—	0.50	—
7.	शिधानूवा माईनर	0.15	—	—	—	—	—
8.	धारापुर डिस्ट्रीब्यूट्री	—	—	—	—	—	—
9.	भूधाली माईनर	—	—	—	—	—	—
10.	बेनी मिरा माईनर	—	—	—	—	—	—
11.	धाणीधीरजा माईनर	—	—	—	—	—	—
12.	गोदवा डिस्ट्रीब्यूट्री	—	—	—	—	—	—
13.	किरण डिस्ट्रीब्यूट्री	—	—	—	—	—	—
14.	एन डी फीडर	—	—	—	—	—	—
15.	घेरपुरा डिस्ट्रीब्यूट्री	—	—	—	—	—	—
16.	गुफा माईनर	—	—	—	—	—	—
17.	मिथी डिस्ट्रीब्यूट्री	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	गोसियान वाला माईनर	—	—	—	—	—	—
19.	गंगला माईनर	—	—	—	—	—	—
20.	मथौली माईनर	—	—	—	—	—	—
21.	ममैतीपुरा माईनर	—	—	—	—	—	—
(ख) लोहारू जल सेवाएं परिमण्डल, भिवानी							
1.	उमरावास माईनर	0.11	0.13	0.04	0.06	—	—
2.	हूडी वाला डिस्ट्रीब्यूटी	0.55	—	—	—	—	—
3.	रूपगढ़माईनर	0.20	0.28	—	0.52	—	0.52
4.	विजना माईनर	0.13	0.06	0.06	—	—	0.10
5.	अटेला डिस्ट्रीब्यूटी	0.19	0.15	0.24	0.24	—	0.08
6.	भेहरा ,,	0.21	0.15	0.12	0.12	—	—
7.	नांगल माईनर	0.20	0.07	—	—	—	—
8.	कूराल डिस्ट्रीब्यूटी	0.50	0.46	0.27	0.44	—	—
9.	दूधवा माईनर	0.07	—	0.10	—	—	—
10.	पेतांवास ,,	0.06	—	0.08	0.06	—	—
11.	पटवान ,,	0.03	—	—	—	—	—
12.	पोखरवास ,,	0.05	—	—	—	—	—
13.	सिसवाल सब ,,	0.32	0.08	—	0.40	—	0.18
14.	कालूवाला ,,	0.04	0.07	—	0.03	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	पोखर सब माईनर	0.13	0.05	0.05	—	—	—
16.	मीरी पुर ,,	0.06	0.03	—	—	—	—
17.	गोठड़ा ,,	0.21	—	0.20	0.23	—	—
18.	बरही ,,	0.06	—	—	0.07	—	0.11
19.	कतिलाना डिस्ट्रीब्यूट्री	0.88	1.00	0.39	0.10	—	0.10
20.	जोझू माईनर	0.19	0.16	0.06	—	—	—
21.	रेहरोथों डिस्ट्रीब्यूट्री	0.14	0.64	0.06	0.20	—	—
22.	पेहलगांव गढ़े सब माईनर	0.10	0.05	—	0.16	—	0.10
23.	बुधवाना डिस्ट्रीब्यूट्री	0.34	0.83	0.12	0.72	—	0.73
24.	गोठड़ा डिस्ट्रीब्यूट्री	0.31	—	—	—	—	—
25.	खेरपुरा माईनर	0.07	0.10	—	0.04	—	—
26.	तोहीं ,,	0.12	0.13	0.06	—	—	—
27.	रामपुरा ,,	0.25	—	—	—	—	0.07
28.	वाडीवास सब ,,	—	0.4	0.04	—	—	—
29.	गुहाणा ,,	—	0.03	0.10	0.09	—	—
30.	पिछोपा ,,	—	.14	—	0.10	—	0.16
31.	नगला सब ,,	—	0.05	—	—	—	—
32.	खेड़ीसमवाल ,,	—	0.18	0.03	0.10	—	0.09
33.	पिछोपा कलां डिस्ट्रीब्यूट्री	—	0.19	—	0.20	—	—
34.	असवाड़ी सब माईनर	—	0.15	0.03	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
35.	खेड़ी बुरा माईनर	—	0.09	0.06	—	—	0.04
36.	पकड़ाना सब ,,	—	0.13	0.04	—	—	0.06
37.	गोठड़ा सब ,,	—	0.11	—	—	—	—
38.	दादरी सब ,,	—	0.03	—	—	—	0.63
39.	1 आर दादरी सब ,,	—	0.02	—	—	—	—
40.	कलाली सब ,,	—	—	0.18	—	—	—
41.	गोकल डिस्ट्रीब्यूट्री	—	—	0.15	0.62	—	0.23
42.	पम्प हाऊस नं0 3 लोहारू कैनाल	—	—	1.00	—	—	—
43.	पम्प हाऊस नं0 2 लोहारू कैनाल	—	—	1.20	—	—	—
44.	पम्प हाऊस नं0 1	—	—	—	1.02	—	—
45.	पम्प हाऊस नं0 4 लोहारू कैनाल	—	—	—	0.83	—	—
46.	लोहारू कैनाल	—	—	—	0.16	—	0.20
47.	दमकौरा डिस्ट्रीब्यूट्री	0.53	0.18	0.58	0.99	—	—
48.	झूपा डिस्ट्रीब्यूट्री	0.81	0.04	0.31	0.16	—	—
49.	बिछिना सब माईनर	0.19	0.19	—	—	—	—
50.	लाड़ा वास डिस्ट्रीब्यूट्री	0.89	0.48	—	—	—	—
51.	सोरा ,,	0.40	1.57	0.11	0.36	—	—
52.	सोरा माईनर	0.13	—	—	—	—	—
53.	मैंकीपुर ,,	0.66	0.79	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
54.	बहल माईनर	0.13	—	—	—	—	—
55.	डिगांवा सब ,,	0.07	—	0.06	—	—	0.29
56.	उन्न	0.06	—	—	—	—	—
57.	लौहारू डिस्ट्रीब्यूट्री	0.59	0.10	0.32	0.51	—	—
58.	गोबिन्द पुरा माईनर	0.13	—	0.06	—	—	—
59.	डगरौली डिस्ट्रीब्यूट्री	0.19	—	—	—	—	—
60.	बढ़धू चिना माईनर	0.08	—	—	—	—	—
61.	ककरौली ,,	0.13	0.16	—	—	—	—
62.	बाढ़ड़ा माईनर	—	0.37	—	—	—	—
63.	पम्प हाऊस नं0 6, लोहारू कैनाल	—	0.04	0.05	0.41	—	0.50
64.	जाझड़ा माईनर	—	0.06	—	—	—	—
65.	नथा ,,	—	0.09	—	—	—	—
66.	हसन पुर ,,	—	0.19	0.19	—	—	—
67.	सिधनियां ,,	—	0.07	0.09	—	—	—
68.	बुढ़ेरी ,,	—	0.08	—	—	—	—
69.	पम्प हाउस नं0 8, लोहारू कैनाल	—	0.01	0.09	—	—	—
70.	पम्प हाउस नं0 7, लोहारू कैनाल	—	0.06	0.07	—	—	—
71.	जैवाली माईनर	—	0.03	0.04	—	—	—
72.	खैड़ी टौका सब माईनर	—	0.06	0.12	—	—	—
73.	डबरका माईनर	—	0.08	0.04	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
74.	भौपाली माईनर	—	0.08	—	—	—	—
75.	व्हेर खौड ,,	—	0.15	—	—	—	—
76.	श्याममला ,,	—	0.05	—	—	—	—
77.	सिरसी सब ,,	—	0.05	—	—	0.05	0.05
	कुल योग =	10.59 लाख	9.97 लाख	6.35 लाख	8.86 लाख	2.45	37.40
कुल योग क + ख =		53.16	39.77	15.26	21.94	2.45	37.40

प्रो० छतर सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय मन्त्री जी ने अनेक्स्चर में जो फिगर्ज दी हैं, अलबत्ता ये सारी फिगर्ज ही मैनिपुलेटिड हैं । हैरानी की बात है कि दादरी फीडर पर 1-4-1993 से ले कर 28-2-1995 तक 15 हजार रुपये खर्च किए गए हैं । भाई आनन्द सिंह डांगी यहां पर हाउस में बैठे हुए हैं । उनका गांव दादरी फीडर के नजदीक पड़ता है । वे भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि नहर में 4 या साढ़े चार फुट तक मिट्टी है, जुई कैनाल में 20 हजार रुपये खर्च किए गए हैं । दादरी फीडर में 5000/-रुपये, लोहारू मेन कैनाल में 5000 रुपये खर्च किए गए दिखाए हैं । अध्यक्ष महोदय, मैंने इनके महकमे को बार-बार लिख कर दिया कि डी-सिल्टिंग करवाएं और उन्होंने लिख कर दिया है कि 1987 से लेकर 1994-95 तक उनकी डी-सिल्टिंग नहीं की गई है । चाहे वह लोहारू कैनाल है, सिवानी कैनाल है, दादरी फीडर है, दादरी डिस्ट्रीब्यूटरी है, बौन्द डिस्ट्रीब्यूटरी है, लोहारू कैनाल माईनर है, इसमें इतनी लम्बी चौड़ी लिस्ट मन्त्री जी ने दी है जिसमें से 5-10-20 हजार रुपये तक खर्च हुए दिखाए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि यह जो 5 से 10-20 हजार तक पैसा खर्च किया गया है, क्या यह वास्तव में खर्च किया गया है या केवल कागज काले किए गए हैं ? अध्यक्ष महोदय, सभी कैनालज की डी-सिल्टिंग नहीं की गई है । माईनर्ज और सब-माईनर्ज टूटी हुई हैं। माननीय बहन शान्ति देवी राठी जी ने माना है कि नहरों की डी-सिल्टिंग नहीं हुई है । लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है । बिजली मन्त्री लोगों को बिजली नहीं दे पा रहे हैं (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : चौहान साहब, आप सवाल पूछें ।

प्रो० छतर सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैं सवाल ही पूछ रहा हूं । मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि दादरी फीडर, लोहारू कैनाल, सिवानी कैनाल की सफाई कब तक करवा देंगे ? नम्बर दो, मैं मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि केवल भिवानी जिला ही नहीं, पूरे दक्षिणी हरियाणा में पानी नाम मात्र का जाता है । स्पीकर सर, पिछली बार भी मैंने आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री तथा मन्त्री महोदय का ध्यान इस बात की तरफ दिलाया था कि सिरसा और हिसार जिलों में नहरों में 24 से 26 दिन महीने में पानी चलता है जब कि भिवानी में महीने में 3 या साढ़े तीन दिन ही पानी चलता है । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछिये, भाषण मत दीजिए । आपका सवाल क्या है ?

प्रो० छतर सिंह चौहान : स्पीकर सर, मैं सवाल पर ही आ रहा हूं । जब नहरों से मिट्टी नहीं निकाली जाएगी तो फिर नहरों में कहां से पानी जाएगा ? पूरे हरियाणा में केवल दो ही जिले हैं जो पानी से डूबे हुए हैं । बाकी सारे प्रान्त में सारे जिलों में से कहीं पर भी पूरा पानी नहीं जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से यह आश्वासन चाहूंगा कि

वे क्या डी-सिल्टिंग का काम जल्दी करवाएंगे ? इसके साथ ही मैं इनसे यह भी पूछना चाहूंगा कि दादरी फीडर, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी और माईनर्ज, लोहारू कैनाल-माईनर्ज, डिस्ट्रीब्यूटरी की डी-सिल्टिंग कब तक करवा देंगे ? (विघ्न) इसके साथ ही इन्होंने रिप्लाई में दिया है 1-4-1994 से 31-4-94, 1-4-94 से 28-2-95 यह डेट में जो ओवर राईटिंग की है, उसका क्या कारण है ? जो आज तक डी-सिल्टिंग नहीं हुई है, उसका क्या कारण है तथा डी-सिल्टिंग के लिए वे क्या कोई प्रबन्ध करवाएंगे ?

चौधरी जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, डी-सिल्टिंग की जहां तक बात है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में डी-सिल्टिंग में दिक्कत है । यह बात हम मानते हैं । इसके साथ ही मैं इनको बताना चाहूंगा कि हर साल का यह प्रोसैस है । जैसे कि पहले भी इस बारे में असैम्बली में सवाल उठता रहा है और उसके जवाब में भी बताया गया है कि भाखड़ा में उतनी सिल्ट नहीं आती जितनी कि यमुना में आती है । यमुना में सिल्ट ज्यादा आती है, जिससे उसमें सिल्ट ज्यादा हो जाती है । यह सब अनैक्सचर में दिया हुआ है । साथ में उनके नाम भी दिए हैं । भिवानी डिस्ट्रिक्ट में 206 माईनर्ज हैं और उनके बारे में भी डिटेलवाईज दिया हुआ है । उसमें यह भी दिया है कि इतने-इतने पैसे वहां पर लगे हैं । अगर इनको कोई शिकायत है तो ये हमें बताएं कि फलानी जगह पर इतना पैसा नहीं लगा है । हम अधिकारियों की खिचाई करेंगे । इन्होंने भिवानी सर्कल की बात छोड़ दी और लोहारू सर्कल की बात कर रहे हैं । उस बारे में भी मैंने बताया है और उसका भी ब्यौरा दिया है । ये उमरावास माईनर, रूपगढ़ माईनर, बिजना माईनर, अटेला डिस्ट्रीब्यूटरी, मेहरा, नांगल, कूराल, दूधवा पेतावास, पोखरवास, कालूवाला, गोरीपुर, पोखर सब-माईनर्ज, कतिलाना डिस्ट्रीब्यूटरी और पेहलगांवगढ़ सबमाइनर इत्यादि हैं । मेरे कहने का मतलब यह है कि इन्होंने सवाल नहीं किया बल्कि लैक्चर दे दिया है । इतनी सारी माईनर्ज हैं और इन सब पर इकट्ठा काम नहीं हो सकता है, क्योंकि इतना पैसा नहीं है । इन्होंने लोहारू में जूई, सिवानी और दादरी फीडर के बारे में कहा । अगर हम इसमें शुरू से आखिर तक काम करें तो सात करोड़ से दस करोड़ तक पैसा लग जाएगा । अध्यक्ष महोदय, सैंकड़ों ही माईनर्ज हैं और इन बारे में मैंने डिटेलज "अनैक्सचर" में दे रखी है । इसमें 1-4-94 से लेकर 28-2-95 तक इतना पैसा कैसे खर्च किया ? इस बारे में इनको यह बताना चाहूंगा कि 1990-91 से 1994 की जुलाई तक ही नहीं बल्कि इसके बाद भी काम हुआ है । आगे जो फिगर्ज दी हुई हैं, वह उसके बाद की हैं ।

श्री सूरजमल : अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी बात से सन्तुष्ट नहीं हूं । मैं कमेटी के साथ बहादुरगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी, दुलहेड़ा डिस्ट्रीब्यूटरी और लूना माजरा डिस्ट्रीब्यूटरी देखने गया था । वहां पर कोई काम नहीं हुआ है । आप आधे घन्टे में ही ये तीनों डिस्ट्रीब्यूटरीज देख सकते हैं । अगर वहां पर डिसिल्टिंग हुई हो तो मैं कसूरवार हूं ।

चौधरी जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, मैंने मौके पर जाकर इनके साथ ही देखा था और इनको अब भी दिखा लेंगे और जहां-जहां पर इनको शिकायत होगी, वहां पर अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेंगे । अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बहादुरगढ़, दुलहेड़ा और लूना माजरा का नाम ले लिया । । वहां पर 76 हजार आर0 डी0 तक का काम हुआ है । अगर वह नहीं हुआ है तो ये बताएं और हम उसे मौके पर जाकर देख लेंगे । (विघ्न) हम वहां पर पानी भी पहुंचाएंगे । अध्यक्ष महोदय, यह जो मैंने अनैक्स्चर दिया है उसमें से अगर चौहान साहब, यह बताएं कि कहीं पर काम नहीं हुआ है, तो हम वहां पर भी काम ठीक करेंगे ।

श्री धर्मपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, इनके रिप्लाई में जैसा कि भिवानी वाटर सर्विसिज डिवीजन, भिवानी में 21 नम्बर पर भागवी माईनर, 33 नम्बर पर मिसरी माईनर, 17 नम्बर पर कुसम्भी सब-माईनर, गोठड़ा डिस्ट्रीब्यूटरी, तथा लोहारू जल सेवाएं परिमंडल, भिवानी में 56 नम्बर पर उग्न माईनर तथा पम्प हाउसिज नम्बर एक और दो हैं तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 1990-91 के बाद से इन माईनर्ज और डिस्ट्रीब्यूटरीज पर एक भी पैसा खर्च क्यों नहीं किया गया, इसका क्या कारण था, क्या इनमें सिल्ट नहीं है या फिर इन माईनर्ज में पानी नहीं जाता ? अगर इनमें 1990-91 के बाद से कोई भी पैसा खर्च हुआ है तो मंत्री जी हमें बता दें । यह सारी माईनर्ज और डिस्ट्रीब्यूटरीज मेरे हल्के की हैं । स्पीकर सर, मैं जानना चाहता हूं कि मेरे हल्के के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है, क्या मंत्री जी इस बारे में बताने की कृपा करेंगे ?

चौधरी जगदीश नेहरा : स्पीकर सर, 1990-91, 91-92, 92-93, 93-94 और 94-95 में जैसा मैंने अर्ज किया अलग-अलग पैसों का प्रावधान किया गया है । हमारे पास जितना पैसा है और जहां पर ज्यादा अरजैन्सी है, गाद है, रेत है तो पहले वहां पर हम प्राथमिकता देकर काम करवाते हैं । शायद कुछ नहरें 1992-93 में ठीक हुई हों और उसके बाद ठीक न हुई हों, तो यह हो सकता है यह बात मैं मानता हूं । रिप्लाई में अलग-अलग साल की फिगर्ज दे दी गयी हैं, लेकिन जिन नहरों में गाद ज्यादा है उनको हम ठीक करवाने की कोशिश करेंगे ।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, जहां तक डिसिल्टिंग आफ कैनाल्ज की बात है तो न केवल यह भिवानी जिले में जैसा छत्तर सिंह जी ने बताया बल्कि सारे प्रदेश के अंदर यह एक ऐसा सैंसटिव मुद्दा बन गया है । सारे प्रदेश के अन्दर चाहे हमारे ट्रेजरी बैंचिज के साथी हों और चाहे विपक्ष के सम्मानित साथी हों, में इस बात को लेकर एक बड़ा भारी असंतोष सा है । गवर्नर ऐड्रस पर और बजट पर भी बोलते हुए सभी ने इस बारे में कहा है । इसलिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या वे सदन को इस बारे में आश्वासन देंगे कि डिसिल्टिंग के बारे में क्यों न सारे प्रदेश में एक विशेष

कम्पेन चलाईं जाएं। जो रिक्वायर्ड मनी है उसको इमीडिएटली देकर क्यों न डिसिल्टिंग का काम शुरू करवाया जाए ? पानी की बहुत ही कमी है इसलिए जब तक चैनल साफ नहीं होंगे तब तक पानी किसानों के खेतों में कैसे जाएगा ? इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वे स्वयं अपनी देखरेख में सारे प्रदेश के अंदर डिसिल्टिंग के लिए एक विशेष कम्पेन चलाएं तथा इस काम के लिए पूरा पैसा भी दें तो क्या आने वाले रैनी सीजन से पहले-पहले नहरों में डिसिल्टिंग के लिए एक विशेष कम्पेन चलाई जाएगी ?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि सारा सदन इस बात को लेकर चिंतित है और सारे सदन का इस बारे में चिंतित होना स्वाभाविक भी है। जब किसानों के लिए पानी टेल तक नहीं पहुंचेगा तो किसान के लिए भी मुश्किल हो जाएगी और जो गांव टेल पर पड़ते हैं उनके लिए पीने के पानी की भी मुश्किल हो जाएगी। उन गांवों में पीने के पानी की दिक्कत कई दफा हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, जब यह हमारी सरकार बनी थी तो हमने सरकार बनते ही सबसे पहले यह फैसला लिया था कि वार फुटिंग पर सारे प्रदेश की नहरों और माईनर्ज की सिल्ट निकलवाएंगे यह आपको भी याद होगा।

श्री अध्यक्ष : आप यह भी बता दें कि नहरों में यह सिल्ट कब से और क्यों हो रही थी ?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, सदन में बहुत से माननीय सदस्यों ने यह कहा कि 95 परसैन्ट तक माईनरों और नहरों की टेल पर पानी पूरा पहुंच रहा है। इन लोगों ने तो प्रदेश का ऐसा सत्यानाश करके रखा था चाहे वह बिजली का मामला हो, चाहे पानी का मामला हो और चाहे सड़कों का मामला हो। सारी सड़कों की भी हमने मरम्मत वार फुटिंग तक करवायी। इन्होंने तो अपने राज में सड़क पर एक रोड़ी या बजरी भी नहीं डाली थी और न ही किसी माईनर या नहर की सफाई इन्होंने करवायी थी।

प्रो० सम्पत सिंह : 1990-91 में तो आपके समय से ज्यादा खर्चा इस बारे में हुआ है यह आपकी ही स्टेटमैंट है। सर, यह असत्य बोल रहे हैं (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, अब हमने पंचायतों के चुनाव करवाए हैं और हम पंचायतों को भी इसमें इन्वोल्व करेंगे, चुने हुए जो नुमाईंदे हैं उनको भी इन्वॉल्व करेंगे और बाकायदा हम सोचते हैं कि इनकी कमेटी बनाएं कि इस माइनर के लिए, इस नहर के लिए इतना पैसा सफाई के लिए दिया जा रहा है ताकि वे देखलें कि क्या वह पैसा ठीक खर्च हो रहा है या नहीं ? हमारी कोशिश होगी कि एक अप्रैल से ज्यादा पैसा नहरों की सफाई के लिए देकर प्रदेश की हर माइनर और नहर की सफाई करने की कोशिश करेंगे ताकि सभी जगह टेल पर पानी पहुंच सके।

Upgradation of Schools of Village Bhagal and Cheeka

*1116. **Sh. Amar Singh Dhanday** : Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the schools at village Bhagal and Cheeka to 10+2 system of district Kaithal ; and

(b) if so, the time by which the above said schools are likely to be upgraded ?

Education Minister (Shri Phool Chand Mulana) :

(a) No.

(b) Question does not arise.

श्री अमर सिंह ढांडे : स्पीकर सर, आपका शिक्षा के प्रति लगाव रहा है । आपने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सराहनीय काम भी किए हैं । स्पीकर सर, मेरे चीका-भागल गांव बहुत बड़े कस्बे हैं वहां म्युनिसिपल कमेटी भी है, सैकड़ों बच्चे 10 जमा 2 की शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं । 10 जमा 2 स्कूल के लिए शिक्षा विभाग ने जो शर्तें रखी हैं वह शर्तें भी हमारे दोनों गांव पूरी करते हैं । आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी की लोकप्रिय सरकार ने वहां 10 जमा 2 स्कूल मंजूर किया था लेकिन इस सरकार ने डिग्रेड कर दिए थे । क्या वहां 10 जमा 2 स्कूल बनाने के बारे में पुनर्विचार किया जाएगा ?

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, चीका में एक डी0 ए0 वी0 कालेज है और उस डी0 ए0 वी0 कालेज में 10 जमा 2 की क्लासिज भी हैं, इसलिए बच्चों को ज्यादा दिक्कत नहीं है, फिलहाल वहां किसी नये 10 जमा 2 स्कूल की आवश्यकता नहीं है ।

श्री अमर सिंह ढांडे : अध्यक्ष महोदय, डी0 ए0 वी0 कालेज में इतनी फीस लगती है कि ग्राम बच्चों का पढ़ना वहां मुश्किल है अगर वहां पर गवर्नमैंट स्कूल होगा तो गरीब बच्चे भी पढ़ सकेंगे । इसके अलावा डी0 ए0 वी0 में बच्चे भी ज्यादा हैं इसलिए बच्चों का पढ़ना मुश्किल होता है ।

Ethyl Easter

*1171. **Chaudhri Om Parkash Beri** : Will the Minister for Agriculture be pleased to state—

(a) the nominal value percentage of product the 2,4—D Ethyl Easter Content tested in the State Insecticides

Testing Laboratory during the years 1992, 1993, 1994 and 1995 respectively ; and

(b) the number of samples found misbranded/Sub-standard on the basis of tests of 2,4—D Ethyl Easter conducted during the period as referred above alongwith the actual values of misbranded samples ?

Agriculture Minister (Shri Harpal Singh,) :
(a) & (b) The information is placed on the table of the House.

Information

(a) The nominal value of 2,4—D Ethyl Ester was 34% (mass/mass) during the year 1992, 1993 and 1994. However, the contents of 2,4—D Ethyl Ester has been raised to 38% (mass/mass) from 29-9-1994. The formulation of 2,4—D Ethyl Ester 34% was also permitted by Government of India till 2-3-1995.

(b) The number of samples found misbranded/sub-standard on the basis of tests of 2,4—D Ethyl Easter during the year 1992 to 1995 alongwith the actual values of the misbranded samples are as follows :—

1992	1993	1994	1995
31.72%	30.84%	30.26%	21.55%
31.09%	31.04%	28.57%	22.23%
28.34%	30.06%	31.31%	29.13%
27.76%	21.97%	31.23%	28.8%
26.9%	30.06%	31.62%	20.15%
27.43%	30.90%		28.61%
30.82%	29.79%		28.33%
			(Against 38%)
27.29%	27.22%		
	29.79%		
	29.37%		
	20.96%		
	30.01%		
	31.03%		

[श्री हरपाल सिंह]

		30.9%		
		27.1%		
		30.40%		
		30.40%		
		31.32%		
Total :	8	18	5	7

चौधरी ओम प्रकाश बेरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने सवाल का जो जवाब दिया है वह तो ठीक है लेकिन मैं इनके नोटिस में लाना चाहता हूं और यह सारे स्टेट के इन्ट्रेस्ट की बात है। मैंने 1993 में यह बात कही थी कि इन्सैक्टीसाइड टैस्टिंग लैबोरेटरी जो करनाल में है, उसमें जो टैस्टिंग का काम करते हैं उनको टैक्नीकल आदमी करते हैं 15-15, 20-20 साल से करनाल में बैठे हुए हैं, वहां से आम तौर पर उनकी भ्रष्टाचार की शिकायत आती है। और अगर मैं यह कहूं कि टैस्टिंग लैबोरेटरी करनाल भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है तो इसमें कोई गलत बात न होगी। क्या हाउस में मंत्री महोदय इस बात का आश्वासन देंगे कि वहां से पुराने लोगों को तबदील करके नये लोगों को बिठाया जाएगा ?

श्री हरपाल सिंह : ऐसा है कि यह तो गवर्नमैंट की पालिसी है कि जहां शिकायत आती है, वहां ऐक्शन लिया जाता है और यहां मैं सदन को पूरा विश्वास दिलाता हूं कि उसकी हमें बड़ी चिंता है। हमने वहां का इन्चार्ज बदल दिया था। दूसरे की जब कंपलैंट आई तो उसको बदल दिया। हम कोशिश करते हैं कि ईमानदार आदमी को लगाएं, जिसकी रेपुटेशन अच्छी हो, वह लैब में लगाया जाए। जो आदमी वहां ठीक नहीं हैं, पुराने बैठे हुए हैं, उनको हम जरूर शिफ्ट कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल अब समाप्त होता है।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Supply of Sub-Standard Coal

*1128. **Shri Satbir Singh Kadian** ; Will the Minister for Power be pleased to state—

(a) whether the management of Thermal Power Plants have drawn the attention of the Government in regard to the

supply of sub-standard coal which leads to more discharge of waste ash than the standard during the years 1992-93, and 1993-94;

(b) if so, the percentage of waste ash discharged by the said power plants, per tonne standard coal ;

(c) the steps taken by the Government to ensure the supply of standard coal to the Thermal Power Plants; and

(d) the total area of land covered under this waste ash in various power plants in the State ?

बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) :

(क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) प्रति टन स्टैण्डर्ड कोयले के हिसाब से बनी बेकार राख निम्न प्रकार से है :–

फरीदाबाद थर्मल पावर स्टेशन	= 320 से 350 किलो ग्राम
पानीपत थर्मल पावर स्टेशन	= 390 से 420 किलो ग्राम

(ग) बेहतर किस्म के कोयले के मुद्दे के बारे में मामला समय–समय पर कोल इण्डिया लिमिटेड/भारत सरकार के साथ उठाया जाता रहा।

(घ) राख निपटान के लिए इन दो थर्मल स्टेशनों पर व्यवस्थित क्षेत्र निम्न प्रकार से है —

फरीदाबाद थर्मल पावर स्टेशन	= 225 एकड़
पानीपत थर्मल पावर स्टेशन	= 925 एकड़

Number of Students in J.B.T. and O.T.

*1145. **Shri Azmat Khan** : Will the Minister for Education be pleased to state the institutionwise number of students given admission in J.B.T. and O.T. courses during the year 1994-95 in the State ?

शिक्षा मन्त्री (श्री फूल चन्द मुलाना) : सूचना की तालिका सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

सूचना

संस्थावार डी0एड/ओ0 टी0 में प्रविष्ट छात्र/छात्राओं की संख्या का ब्यौरा

[श्री फूल चन्द मुलाना]
निम्नानुसार है —

(क) डी0 एड वर्ष 1994–95

क्रमांक	संस्था का नाम	प्रविष्ट अभ्यार्थियों की संख्या
1.	डाईट बीसवामील बढ़मलिक (सोनीपत)	47
2.	डाईट मदीना (रोहतक)	96
3.	डाईट डींग (सिरसा)	98
4.	डाईट मोहड़ा (अम्बाला)	99
5.	डाईट बिरही कलां (भिवानी)	98
6.	डाईट पलवल (कुरुक्षेत्र)	48
7.	डाईट मातनश्याम (हिसार)	100
8.	डाईट महेन्द्रगढ	97
9.	डाईट शाहपुर (करनाल)	49
10.	ईक्कस (जींद)	100
11.	डाईट गुड़गांव	51
12.	डाईट पाली (फरीदाबाद)	102
13.	राजकीय प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान लोहारू (भिवानी)	99
14.	राजकीय प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, आदमपुर (हिसार)	152
15.	राजकीय प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, मोरनी हिल्ज (अम्बाला)	99
16.	राजकीय प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, जीन्द	98
17.	राजकीय प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, राजपुर (सोनीपत)	144
18.	राजकीय प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, ओढ़ा (सिरसा)	100

19.	राजकीय प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, फिरोजपुर नमक (गुड़गांव)	136
20.	राजकीय प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, ऐलनाबाद (सिरसा)	100
21.	राजकीय प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, कोल (कैथल)	96
22.	राजदेवी मल्टीपरपज गर्लज कालेज, भैरिया (कुरुक्षेत्र)	39
23	राजीव गांधी मैमोरियल इन्स्टीच्यूट, पंचकुला (अ0)	40
	कुल योग	2088

(ख) ओ0 टी0 (हिन्दी)

क्र0	संस्था का नाम	प्रविष्ठ अभ्यार्थियों की संख्या
1.	डाईट गुड़गाँव	57
2.	डाईट पलवल (कुरुक्षेत्र)	56
3.	राजीव गांधी मेमोरियल इन्स्टीच्यूट, पंचकुला।	56
4.	सी0 आर0 एस0 जाट कालेज (हिसार)	56
	योग	225

ओ0टी0 संस्कृत

क्र0	संस्था का नाम	प्रविष्ठ अभ्यार्थियों की संख्या
1.	डाईट बीसवामील बढ़मलिक (सोनीपत)	70
2.	डाईट शाहपुर (करनाल)	58
	योग	128

Construction of a Tourism Complex at Pehowa

*1169. **Shri Jaswinder Singh** : Will the Minister of State for Tourism be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Tourism Complex in Pehowa; if so, the time by which it is likely to be constructed ?

राज्य पर्यटन मन्त्री (श्री लीला कृष्ण) : जी हां । पेहवा में एक यात्रिका बनाने का प्रस्ताव केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हुआ है । भूमि स्थानान्तरण के बाद इस परियोजना का निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा ।

Repair of School Building

*1175 **Shri Daryao Singh** : Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether it is a fact that some rooms of Higher Secondary School, Jhajjar is in damaged condition ; and

(b) if so, the time by which the aforesaid rooms are likely to be repaired ?

शिक्षा मन्त्री (श्री फूल चन्द मुलाना) :

(क) जी हां, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय झज्जर के कुछ कमरे क्षतिग्रस्त हैं और उन की विशेष मुरम्मत की आवश्यकता है ।

(ख) गत वर्ष 50,000/- रुपये की राशि स्वीकृति की गई थी । इस वर्ष 1,70,375/- रुपये की राशि विद्यालय भवन की मुरम्मत के लिये स्वीकृत की जा चुकी है । कार्य शीघ्र ही कर लिया जायेगा ।

Construction of Roads

*1184. **Shri Lehri Singh** ; Will the Minister for PWD (B & R) be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the following roads :—

(i) From Kheri-Dabdalan to Mehra (Kurukshetra) ;

(ii) From Dholra to Jandhera (Kurukshetra) ;

(iii) From Seeli Khurd to Ghalaur (Yamunanagar) ;

(iv) From Thaska Khadar to Fatehgarh (Yamunanagar) ;

(v) From Ghalaur to Magra (Yamunanagar) ;

(vi) From Gundyana to Jhinwar Majri (Yamunanagar) ;

(vii) From Gundyani to Mustafabad Railway Station (Yamunanagar) ;

(viii) From Mehmadpur to Thambar ; and

(ix) From Kabulpur to Golni (Yamunanagar) ; and

(b) if so, the time by which the aforesaid roads are likely to be constructed ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री अमर सिंह) :

(क) नहीं, श्रीमान् जी ।

(ख) उपरोक्त (क) के अनुसार प्रश्न ही नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Embezzlement cases in Haryana State Cooperative Housing Federation

252 **Shri Lehri Singh** : Will the Minister for Cooperation be pleased to state—

(a) whether any cases of embezzlement in the Haryana State Cooperative Housing Federation have been detected during the period from 1984 to 1987 ; and

(b) if so, the total amount involved in each case together with the names of officers/officials, if any, held responsible therefor ?

सहकारिता मंत्री (श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया) :

(क) वर्ष 1984 से 1987 के दौरान, हरियाणा राज्य सहकारी आवास प्रसंघ लि० में गबन का कोई मामला नहीं पकड़ा गया, लेकिन हरियाणा राज्य चौकसी ब्यूरो द्वारा की गई जांच के आधार पर हरियाणा राज्य सहकारी आवास प्रसंघ द्वारा वर्ष 1984 से वर्ष 1987 तक दिए गए रु० 162.38 लाख के ऋणों का दुरुपयोग हुआ कहा जाता है ।

(ख) चौकसी विभाग द्वारा पहले ही 8 चालान विभिन्न अदालतों में दायर किए जा चुके हैं व अन्य केसों में अभी भी जांच जारी है ।

Works Manager in Transport Department

253 **Shri Lehri Singh :** Will the Minister of State for Transport be pleased to state—

(a) the number of Works Manager working in the Transport Department at present ;

(b) the number of Works Manager out of those as referred to in part (a) above belonging to Scheduled Castes ; and

(c) whether there is any shortfall in the reserveration of Scheduled Castes in the aforesaid posts ; if so, the time by which it is likely to be wiped off ?

राज्य मंत्री (श्री बलबीर पाल शाह) :

(क) 20, श्रीमान जी ।

(ख) 2, श्रीमान जी ।

(ग) नहीं, श्रीमान जी । कार्य प्रबन्धक के पद श्रेणी II के होने के नाते इन पर पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं है । फिर भी अनुसूचित जातियों के लिए सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण है । हरियाणा परिवहन विभाग (ग्रुप ख) सेवा नियम, 1992 के अनुसार कार्य प्रबन्धक के 25 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं और 75 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

समस्त जिला फरीदाबाद में प्रदूषण सम्बन्धी

Mr. Speaker : Hon. Members, I have received a notice of Calling Attention Motion No. 5, given notice of by Shri Karan Singh Dalal, M.L.A. regarding pollution being at the extreme in whole of the district Faridabad. I admit it. He may read his notice and concerned Minister may make a statement, thereafter.

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान अत्यन्त लोक महत्व विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सारे जिला फरीदाबाद में प्रदूषण जोरों पर फैला हुआ है और सारे इलाके में महामारी फैलने का डर है । औद्योगिक प्रदूषण न केवल हवा में ही गन्दगी फैला रहा है परन्तु नहर का पानी भी पूरी तरह से गन्दा हो रहा है

अत: मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस वर्तमान समस्या के बारे में इस महान सदन में अपना वक्तव्य दें।

वक्तव्य–

उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी

पर्यावरण, वन तथा वन्य-प्राणी संरक्षण मन्त्री (श्री रामपाल सिंह कंवर) : फरीदाबाद हरियाणा का एक मुख्य औद्योगिक नगर है । राज्य में कुल 682 बड़ी और मध्यम औद्योगिक इकाईयों में से 188 इकाईयां फरीदाबाद जिला में लगी हुई हैं। इसके अतिरिक्त फरीदबाद में लगभग 16188 लघु स्तर की औद्योगिक इकाईयां भी हैं इनमें से लगभग 95 प्रतिशत लघु इकाईयां प्रदूषण रहित किस्म की हैं और इनके लिए किसी प्रकार के प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है । ये इकाईयां अधिकतर इंजीनयरिंग श्रेणी की हैं जो कि गंभीर किस्म का प्रदूषण नहीं फैलाती ।

उपरोक्त औद्योगिक इकाइयों में से 266 औद्योगिक इकाईयां ऐसी हैं जो जल को प्रदूषित करती हैं और इन्हें जल (नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1974 के अंतर्गत प्रदूषण जल को शुद्ध करने की आवश्यकता है । 197 औद्योगिक इकाईयों ने पहले ही अपने जल शोधक संयंत्र लगाए हुए हैं और ये अपना स्त्राव (effluents) हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित किए हुए मापदंडों के अनुसार साफ (treat) कर रही है । 16 औद्योगिक इकाईयों में जल शोधक संयंत्र लगाने का कार्य प्रगति पर है और 53 इकाईयों को 6 महीने के भीतर शोधक यंत्र लगाने के लिए नोटिस जारी किए हुए हैं जिनके नहीं लगाने पर उनके विरुद्ध जल प्रदूषण (नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1974 के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जाएगी ।

फरीदाबाद जिले में 366 इकाईयां वायु को प्रदूषित करने वाली श्रेणी में आती हैं । इनमें से 102 औद्योगिक इकाईयों ने पहले ही वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र लगाए हुए हैं तथा 86 इकाईयों में इन संयंत्रों के लगाने का कार्य प्रगति पर है। 178 औद्योगिक इकाईयों ने अभी तक वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र नहीं लगाए हैं, तथा बोर्ड ने इन इकाईयों को वायु प्रदूषण (नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981 के अधीन ऐसे संयंत्र लगाने के लिए नोटिस जारी किए हुए हैं।

जहां तक फरीदाबाद में वायु प्रदूषण का सम्बन्ध है, वहां पर स्थित बड़ी-बड़ी प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाईयों में से एक है थर्मल पावर प्लांट । हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सतर्क प्रयत्नों में से थर्मल प्लांट के अधिकारियों ने अपनी इकाईयों के 6 पाथों में से अब 5 पाथों में वायु प्रदूषण रोकथाम संयंत्र लगा दिए है तथा छठे पाथ (Paths) में वायु प्रदूषण रोकथाम संयंत्र लगाने का कार्य प्रगति पर हैं ।

जिला फरीदाबाद में से गुजरने वाली दो नहरों (गुड़गांव नहर तथा आगरा नहर) का पानी फरीदाबाद जिले में लगी औद्योगिक इकाईयों के स्त्राव (effluents) से प्रदूषित नहीं होता । संघ राज्य दिल्ली से बहने वाली प्रदूषित स्त्राव (effluents)

[श्री रामपाल सिंह कंवर]

इन दो नहरों के पानी में प्रदूषण का मुख्य कारण है फरीदाबाद में से गुजरने वाली गुड़गांव नहर। वास्तव में आगरा नहर की ही डिस्ट्रीब्यूटरी है, जो कि बदरपुर थर्मल पावर प्लांट के डाउन स्ट्रीम हरियाणा के कुछ भागों में सिंचाई करती है। आगरा नहर के पानी का मुख्य स्रोत (source) यमुना नदी है जिसका पानी देहली की 60,000 से भी अधिक औद्योगिक इकाईयों के बिना साफ किए हुए औद्योगिक स्राव (effluents) तथा संघ राज्य दिल्ली में स्थित 19 मुख्य नालों से बिना साफ किया हुआ व्यवसायिक स्राव के छोड़े जाने पर बहुत ही प्रदूषित हो जाता है। आगरा नहर अपने बहाव के दौरान प्रदूषित जल को गुड़गांव फीडर नहर जो कि इसकी शाखा है, में डालने से पहले संघ राज्य दिल्ली के ओखला व्यवहारिक शोधक प्लांट और बदरपुर थर्मल प्लांट में से काफी मात्रा में दूषित जल ग्रहण करती है। इस प्रकार फरीदाबाद–दिल्ली बार्डर के पास आगरा नहर से शुरु में ही गुड़गांव नहर में छोड़ा गया पानी अत्यंत ही प्रदूषित होता है जिसका बी0ओ0डी0 (B.O.D.) निर्धारित मापदंडों से अधिक है और इसका कारण ओखला व्यवसायिक यंत्र बदरपुर पावर प्लांट की स्राव से तथा दिल्ली में 19 नालों से बिना साफ किए हुए मलमूत्र (sewage) निकास से एवं 60,000 से भी अधिक देहली की औद्योगिक ईकाईयों के व्यवसायिक स्राव (effluents) से प्रदूषित होता है न कि फरीदाबाद जिले में लगी हुई औद्योगिक ईकाईयों से।

इस बोर्ड द्वारा नहर के शुरु से लेकर सोहना तक गुड़गांव नहर के पानी की गुणवत्ता को 6 निर्धारित स्थानों पर मापा जा रहा है। बोर्ड पहले से ही इस मामले को देहली प्रशासन के अधिकारियों (Delhi Administration Authorities) के ध्यान ला चुका है कि वह अपना मल निकास (sewage) तथा औद्योगिक इकाईयों का गन्दा पानी (waste water) यमुना नदी में डालने से पहले साफ करें ताकि गुड़गांव नहर का पानी प्रदूषित रहित गुणवत्ता (quality) का हो, इसके इलावा फरीदाबाद जिले में स्थित औद्योगिक ईकाईयों द्वारा फैलाए जाने वाले प्रदूषण को कम करने में बोर्ड लगातार अपनी पूर्ण कोशिश कर रहा है।

स्वास्थ्य विभाग ने भी कहा है कि प्रदूषण के कारण फरीदाबाद में कोई महामारी फैलने का आन्देशा नहीं है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने बड़ी सफाई से हमारी इस समस्या के बारे में सदन के सामने अपने विचार रखें। ये स्वयं मानते है कि फरीदाबार देश का दसवां इंडस्ट्रियल टाउन है। अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद में कभी आपको जाने का जरूर मौका मिला होगा जब आप दिल्ली से जाते हुए फरीदाबाद में दाखिल होते है तो वहां इतना जबरदस्त धुआं होता है कि आखों में पानी आने लगता है। इसके अलावा जितने भी वहां उद्योग हैं, वे बहुत प्रदूषण फैलाते हैं। मन्त्री जी ने केवल थर्मल प्लांट के बारे में कह दिया कि इन्होंने वहां पर यन्त्र लगा दिया है। यह

बात इनकी दुरुस्त है कि थर्मल से जो प्रदूषण होता था वह रुकेगा और उसमें कमी भी आई है । लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस पोल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड की ये बात कर रहे हैं वह बोर्ड ईकाइयों का प्रदूषण रोकने की बजाए उनसे चन्दा और पैसा इकट्ठा करने की बात करता है । जिस किसी इकाई के बारे में हम ग्रीवैंसिज कमेटी में या और माध्यम से बात उठाते हैं कि यह प्रदूषण फैलाती है तो समझो उन लोगों की लाटरी लग जाती है ये उनके पास जाएंगे और पैसे ले लेंगें । ये प्रदूषण को रोकने की कोई बात नहीं करते । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि फरीदाबाद जिले में आपने पिछले दो साल में कितने उद्योगपतियों के खिलाफ मुकद्दमें दर्ज करवाए हैं और कितने उद्योगपतियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की है । इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, पलवल में जी0टी0 रोड पर आलापुर में एक कारखाना लगा हुआ है, उस कारखाने से बहुत ज्यादा बदबू आने के कारण आस पास के 4-5 गांवों के लोग बहुत परेशान हैं । वहां पर मच्छर बहुत ज्यादा पैदा होते हैं । इसके अलावा बल्लभगढ़ में एक स्टायर वाथर फैक्टरी है । उस फैक्टरी के बारे में वहां के जो दूसरे एम0 एल0एज है, उनको पता है कि उस फैक्टरी से बहुत ज्यादा मात्रा में काला धूआं निकलता है । वह इतना ज्यादा होता है जिसका कोई हिसाब नहीं है । इसके अलावा हथीन में एक शराब की फैक्टरी है, उससे भी बहुत ज्यादा बदबू आती है ।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब आप सवाल पूछें ।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, मैं सवाल ही पूछ रहा हूं । माननीय मन्त्री जी मेरे सवालों को नोट करते जाएं और उनका ये जवाब दे दें । अध्यक्ष महोदय, हथीन में जो शराब की फैक्टरी है .....

श्री अध्यक्ष : इस बात का इस प्रस्ताव से कोई ताल्लुक नहीं है, आप पोलयशन के बारे में बात करें ।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, जो हथीन में शराब बनाने का कारखाना है उसमें बहुत ज्यादा बदबू आती है और उसके आस-पास के 15-20 गांवों के लोग परेशान हैं क्या सरकार उस बदबू का कोई न कोई प्रबन्ध करने के बारे में कार्यवाही करेगी ? इसके अलावा, पलवल में जो शूगर मिल लगा हुआ है, उससे बहुत ज्यादा प्रदूषण निकलता है । उस शूगर मिल में बहुत ज्यादा मुनाफा भी है । मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से और खास करके मुख्य मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या उस शूगर मिल की कमाई से ही उसके प्रदूषण को रोकने के लिए कोई संयंत्र लगाने की व्यवस्था करेंगे और उसके आस पड़ौस के जो गांव है, क्या उनमें कीटनाशक दवाई का छिड़काव करने का कोई प्रबन्ध करेंगे ?

श्री राम पाल सिंह कंवर : स्पीकर साहब, वैसे तो आपने यह फैसला किया हुआ है कि एक कालिंग अटैंशन मोशन के जवाब पर दो ही सवाल पूछे जा सकते है । लेकिन दलाल साहब ने एक ही सांस में बल्लभगढ़ की सारी फैक्टरीज गिनवा दी हैं ।

[श्री राम पाल सिंह कंवर]

इन्होंने वहां की कोई फैक्टरी नहीं छोड़ी। जैसे इन्होंने कहा कि वहां पर बहुत ज्यादा प्रदूषण है, मैंने उस प्रदूषण के बारे में अपने मैडीकल औफिसर से रिपोर्ट ली है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि वहां पर जो प्रदूषण है, उससे न कोई एपिडैमिक बीमारी फैली है और न ही आगे फैलने का कोई अंदेशा है। जिन कारखानों के मालिकों ने प्रदूषण को रोकने के लिए संयंत्र नहीं लगाए, उनको हमने नोटिस दिए हैं और नोटिस के जवाब न आने पर हमने हरियाणा प्रदेश के लगभग 406 कारखानों के मालिकों के खिलाफ कार्यवाही की है। हमने 181 कारखानों के मालिकों के खिलाफ वाटर एक्ट के तहत और 225 के खिलाफ एयर एक्ट के तहत भिन्न भिन्न कोर्टस में केस दायर किए हुए हैं और वे केस कोर्टस में लम्बित पड़े हैं। इसके अलावा, माननीय सदस्य ने स्टायर वायर फैक्टरी के बारे में कहा है। उसके बारे में मैं उनको बता देना चाहता हूं और माननीय सदस्य ने यह माना भी है कि वहां पर थर्मल प्लांट में प्रदूषण रोकने के लिए संयंत्र लगाने के पश्चात उसका प्रदूषण कम हो गया है और वहां पर एक संयंत्र और लगाने जा रहे हैं। इसी तरह से इन्होंने शूगर मिल पलवल का जिक्र किया। पलवल में संयंत्र लगाया हुआ है। जिसके अन्दर एयर पोल्यूशन की पी0 ओ0 डी0 मात्रा 1000 मिलीग्राम की है, जिसमें थोड़ा मार्जनल 120 पी0 ओ0 डी0 है जबकि 100 मिलीग्राम होनी चाहिए। इस तरह से वहां एयर पोल्यूशन 598.8 मिलीग्राम है जबकि लिमिट 500 ग्राम की है। यह कुछ ज्यादा है, इनको कहा गया है कि इसको मोडीफाई कीजिए और ट्रीटमैंट प्लांट में भी मोडीफाई कीजिए। इन्होंने कहा है कि वे जल्दी ही इसका प्रबंध कर रहे हैं। इसी प्रकार से यहां पर हथीन डिस्टीलिरी का जिक्र आया। कहा गया कि वहां पर लगुनिंग सिस्टम था जो बाद में हटाया गया। मैं बताना चाहूंगा कि जो लगुनिंग सिस्टम लगाया हुआ था, वह अब भी लगा हुआ है। अब सैन्ट्रल पोल्यूशन बोर्ड ने फैसला किया है कि यह सिस्टम जो बायो मैथानीज का है उसकी पूरी रिकवरी नहीं होती है, इस लिए इसकी बजाये उनसे कहा है कि बायोमैथानीज सिस्टम अडौप्ट कीजिए और इस सिस्टम पर 90 लाख रुपये खर्च भी कर दिये गये हैं। मैं बताना चाहूंगा कि जो पहला सिस्टम है उसका खर्चा भी नकारा नहीं जायेगा। अब प्राईमरी ट्रीटमैंट भी लेटैस्ट मैथड से होगा और जो पहला सिस्टम लगुनिंग का है, वह भी चलता रहेगा। इस तरह पूरा सिस्टम लागू करने से पर्यावरण में जो थोड़ा बहुत गंद जाता था, वह भी खत्म हो जाएगा। इसी तरह से यह जो इन्होंने अशोका डिस्टिलरी के बारे में पूछा था इसका यही जवाब है। एक सवाल इन्होंने यह पूछा है कि बुकरम की जो एक फैक्टरी है, उसका ए0 पी0 सी0 एम0 अभी तक भी नहीं लगाया है लेकिन फिर भी हमने इसको चैक किया और जो देखा है, उससे यही पता चलता है कि उससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन नहीं है लेकिन फिर भी हमने फैक्टरी के मालिक को कहा है कि आप ए0 पी0 सी0 एम0 पोल्यूशन सिस्टम लगाएं ताकि जो थोड़ी बहुत शिकायत है ऐयर में, वह भी खत्म की जा सके। एफ्यूलेंट जो है, उसके लिए इन्होंने पहले ही एक ट्रीटमैंट प्लांट लगाया हुआ है। इसके रिजल्ट जो टैस्ट के बाद सामने आए

हैं, वे विद इन लिमिटस हैं। तो मैं समझता हूं कि दलाल साहब ने जिन फैक्टरियों के बारे में पूछा है, उन सब सवालों की संतुष्टि इनकी मेरे इन उत्तरों से हो गई होगी। वैसे भी हमारी सरकार अपनी तरफ से भरसक कोशिश कर रही है कि कैसे प्रदूषण को रोका जा सके।

श्री अजमत खां : अध्यक्ष महोदय, अब जिन प्वायंटों का जिक्र आया, वे मेरे हल्के से संबंधित हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से एक अर्ज करना चाहता हूं कि ये खुद और अपने अधिकारियों के साथ वहां पर 24 घंटे बिता आएं, या 12 घन्टे बिता आएं फिर बता दें कि वहां का वातावरण कैसे है। वहां पर उस अशोका डिस्टीलिरी की वजह से हालत बहुत खराब है। जी0 टी0 रोड पर बहुत बदबू है। इस फैक्टरी ने 15-20 गांवों का जीवन नरक बना रखा है। मवेशियों में बीमारियां फैलती हैं। गुड़गांव कैनाल का जो पानी मछली फार्म के लिए जाता है, उसमें मछलियों का जितना भी बीज होता है, वह सारा का सारा खत्म हो जाता है। लोग दूसरे पानी में बीज तैयार करके लाते हैं, तब जाकर वह बीज बचता है। ये एक रात बिता आयें, फिर रिपोर्ट करें, हमारी तो अब आदत सी पड़ गई है क्योंकि हमें तो वहीं रहना होता है।

श्री रामपाल सिंह कंवर : अध्यक्ष महोदय, सैन्ट्रल पोल्यूशन बोर्ड की तरफ से जो नई इन्स्ट्रक्शन्ज आई हैं, उनके मुताबिक ट्रीटमैंट प्लांट लगेगा। इसके मुताबिक बोर्ड की तरफ से उनको इन्स्ट्रक्शन्ज दी जा चुकी है कि न्यू सिस्टम आफ पोल्यूशन कण्ट्रोल बोर्ड के मुताबिक ट्रीटमैंट प्लांट लगाएं। यह आदेश दे दिया गया है और वह प्लांट अण्डर प्रोसैस है जिस पर वे आलरेडी 90 लाख रुपये खर्च कर चुके हैं। यह प्लांट कम्पलीट हो जाने के बाद कोई कमी नहीं रहेगी और पोल्यूशन की समस्या खत्म हो जाएगी। जहां पुराना ट्रीटमैंट प्लांट नहीं लगा हुआ है, वहां प्लांट लगाएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो सैकण्ड ट्रीटमैंट करेंगे ताकि पोल्यूशन को रोका जा सके। अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय साथी ने कहा है कि एक रात वहां पर रह कर देखें। मैं जाकर उनके पास ठहरूंगा अगर वे मुझे इन्वाईट करें तो मैं रात भी उनके पास ठहरूंगा। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कर्ण सिंह जी, आपका सवाल हो गया है, अब आप बैठें। Hon. Members, now the general Discussion on the Budget for the year 1995-96 will be resumed.

वाक आउट

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आप मेरी बात सुनें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अभी मुझे एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछना है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कर्ण सिंह जी, आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न) राम विलास जी, आप शुरू कीजिए।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

श्री अध्यक्ष : आपने सवाल पूछ लिया है इसलिए अब आप बैठें। मेरी इजाजत के बिना अगर आप बोलेंगे तो रिकार्ड नहीं होगा, इसलिए आप बैठिए।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, आप कम से कम मेरी बात सुन लें। * * * * *

श्री अध्यक्ष : जो ये बोल रहे हैं उसको रिकार्ड न किया जाए। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, अगर मुझे अपनी बात कहने की इजाजत ही नहीं है तो मैं इसके विरोध में सदन से वाक आउट करता हूं।

(इस समय विरोधी पक्ष के सदस्य श्री कर्ण सिंह दलाल हाउस से वाक आउट कर गए)

वर्ष 1995–96 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

प्रो० राम विलास शर्मा (महेन्द्रगढ़) : अध्यक्ष महोदय, श्री मांगे राम गुप्ता जी ने 13 मार्च को इस महान सदन में हरियाणा सरकार का जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं उस पर अपने विचार प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। स्पीकर सर, इनकी पूरी स्पीच सुनने के बाद और पूरे बजट को बार–बार पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि यह बजट नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस महान सदन में जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह सारहीन बजट है। **(इस समय सभापतियों की सूचि में से एक सदस्या श्रीमती चन्द्रावती पधासीन हुई)** आदरणीय चेयरमैन साहिबा, आप जैसी वरिष्ठ सदस्या को आज हाउस की कार्यवाही को प्रिजाईड ओवर करने का जो अवसर मिला है, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। (विघ्न) चेयरमैन साहिबा, मैं यह कह रहा था कि जो बजट होता है, वह सरकार का संकल्प होता है, सरकार की प्राथमिकताओं का कार्यक्रम होता है, लेकिन यह जो बजट है यह बजट नहीं है, इसमें कोई दिशा नहीं है, इसमें कोई संकल्प नहीं है, इसमें कोई प्राथमिकता नहीं है, इस में किसी को राहत नहीं दी गई। ऐसा लगता है कि सरकार किसी को राहत देना ही नहीं चाहती। चेयरमैन साहिबा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक के समुद्र से जो लहर उठी उसके भय से डर कर हमारे साथी ने घबराकर अपना बाट छोड़ दिया है और कर-मुक्त बजट यहां प्रस्तुत कर दिया।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

इन्होंने, सिन्दूर, चूड़ियां और मंगलसूत्र पर टैक्स माफ कर दिया। चेयरमैन महोदय, इन्होंने अपने चार साल के राज में पुरुषों के लिए जो कुछ भी किया उससे इनको विश्वास हो गया है कि पुरुषों से इनका कुछ नहीं बनेगा, पुरुषों के ऊपर इनका विश्वास ही नहीं रहा है ; इसलिए ये अब महिलाओं को खुश करने की बात कर रहे हैं (विघ्न) बहनों का जितना आदर हम करते हैं उतना कोई नहीं करता होगा। "यत्र नरीय पूजयन्ते, तत्र रमयते देवता" हम इसी संस्कृति के उपासक हैं और हमें इस बात की खुशी है। चेयरमैन महोदया, आज ये भोली भाली महिलाओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। आज इनको चार साल बाद बहनों की याद आई है। चेयरमैन महोदया, अटेली में एक बार चुनाव हुआ था। उन दिनों वहां पर बाबा खेतानाथ जी नाम के एक संत हुआ करते थे कांग्रेस के लोगों ने उनको जबरदस्ती टिकट दे दी जबकि वे चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। यहां पर राव बसी सिंह जी बैठे हैं, ये भी उन लोगों में शामिल थे। वे बाबा जहां-जहां पर भी जाते थे तो बहनें उनके पैर पड़तीं थी, टीका लगाती थी और श्रद्धा में एक-दो रुपए भी देती थी और बदले में बाबा उन्हें प्रसाद भी दिया करते और कहते थे कि जीजी/बाई मैं चुनाव में खड़ा हुआ हूं। बहनों ने कहा कि बाबा जी, हम तो आपकी ही पूजा करते हैं, पर जीजी क्या करें यह जीजा ही नही मानते हैं। तो हमारी बहनें भाईयों के पीछे हैं। चेयरमैन महोदया, बहनें तभी मांग में सिन्दूर लगाती हैं जब खेतों में फसल खड़ी हो, जब उसके पति की जेब में पैसा हो और जब उसके बेटे को रोजगार मिला हो। जब घर में अनबन हो, असुविधा हो और दुख हो तो बहनों के लिए सिन्दूर के कोई मायने नहीं होते हैं। इस सरकार ने बहनों को धोखे में रखने और आंसू पोंछने वाली बात की है।

सभापति महोदया, चौधरी भजन लाल जी का सबसे बड़ा संकल्प तो एस0 वाई0एल0 का था। चार साल से तो हम पूछ रहें हैं। अब मुख्यमंत्री जी कह देगें कि यह बात गवर्नर एड्रैस में भी आ गई है। चेयरमैन महोदया, इनके राज में लोग बात नहीं कह सकते हैं। हर आदमी इनके उस भाषण को याद करता है जिसमें इन्होंने कहा है कि हम इसको 90 दिन में पूरा कर देगें। उस वायदे का क्या हुआ ? एस0वाई0एल0 जो हरियाणा के लिए जीवन-मरण है उस बारे में इस बजट में कुछ भी नहीं है। चेयरमैन महोदया, 1 नवम्बर 1966 से हरियाणा बना है, तब से लेकर जितनी भी सरकारें चाहे चौधरी देवी लाल की, चौधरी बंसी लाल की और मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल की थी, इस पर कुछ काम नहीं हुआ है। तब से लेकर आज तक इस मुद्दे पर आन्दोलन हो चुके हैं और हर सरकार ने अपने गवर्नर एड्रैस में बजट अभिभाषण में और चुनाव के मैनीफैस्टो में एस0 वाई0 एल0 के बारे में वायदे ही किए हैं और इस सरकार ने भी एक नया पैसा इस बजट में नही रखा है। इसको कितने हल्के शब्दों में टाल दिया है, वह इस बजट के पेज नंबर 8 पर है कि :—

[प्रो० राम विलास शर्मा]

"हम केन्द्रीय सरकार और पंजाब सरकार से सतलुज-यमुना लिंक नहर के पंजाब क्षेत्र में आने वाले भाग को शीघ्र पूरा करने के लिए लगातार अनुरोध कर रहे हैं।"

हम चार साल से इनसे पूछ रहे हैं और दो बार तो हम सबने सदन के नेता से प्रार्थना कर ली कि एक ऐसा प्रस्ताव पास करो लेकिन यह कहने लगे कि कुछ बातें ऐसी हैं जो कि बेअन्त सिंह और प्राईम मिनिस्टर जी के बीच में चल रही हैं। हमने इनकी बात पर विश्वास किया। आज लगातार चार साल हो गए हैं, न तो ये प्रस्ताव पास करने के लिए तैयार हैं और न ही प्राईम मिनिस्टर के पास जाने के लिए तैयार हैं। They are conceiving time and again but they are delivering nothing for the last 4 years. चार साल में एस० वाई० एल० के ऊपर कोई बताने लायक बात नहीं है कि यह 2-4 कदम आगे बढ़े हों या पीछे हटे हों। इस मामले में हरियाणा की जनता के साथ बड़ा भारी विश्वासघात हुआ है।

[11.00 बजे] कांग्रेस ने अपने मैनीफैस्टो में जो बहुत बड़ा वायदा किया था, आज उसको इन्होंने डाईलूट कर दिया।

इसके अलावा, इन्होंने बजट में कृषि के बारे में भी बताया। चेयरमैन साहिबा, हरियाणा की जनता पर राम मेहरबान हो जाता है इसलिए बारिश हो जाती है और फसलें हो जाती हैं। लेकिन हरियाणा का जो इकोनोमिक सर्वे है जिसको इन्होंने माना है कि जो फसलें हैं वह रिकार्ड तोड़ हुई हैं। केन्द्रीय पूल में इन्होंने मैक्सिमम 22 लाख टन चावल दिया है। चेयरमैन साहिबा, चावल की पैदावार किसान ने की है, गेहूं का उत्पादन किसान ने बढ़ाया है लेकिन उस किसान को प्रोत्साहन क्या मिला, तोहफा क्या मिला, इन्होंने किसान को तोहफा यह दिया कि जो करनाल में एक बीज की बहुत बड़ी कम्पनी है, जो जूते भी बनाती है और नकली बीज भी किसानों को देती है, जिसके बारे में इस सदन में 9 महीने से बार-बार मुद्दा उठ रहा है और सरकार ने उसकी इंक्वायरी भी करायी है। हजारों किसानों का नुकसान सरकार ने माना है परन्तु फिर भी सरकार के कुछ लोग, जब कभी कोई सरकारी काम होता है तो उसी बीज-कम्पनी के यहां होता है और वे वहीं पर चाय पीने के लिए जाते हैं। चेयरमैन साहिबा, किसान जब देखता है कि जिस आदमी ने उसको पीड़ा पहुंचाई है, नकली बीज दिया है, उसी के यहां इस सरकार के लोग जाते है और चाय पीते हैं तो यह गलत मैसेज कन्वे करते हैं। सर, किसान बड़े लोगों से नहीं लड़ सकता परन्तु इस तरह से किसान को पीड़ा जरूर पहुंचती है, पीड़ा इकट्ठी होती रहती है। सर, जिस किसान ने हरियाणा में इतना अनाज पैदा करके केन्द्रीय भण्डार में दिया हो तो उस किसान को खाद का क्या भाव मिलता है? इस सदन में इस बारे में कई बार चर्चा चली परन्तु नेहरा साहब कोई जवाब ही नहीं दे पा

रहे हैं। जब किसान को महंगी खाद मिलेगी, बीज नकली मिलेगा तो वह कैसे इतना अनाज पैदा कर पाएगा। इन्होंने, जो खाद पर सबसिडी मिलती थी उसको भी खत्म कर दिया। पंजाब की सरकार ने किसानों को प्रोत्साहन के रूप में बोनस दिया है। पंजाब और हरियाणा के किसानों की हालत में कोई अन्तर नहीं है इसलिए हमारी सरकार को भी किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य देना चाहिए। दोनों स्टेट के किसानों की मेहनत में कोई अन्तर नहीं है, पसीने में अंतर नहीं है लेकिन सरकार ने किसानों को क्या दिया। सरकार ने सन-फलावर के बारे में बात की है। ये जितनी भी बातें लेकर हरियाणा में आते हैं, किसान उसी बात को लेकर अपनी मेहनत से उस कार्य में जुट जाता है। सूरजमुखी के लिए भी किसान ने मेहनत करके इसका उत्पादन हरियाणा में बढ़ाया। उसने इसका बीज नहरों के साथ-साथ तथा अन्य जगहों पर भी दिया लेकिन उसके साथ क्या ज्यादती हुई, इसके बारे में मैं आपको 17 सितम्बर, 1994 का ट्रिब्यून अखबार पढ़कर सुना देता हूं जिसका हैडिंग है "Bungling Hits Sunflower Output." सर, यह सारी न्यूज आईटम तो बहुत लम्बी है इसलिए मैं इसका रैलवेन्ट पोरशन ही पढ़ देता हूं। यह जो खाद पैदा करने वाली कम्पनी है, ऐसा लगता है कि इसको सरकार नहीं चला रही है बल्कि इसका प्राइवेटाईजेशन इन्होंने कर दिया है। इस अखबार में एच0 एस0 आई0 डी0 सी0 के बारे में लिखा है—

> "It has been found that the seed was of low quality. It is believed that over 800 quintals of this seed is still lying with the HSIDC. The agency is trying to sell it to the farmers in the coming rabi crop."

इसमें एक हजार क्विंटल बीज बेकार पाया गया, सब-स्टैण्डर्ड पाया गया। सर, यह 1994 की बात है, परन्तु इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई है। किसानों ने अपनी मेहनत करके, अपने पसीने से फसलें पैदा करके केन्द्रीय भंडार को भर दिया लेकिन सरकार ने उसको अपनी करामात मान लिया जोकि ठीक बात नहीं है।

इसी तरह से ला एण्ड आर्डर की बात है कुछ बातें बहुत पुरानी हैं, उनको दोहराने से कोई फायदा नहीं है। आज भी मुख्यमंत्री जी ने सदन में बताया है कि हत्या के 84 मामले ऐसे हैं जिनके ऊपर गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है। चेयरमैन साहिबा, लोग इससे सन्तुष्ट नहीं हैं कि गवाह नहीं मिला या क्या नहीं हुआ। लोग अपने आसपास जब लोगों का अपहरण होते हुए देखते हैं, हत्या होते देखते हैं तो परेशान होते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो इस सरकार के साथ जुड़ी हुई है जींद जिले में सफीदों में बिट्टू सन आफ श्री पाले राम बूढ़ा खेड़ा गांव से, साढ़े चार साल का एक बच्चा 27-4-94 से लापता है, उसका कोई अता-पता नहीं है। जींद से मेरा नाम राशि राम विलास, सुपुत्र श्री बाल कृष्ण निवासी नगरपालिका जींद, 7 दिसम्बर, 1993 से लापता है। कितनी बार लोग मुख्यमन्त्री जी से मिल लिए और मुख्यमन्त्री जी को लिखकर दिया। मुख्यमन्त्री जी का अपना आदेश है,

[प्रो० राम विलास शर्मा]

कितना स्पष्ट है। 14-11-94 को जींद में लोगों ने इनसे भेंट की। इसके ऊपर इनके सीनियर सैक्रेटरी के आर्डर हैं--

"Presented to C.M. He has desired that S. P. Jind may look into this matter personally and every possible steps be taken for tracing the boy. And also stern action be taken against the culprits."

अपहरण, हत्या और छोटा सा हरियाणा व इतना बड़ा पुलिस का बन्दोबस्त है। अब मैं अगर भूत मांजरा की बात करूंगा तो कहेंगे कि इनको भूतमांजरा का भूत सवार हो गया है। हरिजन बाला संतोष की बात करूंगा तो ये कहेंगे। चेयरमैन साहिबा, कोई जिला ऐसा नहीं है जिसमें इस तरह की बात नहीं हुई। 24 फरवरी के दैनिक ट्रिब्यून में ऐडीटोरियल छपा था। उसमें सुप्रीमकोर्ट ने हरियाणा के हिसार जिले की पुलिस के बारे में कहा था कि वहां की पुलिस दो आदमियों को गिरफ्तार करके अदालत में जाने से तो रोक सकती है लेकिन कलप्रिट को नहीं पकड़ सकती। (विघ्न) एक दुदवा गांव है। चेयरमैन साहिबा आप लोहारू से हैं आप एक-एक गाँव से वाकिफ हैं दुदवा से ढाई साल से एक लड़का अशोक, उसकी जीप का कंडक्टर लापता है। क्राइम ब्रांच और पुलिस के अफसरों से मिलने के लिए लड़के के मां-बाप और पत्नी जाते हैं और रोते पीटते हैं तो वे कह देते हैं कि यह तो हमको मालूम है कि यह लड़का और जीप कहां है लेकिन उस गिरोह के हाथ बहुत लम्बे हैं। हरियाणा पुलिस की अच्छी प्रतिष्ठा रही है लेकिन पुलिस वर्दी में खोये हुए बेटे के बाप को यह कह दे तो उस पर क्या बीतेगी? आखिर कितना समय लगता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाड़ खेत को खा रही है। इसके बारे में सरकार को चिंता करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट चिंता कर रही है, अखबार के सम्पादक चिंता कर रहे हैं यह राजनीतिक मामला नहीं है। सुशीला का मामला राजनीतिक नहीं सुशीला समाज की बेटी है। बेटी न चमार की होती है, न ब्राह्मण की होती है, न जाट की होती है, बेटी समाज की होती है। बेटियों पर जब अत्याचार का सिलसिला शुरू होता है, द्रोपदी के साथ जब अत्याचार होता है तो महाभारत इस धरती पर हुआ करता है। सीता की तरफ रावण पाप की दृष्टि से देखता है तो उसकी लंका जलकर राख हुआ करती है। महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, इस बार तो विश्व महिला वर्ष भी मनाया गया। सरकार को इस बारे में चिंता करनी चाहिए, कुछ करके दिखाना चाहिए। हरियाणा पुलिस के सारे मामले सी०बी०आई० को जा रहे हैं इसके माने क्या है? सी०बी०आई० में हरियाणा के लोग नहीं हैं। हरियाणा पुलिस से हरियाणा के लोगों का विश्वास उठता जा रहा है।

शिक्षा के बारे में इस बजट में कोई नए विद्यालय खोलने की बात नहीं है। सारी दुनियां के आंकड़े थे। हिन्दुस्तान में, हरियाणा में 2.5 परसैंट लड़के-लड़कियां दसवीं के बाद शिक्षा प्राप्त करते हैं।

और जिन देशों के साथ हम मुकाबला करते हैं वहां पर 66 परसैन्ट अमेरिका और कैनेडा जैसे मुल्कों में मैट्रिक से ऊपर लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं। जो विकासशील देश हमारी कैटेगरी में आते हैं वहां 47 परसैन्ट लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं। हमारे यहां पर केवल 55.9 परसैन्ट लिट्रेसी खींच तान कर कागजों में पहुंचायी है और इस क्षेत्र में बहनों का अनुपात तो बहुत ही कम हैं। चेयरमैन साहिबा, शिक्षा के ऊपर कोई विशेष बजट का प्रोवीजन न करना, यह कोई अच्छी बात नहीं है। इंग्लैण्ड में सदन के अन्दर इसी शिक्षा के ऊपर बात आई कि नागरिकों का निर्माण विश्व-विद्यालय में होता है, नागरिकों का निर्माण स्कूल की चारदीवारी से होता है इसलिये जो कौम अपनी पीढ़ी को प्रशिक्षित नहीं करती, वह दो गुणा पाप कर रही है। चेयरमैन साहिबा, इन्होंने यहां पर क्या किया कि जो अनुदान प्राप्त कालेजों के प्राध्यापक हैं, उनके वेतनमान तो सरकार ने बढ़ा दिये हैं लेकिन जो अनुदान प्राप्त प्राइवेट स्कूलज हैं, उनके मास्टर्ज व कर्मचारियों को उनके समान नहीं रखा गया है। अभी इन्होंने इकनोमिक सर्वे की रिपोर्ट में बताया कि 70,863 आदमी इंजीनियर्ज, डाक्टर्ज, आई०टी०आई० ट्रेन्ड, टैक्नोक्रेट्स इस समय बेरोजगार हैं और दूसरी ओर बी-एड, जे0बी0टी0 किये हुए लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। एक तरफ चेयरमैन साहिबा, प्रौढ़ शिक्षा के बारे में, 10-10 सालों से लड़के लड़कियां इस तरह के केन्द्र चला रहे हैं, उनमें मैट्रिक से सब लोग ऊपर हैं और इस तरह के कितने ही लोग कई बार जेलों में भी चले गये। इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार यूं ही टी0वी0 रेडियो पर एडवर्जिमैन्ट्स देती रहती है, जैसे हमने टी0वी में एक माता को बोलते हुए सुना है कि हम सब को एक साथ उठने का वक्त आ गया है, हम सब को एक साथ डुबने का वक्त आ गया है, इस तरह से सरकार इन फिजूल के नारों पर पैसा व्यर्थ ही बरबाद कर रही है। इस की बजाये जो लड़के लड़कियां ढाई-तीन सालों से प्रौढ़ शिक्षा से सम्बधित हैं, जिनको मेरे विचार से 10-10 साल से कम का तजुर्बा नहीं है, सरकार को चाहिये कि इन सब को जे0बी0टी0 ट्रेन्ड मान ले और उनको जे0बी0टी0 का पे स्केल देकर के जहां-जहां इस तरह के स्थान खाली हों, वहां ऐसे बच्चों/बच्चियों को एडजस्ट कर दे, इससे सरकारी पैसे का सदुपयोग होगा। चेयरमैन साहिबा, इन लोगों को पढ़ाते हुए 10-10, 15-15 साल हो गये हैं, उम्र उनकी पूरी हो गई है और वे अब ओवरेज वाली कैटेगरी में आ गयें हैं। अतः सरकार इस ओर ध्यान दे।

इससे आगे मैं यह कहना चाहूंगा कि भाई अजमत खां जी जब बोल रहे थे तो कह रहे थे कि हमारे इलाके में उर्दू पढ़ाने वाले कोई नहीं हैं। मैं तो यह कहूंगा कि उर्दू तो बाद में आती है, पहले तो सृष्टि में संस्कृत ही आती थी। देववाणी आती थी। जो जन्म, कर्म है, वह सब कुछ आज संस्कृत में है। चेयरमैन महोदया, वैसे तो संस्कृत पीठ हमारे कम हैं। सारे संस्कृत विद्यालय जितने हैं, महाविद्यालय जितने हैं, उन सब ने मिलकर एक सम्मेलन किया और उनकी यह मांग थी कि जो लोग आचार्य ट्रेनिंग लेकर आए हैं, बी लोग शास्त्री पास हैं, जो

[प्रो० राम बिलास शर्मा]

लोग ओ०टी० ट्रेन्ड हैं, सब जगहों पर सरकार अनुदान देती है लेकिन इन संस्कृत पीठों को कहीं पर भी यह अनुदान सरकार की ओर से नहीं दिया जाता। जो लोग प्राईवेट संस्थायें खोलकर बैठे हैं, उनको भी अनुदान दिया जाता है लेकिन जो लोग संस्कृत पढ़ा कर लोगों का उत्थान कर रहे हैं उनके लिये कुछ भी सहायता नहीं है। संस्कृत की शिक्षा-दीक्षा बहुत जरुरी है, इसलिये सरकार को इधर पूरा ध्यान देना चाहिये।

चेयरमैन महोदया, आप तो आर्य समाज विचारों की हैं, आपको याद होगा कि जब अंग्रेजों ने यहां पर वेदों को जलवा दिया था, खत्म कर दिया था तो जर्मनी के जो मैक्समुलर थे, उन्होंने अपने जीवन का यह लक्ष्य बनाया कि वेदों की मौलिक प्रति उपलब्ध करवाऊंगा। वेद की धरती हिन्दुस्तान से अगर वेदों को जलवाया गया था, या खत्म करवा दिया गया था तो उसी मैक्समुलर ने ओरिजनल प्रतियां देश में लाकर उपलब्ध करवाई। चेयरमैन साहिबा, सवाल यह है कि शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए न कि निरूत्साहित किया जाए। आज जो संस्कृत पढ़ा रहे हैं, वे सारे भूत और भविष्य को जानते हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : चेयरमैन साहिबा, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है। मैं भाई राम बिलास शर्मा की विद्वता और योग्यता पर तो कोई प्रश्न नहीं कर सकता लेकिन मैं उनसे आग्रह करूंगा कि यह असत्य है कि मैक्समुलर ने जो हमारे ओरिजिनल वेद थे वे यहां ला कर दिए। यह बात असत्य है, कृपया आप इसको अपने कथन में ठीक कर लें।

प्रो० राम बिलास शर्मा : चेयरमैन साहिबा, यह डिबेट का विषय हो सकता है। मैंने तो शुरू में कहा कि वेद की धरती हिन्दुस्तान है। लेकिन एक जलजला इतिहास में ऐसा आया, एक दबाव ऐसा आया, एक खूंखार किस्म की कौम ऐसी आई जिसने यहां की संस्कृति पर, सभ्यता पर, यहां के रहन सहन पर एक जबरदस्त चोट की। वह कौम इतनी चालाक थी कि उसने सोचा कि हिन्दुस्तान का आदमी प्रेरणा कहां से लेता है। जब उस ने देखा कि यह अपने इतिहास से प्रेरणा लेता है, यह वेदों से प्रेरणा लेता है और यह अपनी संस्कृति से प्रेरणा लेता है तब उन्होंने इन सारी चीजों को यहां से गायब करने का अभियान छेड़ा। यह बहुत लम्बा विषय है।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : चेयरमैन साहिबा, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे ऋषि मुनियों ने और विशेष कर देश के ब्राह्मणों ने हमारे वेदों को सुरक्षित रखा है। क्योंकि वेद ब्राह्मणों ने कंठस्थ किए हुए थे। मैं चाहता हूं कि ये अपने आप को करैक्ट करें। वेद वहां नहीं गए और मैक्समुलर उनको यहां नहीं ले कर आया। वे यहीं रहे हैं। हमारे देश के ऋषि मुनियों ने और उच्च कोटि के

विद्वानों ने सारे ज्ञान को यहीं सुरक्षित रखा है। आगे आने वाले समय में विदेशों में और दुनिया की सारी धरती पर आध्यात्मिकता की लहर भी यहीं से चलेगी इसलिए आप क्यों ऐसी बात कह रहे हैं।

प्रो० राम विलास शर्मा : चेयरमैन साहिबा, मुझे अच्छा लग रहा है कि राजेन्द्र सिंह बिसला जी की रुचि भी वेदों में है। मैंने शुरू में कहा था अपनी इस बात को ये भी मान रहे हैं कि इन्होंने सुरक्षित रखा। चेयरमैन साहिबा, मुझे उर्दू से विरोध नहीं, उर्दू के अध्यापकों को भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए और उनको मेवात में लगाया जाना चाहिए। जो बच्चे हरियाणा में उर्दू पढ़ना चाहते हैं, उनको पढ़ाया जाना चाहिए। जो पंजाबी पढ़ना चाहते हैं, उनको पढ़ाया जाना चाहिए। हम किसी भाषा के विरोधी नहीं हैं। परन्तु यदि संस्कृत पढ़ने पढ़ाने वाले नहीं रहेंगे, यह देव वाणी नहीं रहेगी और यह मानवीय संस्कृति यदि हिन्दुस्तान से खत्म हो गई तो उर्दू पढ़ने वालों की संख्या भी यहां कम हो जाएगी। चेयरमैन साहिबा, हिन्दुस्तान में यह मानवता तब तक है जब तक वेदों के संस्कार हमारे ऊपर हैं। जो हिन्दुस्तान के टुकड़े हम से अलग हो गए, वेदों के संस्कार से अलग हो गए वहां मां-बेटी लड़ रही हैं, भाई बहन लड़ रहे हैं। मुर्तजा और बेनजीर लड़ रहे हैं और उसकी मां और बेटी लड़ रही हैं। तो यह संस्कारों का कमाल है इसलिए मेरा आग्रह है कि संस्कृत के संबंध में जो अनुदान दिया जाता है, वह सब को बराबर दें। अगर संस्कृत को प्राथमिकता नहीं देनी तो बराबर तो रखें, इसके साथ भेद भाव तो न करें। आज उर्दू के अध्यापकों की जिस तरह से खोज हो रही है उसी तरह से संस्कृत के अध्यापकों की भी खोज होनी चाहिए। अब मैं सिंचाई के मामले में कहना चाहता हूं। चेयरमैन साहिबा, नहरों में गाद की बात तो इस बार जब सदन के बाद कोई विद्वान पत्रकार लिखेगा तब आएगी। जैसे मैन आफ दि मैच हुआ करता है, टौपिक आफ दि सैशन हुआ करता है। तो उसमें हरियाणा की नहरों की गाद, महंगी खाद और चीनी का कड़वा स्वाद वह लिखेगा। यह तो उसके बाद की बात आएगी। चेयरमैन साहिबा, मैंने शुरू में कहा था कि यह जो बजट है इसके लिए कुछ रस्में हैं, कुछ पार्लियामैंटरी कन्वैन्शंज है। चेयरमैन साहिबा, बिजली के दाम तीन बार बढ़ा लिए और फिर कह दिया कि हम बिजली के लिए 476 करोड़ रुपए रख रहे हैं। कम से कम जब बजट अधिवेशन बुलाया था तो हरियाणा के लोगों की तसल्ली हो जाती कि बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, बिजली को कितना पैसा मिलेगा, ये बिजली कैसे देंगे। लेकिन सदन में बिजली के बारे में चर्चा न हो। चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी भले आदमी हैं और इनको उधर ले जाते ही बिजली में फंसा दिया। चेयरमैन साहिबा, यह बजट अधिवेशन है और सरकार कोई भाग नहीं रही। कोई दिक्कत नहीं है। आने जाने वाली और वह जहाज डूबने वाली बात तो साल-छः महीने बाद आएगी। तो मुख्य मन्त्री जी से मैं आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं कि जो यह एस०वाई०एल० का मामला है और चाहे वह यमुना जल समझौते का मामला है इसकी तरफ आपका ध्यान

[प्रो0 राम बिलास शर्मा]

नहीं गया । नरसिम्हा राव जी को बचाते बचाते आपको चिन्ता केन्द्र की ज्यादा रही । अब कुछ दिन हरियाणा की भी चिन्ता करें । एस0वाई0एल0 के मामले पर इनसे मैं फिर कहना चाहता हूं कि हरियाणा यदि बचेगा, हरियाणा का गरीब किसान जहां बचेगा, वहां राजनीति भी बचेगी और पार्टियां भी बचेंगी । इस काम में तो राजनीति से थोड़ा ऊपर उठकर इस पर एक बार फिर से चिन्ता करके विचार करें । इस पर आप हरियाणा प्रदेश के लोगों को कुछ करके दिखाएं । आपको राज करते हुए चार साल हो गए । चार साल का समय किसी सरकार को अपनी प्राथमिकताएं अभिव्यक्त करने के लिए और अपनी प्राथमिकताओं पर कार्यवाही करने के लिए कोई कम समय नहीं होता । लोगों के सामने आपने जो वायदे किए थे कम से कम आप उन वायदों को तो पूरा करें । आज हरियाणा प्रदेश के किसान जगह-जगह आन्दोलित हैं । चेयरमैन साहिबा, बहुत से लोग आन्दोलनों में मरे है । अभी 10 अगस्त को नारनौल में दो नौजवान पुलिस की गोलियों से पानी मांगते-मांगते मरे । इसी तरह से नारनौंद में बिजली मांगते-मांगते एक शमशेर सिंह नाम का नौजवान पुलिस की गोलियों से मरा । इसी तरह से निसिंग में बिजली और पानी मांगते मांगते किसान मरे । चेयरमैन साहिबा, यह जो आन्दोलन उठते हैं उनके बारे में कह दिया जाता है कि फलां आदमी किसानों को भड़का रहा है, लेकिन मैं इस सरकार को कहना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश का किसान आज बहुत ज्यादा समझदार है वह किसी के बहकाने से भड़कता नहीं है । कई बार लोग बिरादरी में फंस जाते हैं कि चौधरी भजन लाल जी उन को पसंद नहीं है । यह ऐसी बात नहीं है । चेयरमैन साहिबा हरियाणा प्रदेश का किसान विचारों से जुड़ता है । हरियाणा का किसान सरकारों की परफौरमैंस देखता है । हरियाणा का आदमी सरकारों की कारगुजारी देखता है लेकिन इस बजट में ऐसा कुछ नहीं है । यह इस जिन्दा सरकार का बजट है । इनकी इच्छा शक्ति खत्म हो गई है । वित्त मंत्री श्री मांगे राम गुप्ता जी ने कलम और दवात पर टैक्स माफ कर दिया । सेठ तो सयाना है न इन्होंने सोचा कि कलम दवात तो फिर पकड़नी है । साल भर बाद कलम दवात कहां जाएगी इसलिए इन्होंने अपने उपयोग में आने वाली कलम और दवात पर टैक्स माफ कर दिया । लुगाई बेलन से न पीटदे इसलिए इन्होंने सिन्दूर और चूड़ियों पर टैक्स माफ कर दिया । मेरा कहना है कि जो जीजी हैं वे जीजों के गेल रहती हैं । बिजली के रेट बढ़ा कर इस सरकार ने किसान को मार दिया । पीने का पानी मुफ्त देने की बात थी लेकिन इस सरकार ने शहरों में पीने के पानी पर टैक्स बढ़ा दिया । पहले 10 रुपये महीने के देते थे अब 10 रुपए की जगह 100 रुपया महीना देना पड़ेगा । चेयरमैन साहिबा, इस सरकार ने पानी नापने के नए मैयजर इजाद किए हैं । पहले पानी लीटर्ज में नापा जाता रहा है लेकिन इस सरकार ने कमाल ही कर दिया । अब यह सरकार पानी को गजों में नाप रही है । अगर 100 गज का प्लाट है तो

उसका पानी का रेट 100 रुपया महीना होगा और अगर प्लाट 300 गज का है तो उसका पानी का रेट 300 रुपया महीना होगा । इस सरकार ने पानी को गजों में नाप कर कमाल ही कर दिया । चौधरी फूला राम जी ऐसे विधायक हैं जिनको मैं यह कहता रहता हूं कि भाई आप पांच साल में कम से कम एक बार जरूर बोलो नहीं तो आपके कान गल जाएंगे ।

सभापति : शर्मा जी, आपको बोलते हुए आधा घंटा हो गया अब आप वाईंडअप करें ।

प्रो० राम बिलास शर्मा : चेयरमैन साहिबा, मैं आपका पड़ौसी भी हूं और आपका छोटा भाई भी हूं इसलिए आप मुझे बोलने का टाईम थोड़ा ज्यादा दें । इस सरकार ने 59.71 करोड़ रुपए के घाटे का बजट पेश किया है । चेयरमैन साहिबा, क्योड़क गांव की एक घटना है । उस गांव के हरिजन गांव छोड़ कर कैथल चले गए और उनके बारे में मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि वे सब लोग वापिस अपने गांव में चले गए हैं । चेयरमैन साहिबा, मैं 19 तारीख को जींद होकर आया हूं और वापिस आते समय मैं कैथल और क्योड़क होकर उनसे मिल कर आया हूं । अब भी उस गांव के 25 हरिजन परिवार कैथल की चार दिवारी के बाहर तम्बू लगाए बैठे हैं । चेयरमैन साहिबा, उनका कसूर केवल यह है कि उनमें से एक हरिजन लड़के ने वहां से जिला परिषद का चुनाव लड़ लिया और उस चुनाव में वहां का एक दिग्गज आदमी चुनाव हार गया । उस गांव के कुछ ठाडे लोगों ने कहा कि यह हरिजन कैसे चुनाव लड़ गया और इसके कारण हम चुनाव हार गए । इस बिनाह पर उसको गांव से उजाड़ दिया । चेयरमैन साहिबा, जब कोई आदमी गांव से उजड़ता है तो उसको बहुत पीड़ा होती है । यदि कोई पक्षी अपना घोंसला छोड़ता है तो उसको बहुत दर्द होता है । फिर यह सरकार हरिजनों के कल्याण की बात करती है । आज भी वह 25 हरिजन परिवार कैथल में तम्बू लगाए बैठे हैं । चेयरमैन साहिबा, उन हरिजनों के गले में जूतों की माला डाल कर एस०पी० ने कैथल शहर के बीचों बीच साथ साथ चल कर घुमाया और कहा कि तुम बोलो कि हम ढ़ेड हैं और चुनाव लड़ने की हमने हिमाकत की है । चेयरमैन साहिबा, एस०पी० उनके साथ इस तरह की कार्यवाही करे । इसी तरह से कैथल में एक एक्स एम०एल०ए० श्री चमन लाल सराफ को उल्टा लटका कर * * * * दे दिया । मुख्य मंत्री जी ने यह ठीक किया कि उस बारे में इन्कवायरी करवाई लेकिन आज तक वह पुलिस का दरिन्दा औफिसर वैसे ही घूम रहा है उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई ।

सभापति : माननीय सदस्य ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उनको रिकार्ड न किया जाए ।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया ।

प्रो0 राम बिलास शर्मा : चेयरमैन साहिबा, मेवात में जिन लोगों ने जिन्दा गउएं जलाई थीं, जिन्होंने मंदिर तोड़े थे उनके खिलाफ यानि जिन 595 लोगों के खिलाफ मुकद्दमे दर्ज हुए थे, वापस ले लिए । इसी प्रकार से बौंद गांव में एक भवन में एक सरकारी संस्था चलती है । वहां पर 37 लोगों के खिलाफ जो झठे मुकद्दमे दर्ज हुए थे, वे तो वापस लिए नहीं लेकिन उजीना गांव के किसन सिंह की और पल्ला गांव के कुन्दन लाल की हत्या करने वाले लोगों के खिलाफ जो मुकदमें दर्ज किए गए थे, वे वापस ले लिए गए । सरकार सारे गलत काम कर रही है । गुप्ता जी ने जो बजट पेश किया है, इससे आम आदमी में निराशा पैदा हुई है और लोगों में खामोशी है । यह बजट विफलताओं से भरा हुआ है । गुप्ता जी ने दवात और कलम को तो टैक्स से छूट दे दी लेकिन आम आदमी को राहत नहीं दी । सरकार ने भाईयों पर मार करके बहनों को जो राहत देने की कोशिश की है, वह बजट को प्रस्तुत करने वालों को मजा चखाएगी । धन्यवाद ।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह (उचानाकलां) : हमारे वित्त मंत्री ने इस सदन में हरियाणा सरकार का लेखा-जोखा रखा है कि 1995–96 में सरकार क्या करने जा रही है । इसके विषय में जो बजट रखा है, उस पर मैं बोलना चाहता हूं । यह शायद इनका पांचवां बजट है । मांगे राम जी एक बजट जो पिछली सरकार को रखना चाहिए था, अपने कारनामों की वजह से नहीं रख सकी थी, इसलिए हो सकता है कि एक और बजट रखने की जरूरत पड़े और 5 साल की अवधि में 6 बजट प्रस्तुत करने का मौका इनको मिल सकता है । मैडम चेयरपर्सन, इसी तरह से डा0 मनमोहन सिंह ने भी अपना पांचवां बजट लोक सभा में रखा है । मैडम, आज 4 साल में देश में एक नयी चीज, एक नई बात जिसको हम उदारीकरण या लिबरेलाईजेशन कहते हैं, इस देश की अर्थ व्यवस्था में आई है । 4 साल का समय इस लिबरेलाईजेशन को टैस्ट करने का कोई समय नहीं है कि इससे इस देश की जनता को कोई लाभ हुआ या इससे देश की जनता को कोई नुकसान हुआ । चेयरमैन साहिबा, मैं एक बात अपनी ओर से कहना चाहता हूं । मेरी अपनी राय है कि उदारीकरण के संदर्भ में हरियाणा की सरकार को अपने बजट को नये नुक्तानिगाह से देखना चाहिए और नई दिशा इस बजट को देनी पड़ेगी । जो बजट इस साल आया है वह स्टीरियो टाईप्ड बजट है जैसा कि पहले आता रहा है । मेरा अपना यह विचार है, मेरा यह मानना है कि दिल्ली के नजदीक होने के कारण हरियाणा में अगले 10 साल में उद्योगों का विस्तार होगा । हरियाणा में जितना उद्योगीकरण होगा उतना शायद देश के किसी अन्य प्रान्त में नहीं हो सकेगा । यह स्वाभाविक है क्योंकि राजधानी के साढ़े तीन तरफ हरियाणा लगता है और जहां पालम ऐयर पोर्ट जैसा हवाई अड्डा है वहां से दुनिया के हर कोने में हरियाणा के उद्योगों में बना हुआ माल पहुंच जाता है । चेयरमैन साहिबा, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि स्टेट में तेजी से उद्योगों का विस्तार होगा यह एक समस्या हो

जाएगी । लेकिन दूसरी जो एक बड़ी समस्या है उसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं । यह बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या है । आज प्रदेश के नौजवानों में बेरोजगारी है, कितने लोग और नौजवान ऐसे हैं जिनके नाम नौकरियां पाने के लिए रोजगार कार्यालयों के रजिस्टरों में दर्ज हैं । लेकिन हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी है कि जब किसी को 10वीं, बी0ए0 या एम0ए0 की सन्नद मिलती है तो वह चाहता है कि उसको नौकरी मिल जाए और वह सिर्फ सरकारी नौकरी चाहता है । चेयरमैन साहिबा, सरकार कितने लोगों को सरकारी नौकरियां दे सकती है। सरकार के पास इतनी नौकरियां देने के लिए कहां हैं जो हर नौकरी नौजवान को दे सके । हर नौजवान को नौकरी देना सरकार के लिए सम्भव नहीं हो सकता है । हरियाणा में जिस कद्र उद्योगीकरण हुआ है मेरा अपना यह मानना है कि अगले 10 साल में हरियाणा के 100 किलो मीटर तक के ऐरिया में कहीं भी चले जाईये वहां पर उद्योग ही उद्योग लगे हुए होंगे । चेयरमैन साहिबा, इसमें समस्या यह है कि जो भी उद्योग लगता है उसमें तकनीकी ज्ञान वाला आदमी वे लोग लगाते हैं। उनमें 90% बाहर के आदमियों को नौकरियां दी जाती हैं । मुझे इस बारे में पता नहीं सरकार इसका पता लगाए कि वे कितने लोगों को बाहर से लाकर नौकरियां देते हैं । चाहे वे लोग बिहार से हैं या यू0पी0 से हैं या महाराष्ट्र से या किसी और प्रदेश से हों, लेकिन हरियाणा के लोगों को नौकरियां नहीं देते हैं। यह स्थिति ठीक नहीं है। अगले 10 साल के अन्दर इतने उद्योग बढ़ेंगे जिससे कम से कम 10 लाख रोजगार के नये साधन पैदा होंगे लेकिन अगर बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के रहने वाले लोगों को यह रोजगार मिलता है तो फिर इन उद्योगों को हमारी धरती पर लगाने का क्या फायदा है । चेयरमैन साहिबा, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो लीडरशिप है चाहे वह मुख्य मन्त्री जी हैं, विपक्ष के नेता हैं उनको ब्यूरोक्रेट्स पर नीति के मामले में डिपैंड रह कर नीति तय नहीं करनी चाहिए यह नजरिया आपको बदलना पड़ेगा हरियाणा में जो बेरोजगारी की भयानक समस्या है यदि इस ओर ध्यान न दिया गया तो यह और भयानक हो सकती है जिससे कि हम जूझ रहे हैं और लड़ रहे हैं । चेयरमैन साहिबा, इस बारे में मैं फाईनैंस मिनिस्टर को भी कहना चाहूंगा कि वे इन बातों पर गौर करें ताकि हम बेरोजगारी की समस्या से लड़ सकें । चेयरमैन महोदया, मेरा इनको एक सुझाव है, अगर यह मानकर चलें कि कल को 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा तो कम्पनी वाले तो अपने यहां पर अच्छे टैक्नीकल आदमी रखेंगे । इसलिए इस सरकार को सी0 आई0 आई0 के थ्रू यह पता करना चाहिए कि उनको कितने आदमियों की आने वाले सालों में जरूरत है । मिसाल के तौर पर आप एस्कोर्ट कम्पनी को लें । फर्ज करो उस कम्पनी को 10 हजार आदमियों की जरूरत है । उन आदमियों के बारे में ये सी0 आई0 आई0 से लिस्ट ले लें कि उनको किस तरह के आदमियों की जरूरत है और उसी तरह की ट्रेनिंग अपने यहां पर दी जाए और लड़कों को ट्रेन्ड किया जाए। इस तरह उन ट्रेण्ड बच्चों को

[चौधरी बीरेन्द्र सिंह]

यह लगेगा कि कि अब उनको रोजगार मिल जाएगा। जब हमारे बच्चे इस प्रकार का तकनीकी ज्ञान लेने के लिए आगे आएंगे, तभी हम बेरोजगारी से लड़ सकेंगे। दूसरी समस्या यह है कि अगर हरियाणा में उद्योगों को विकसित करना है तो यह मानकर चलना पड़ेगा कि हमारे यहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर है और वह बिजली है। सब से पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि हिसार में मुख्यमन्त्री जी ने ब्यान दिया था कि हरियाणा के अन्दर चार साल तक बिजली नहीं बनेगी।

बिजली मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : चेयरमैन साहिबा, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मेरे को पता नहीं इन्होंने कहां से यह ब्यान पढ़ा है और न ही मेरी नौलेज में है कि मुख्य मंत्री जी ने यह बात कही होगी। शायद थर्मल बेस्ड प्लांट का कहा होगा। पानीपत में हमारे पास एक छठा यूनिट है, डीजल बेस्ड प्लांट के लिए हमने एडवरटाईज किया है और हमारे पास टैन्डर भी आ गए हैं। उससे एक-डेढ साल के अन्दर बिजली मिल सकती है।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : चेयरमैन महोदया, थर्मल बेस्ड प्लांट 4-6 साल तक लग ही नहीं सकता है। सरकार ने तो इस नीयत से फैसला किया है कि आमदनी सरकार की हो। चाहे हिसार, जमुना नगर या फरीदाबाद में ये प्लांट लगे। बिजली कोई और बनाएगा और यह सरकार तो यह देखेगी कि वे हमें कितने रेट पर बिजली देंगे। इतनी बड़ी इन्वैस्टमैंट राज्य सरकार के बस की बात नहीं है। ये जो उदारीकरण की बात करते हैं तो ये हरियाणा को लगातार बिजली देने में सक्षम नहीं रहेंगे क्योंकि आबादी बढ़ जाएगी और साथ-साथ कंजम्पशन भी बढ़ेगी। अगर बिजली नहीं मिलेगी तो उससे कन्जयूमर, दुकानदार और किसान ही मरते हैं। मेरा तो यह अनुरोध है कि अगर आप प्राईवेट सैक्टर को बिजली बनाने का काम दें तो बिजली की समस्या का समाधान हो सकता है। मैं आपको मिसाल के तौर पर नोएडा की बात बताता हूं जिसे ग्रेटर नोएडा भी कहते हैं। वहां पर यू0 पी0 वालों ने कलकत्ता की एक प्राईवेट कम्पनी को बिजली बनाने का काम दिया है और उन्होंने उनसे कहा है कि खुद बिजली बेचो, खुद बिल दो और खुद पैसा इक्ट्ठा करो। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। जब तक आप हरियाणा के पांच बड़े शहरों यानी यमुनानगर-जगाधरी, फरीदाबाद, पानीपत, हिसार और गुड़गांव में बिजली देने के काम को प्राईवेट सैक्टर में नहीं देंगे, तब तक बिजली की समस्या दूर नहीं होगी। इंडस्ट्रीज के अन्दर, डोमैस्टिक बिजली और कामर्शियल बिजली देने का सारा काम अगर आप प्राईवेट सैक्टर में दे देंगे तो तीस परसैंट, जो बिजली अब हमारे पास है, उसको हम बचत कर सकेंगे और वह तीस प्रतिशत बिजली हम किसानों के ट्यूबवैल्ज के लिए, किसानों के घरों के लिए 24 घंटे दे सकेंगे।

श्री बीरेन्द्र सिंह : चेयरमैन मैडम, इन्होंने जो कहा है, इनकी यह बात भी हम सोच रहे हैं, यह अंडर कंसीडेशन है।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : लेकिन आप ऐसा नहीं सोच रहे हैं। चेयरमैन सर नौएडा में क्या किया है ? नौएडा में यह किया है कि उन्होंने बिजली के 25 मैगावाट के प्लांट लगाने का फैसला कर लिया और काम शुरू कर दिया है।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल) : हमने भी पहले यह काम प्राईवेट सैक्टर में देने के लिए ऐडवरटाईजमैन्ट कर रखी है।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : लेकिन अभी तक तो आपने केवल इजरायल की फर्म से ऐग्रीमैन्ट किया है।

चौधरी भजन लाल : हमने दूसरे भी टैंडर कॉल किए हैं। अब कोई आए और आकर वह 50, 75 या 100 मैगावाट के प्लांट लगा सकता है।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : अगर आपने ऐसा किया है तो आप इस बारे में फौरी तौर पर कार्यवाही करें। अगर आपने ऐसा किया तो किसानों को 6 महीनें के अंदर-अंदर ही राहत आप दे सकते हैं। आज हरियाणा के अंदर किसानों के जो ऐजीटेशन होते हैं, उसका सबसे बड़ा आधार बिजली की कमी है। मैं मुख्य मन्त्री जी से यह कहना चाहता हूं कि आज किसान केवल दो ही बातें देखते हैं–एक तो बिजली की कमी और दूसरी बात है पानी की कमी। बिजली की कमी तो हम जरूर पूरी कर सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि जिस सिस्टम की बात मैंने कही है, अगर उसी तरीके से हम करेंगे तो बिजली की कमी पूरी कर सकते हैं। आज आप जो बिजली उद्योग-धंधों में देते हैं उस बिजली को दूसरे सैक्टर्ज में तबदील करके किसानों को वह बिजली 24 घंटे के लिए दे सकते हैं दुकानों के लिए और घरों के लिए भी हम बिजली दे सकते हैं। चेयरमैन साहिबा, इसके अलावा, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जब बिजली की कमी पूरी होगी तो उससे हमारा खेती का उत्पादन भी बढ़ेगा क्योंकि फिर खेती में किसान को ज्यादा मेहनत से काम करना पड़ेगा। अगर हरियाणा में एग्रीकल्चर सैक्टर में ऐग्रीकल्चर की डाई-वर्सीफिकेशन नहीं होगी तो हमारा किसान पिछड़ जाएगा। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि किसान जो चीजें पैदा करते हैं, उनको उनका पूरा मूल्य मिलना चाहिए। मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर हरी सब्जी खाड़ी के देशों में पहुंचाई जाए तो इससे किसानों को बहुत फायदा मिलेगा। आज किसान अपनी एक किलो मूली हरियाणा की मंडी में ढाई रुपये किलो बेचता है। अगर उसकी उसी मूली का हरियाणा से पालम हवाई अड्डे तक जाने का इंतजाम हो जाए और वहां से वहां वह खाड़ी के देशों में चली जाए तो वही मूली ढाई सौ रुपए किलो में बिकती है। आज मुख्य मन्त्री जी ने मन्त्रियों की तो बहुत लम्बी लाइन लगा रखी है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आप नया डिपार्टमैंट कामर्स का भी शुरू कीजिए। इससे जिसने भी छोटे व्यापारी है या किसान हैं, उनको दूसरे देशों के साथ व्यापार करने का मौका मिलेगा। आज मुख्यमन्त्री के चारों तरफ

[चौधरी बीरेन्द्र सिंह]

जो लोग हैं या जो ब्यूरोक्रेटस हैं, उनको दूरदर्शिता से काम लेना चाहिए, तभी हम उनको क्रेडिट दे सकते हैं, लेकिन अगर वह इस बात का क्रेडिट लें कि किसी ऑफिसर की प्रमोशन है, वह फलां जाति का है, इसलिए उसकी प्रमोशन नहीं होने देंगे तो ऐसी बातों में कोई क्रेडिट देने की बात नहीं है । हरियाणा में पहली बार ऐसा हुआ है कि आई० ए० एस० कैडर को कम किया गया है क्योंकि जिन आठ आदमियों की प्रमोशन होनी थी, उन में से आठ जाट थे और एक हरिजन था। उन्होंने कहा इतने आदमियों की प्रमोशन नहीं होने देंगे । लेकिन उनको ऐसी सोच को बदलना पड़ेगा, हमारे पोलिटिकल सिस्टम से अलग हटकर उन को ऐसी बातों को अपनी सोच से निकालना पड़ेगा ।

चौधरी भजन लाल : ऑन ए प्वायंट ऑफ आर्डर चेयरमैन साहिबा, इस सरकार के दिमाग में कभी कोई जात-पात की बात नहीं आई है । यह सोचने की बात भी नहीं है, जिनका हक है उनको मिलेगा । यह कहना कि जाट है इसलिए कॉल नहीं करने की बात है, यह बिल्कुल बेबुनियाद और गैर-जिम्मेदाराना बात है, इसको आप हाउस की कार्यवाही से निकलवाइए ।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : चेयरमैन साहिबा, हाउस में अगर मैंने कोई अनपार्लिया-मैंट्री बात कही हो तो उसको हाउस की कार्यवाही से निकाला जा सकता है । मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है । जहां तक जात-पात की बात है यह हमारे सिस्टम में इतनी बुरी तरह घुस गई है । हम पोलिटिकल लोग तो इन बातों को सोचते थे लेकिन ब्यूरोक्रेट सोचें, हमारी सरकार के अधिकारी सोचें, यह कोई न्यायोचित बात नहीं है । आदमी वोट लेने के लिए 100 भेष बदलता है । जिन अधिकारियों का काम सरकार की नीतियों का पालन करना है वे अगर इस किस्म की ऐडवाइस सरकार को दें तो यह कोई न्यायोचित बात नहीं है। सोचने की और बातें बहुत हैं। आज पानी का मसला है । चौधरी बंसी लाल जी ने कहा कि सरकार जांच करवाए कि चार नदियों पर जो बांध हैं यह नारनौल और महेन्द्रगढ़ व रिवाड़ी के इलाके में आते थे, यह बांध कोई आज तो नहीं बने यह 10–12 साल से बने हैं । साहिबी नदी पर बांध बनने की बात हुई थी उसके बाद सभी मुख्यमंत्री बने और तब किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज बंसी लाल जी कह रहे हैं कि उनके निर्माण की जरूरत है। यमुना जल समझौते की बात उन्होंने कही । (विघ्न) यमुना जल समझौते को कोई राजनीतिक रूप दें लेकिन एक बात से मैं सहमत हूं कि जिस दिन यमुना जल समझौते के अन्तर्गत किसाऊ डैम बनेगा उस दिन वैस्टर्न यमुना कैनाल का सिस्टम है जो आज 14 जिलों की धरती प्यासी है उसको पानी तभी मिल सकता है जब किसाऊ डैम बनकर तैयार हो । मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि चाहे हथनी कुंड बैराज हो, चाहे यमुना जल समझौते के तहत दूसरे कोई काम हों, आपकी प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि आप सब कामों को दूसरे नंबर पर रखकर किसाऊ डैम को बनवाने के लिए प्रयत्न करें,

तभी हम यमुना जल समझौते का लाभ उठा सकेंगे वर्ना हमें उसका नुकसान उठाना पड़ेगा किसाऊ डैम 10 साल नहीं बना तो हरियाणा की जनता को इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। आज हरियाणा के अंदर एस0 वाई0 एल0 की बात है। मैं नहीं समझता कि एस0 वाई0 एल0 बनने में किस किस्म की क्या रुकावट है ? केन्द्र सरकार चाहती है, प्रधानमंत्री जी चाहते हैं और हम भी कई बार मिले हैं वे इस बात के लिए बड़े प्रयत्नशील हैं। पंजाब के अंदर ऐसा माहौल भी बनता जा रहा है, हरियाणा भी चाहता है आखिर रुकावट किस बात की है। पंजाब का बजट आया है उसमें पिछले साल भी 10 करोड़ रुपये का प्रौविजन एस0 वाई0 एल0 के लिए था और इस बार भी 10 करोड़ रुपये का प्रौविजन है इस हिसाब से एस0 वाई0 एल0 अगले साल भी बनने की स्थिति में नहीं होगी। आप जहां एस0 वाई0 एल0 बनाने का प्रयत्न करें वहीं दूसरी ओर यह भी देखें कि और कौन से जल साधन हैं जिनको हरियाणा की जनता के लिए, हरियाणा के किसान के लिए जुटा सकते हैं। मैंने कई बार यह बात उठाई है कि घग्घर, मारकंडा और टांगड़ी नदी पर दो महीने मानसून के दिनों में कई लाख क्यूसिक पानी बेकार बह जाता है बल्कि कई जगह घग्घर का जो ओटू का इलाका है, वह फ्लड की स्थिति में आ जाता है। क्या इस पानी को हम कहीं बैराज बनाकर, रोककर अम्बाला के किसान, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र के किसानों को फायदा नहीं पहुंचा सकते हैं, अवश्य पहुंचा सकते हैं और जो इस बैल्ट में जल स्तर पानी का नीचे जा रहा है वह ऊपर आ सकता है। इस बैल्ट को हम राइस बैल्ट कहते हैं, व्हीट बैल्ट कहते हैं यह पानीपत तक हमारी बैल्ट है। मैं चाहता हूं कि बैराज बनाकर इस पानी को रोकने का प्रावधान किया जाए। अफसोस इस बात का है कि बजट का 72 परसैंट सिर्फ तनख्वाहों पर जाता है बाकी 28 परसैंट से ये क्या नहरों की गाद निकालेंगे और क्या करेंगे। जैसे रामबिलास जी ने जींद के एक रामबिलास का नाम लेकर बड़ा कुछ कह दिया कि उसका अपहरण हो गया। मैं उन से कहूंगा कि रामबिलास जी, अगर आपके पास पूरे तथ्य न हों तो कम से कम आप बोला न करें। आपको जींद के रामबिलास के बारे में पूरी तरह से पता होना चाहिये कि इस केस को 6 एस0 पीज0 ने जांच की है और छः के छः एस0 पीज0 ने यह लिखा है कि जो यह कमप्लेनेन्टस हैं ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं कि वह आदमी गायब है, मिसिंग है। मिसिंग और किडनैपिंग में बड़ा ही फर्क है। जो आदमी मिसिंग है, उसके बारे में यह तथ्य सामने आया कि वह मैंटली डिस्टर्बड था और इस मामले में यूंही प्रतिष्ठित आदमियों को तंग किया जाए, यह ठीक नहीं है। कोई तथ्य यह नहीं बोलता कि आप सरकार को गाली निकालते रहें और कुछ भी सरकार के खिलाफ कहें और हम बैठकर आराम से सुनते रहें, यह नहीं हो सकता।

प्रो० रामबिलास शर्मा : चेयरमैन महोदया, चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी का गुस्सा तो कहीं और है और झाड़ मेरे पर डाल रहे हैं। जहां तक इन्होंने तथ्यों की बात कही है, मेरे पास जनसत्ता जोकि एक प्रतिष्ठित अखबार है, उसकी कटिंग है और यह 8 दिसम्बर, 94 की कटिंग है, हिन्दुस्तान अखबार की कटिंग है और यह वुलन्दर किसान अखबार जोकि वहां का स्थानीय अखबार है, उसकी कटिंग मेरे पास मौजूद

[श्री0 राम बिलास शर्मा]

है। जो मैंने पढ़कर सुनाया है 14-11-94 को मुख्यमन्त्री महोदय के पास 100 से ज्यादा लोगों ने इस बारे में लिख कर भी दिया और मुख्यमन्त्री जी ने जो आर्डर उस पर किये, वे भी मैंने पढ़कर सुनाये हैं। फिर ये कहां से आ गया कि वह आदमी मैन्टली डिरेल्ड है। एक आदमी का अपहरण हो जाए जिसके लिये बार बार लोग मांग कर रहे हैं कि इस मामले की जांच होनी चाहिये। यह तो एक नौजवान है चेयरमैन महोदया, यहां पर तो लड़कियां गायब हो जाती हैं और यहां पर जैसा कि पिछली बार कह दिया गया था कि फलां लड़की का करैक्टर ठीक नहीं था। चेयरमैन महोदया, ये लोग अपनी सरकार की तारीफ करें, परन्तु कम से कम हमारे ऊपर इल्जाम मत लगाएं कि हम जो कुछ कह रहे हैं, वह सही नहीं है तथ्यों के आधार पर कहा करें। मैंने जो कुछ कहा है, वह सब तथ्यों के आधार से कहा है। जो जो अखबारों की कटिंग मेरे पास मौजूद है और लोगों की इस बारे में मांग भी यही है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो, तो इससे ज्यादा तथ्य और क्या हो सकते हैं। बाकी मांगे राम गुप्ता जी यहां पर बैठे हैं, इनके जीन्द हल्के की यह बात है, वे बता देंगे।

श्री मांगे राम गुप्ता : चेयरमैन महोदया, रामबिलास जी अमूमन जीन्द आते जाते रहते हैं और 19 तारीख को ये जीन्द गये भी थे। यह कहते हैं कि 100 आदमियों ने मुख्यमन्त्री महोदय को दरख्वास्त दी थी। पता नहीं उस पर कितनों ने साईन किये थे और उन्होंने यह कह दिया कि जांच करो और मुझे जवाब दो। आपको पता ही है कि जांच तो अधिकारियों ने ही करनी है। चेयरमैन साहिबा, यह असलियत है कि यह किडनैपिंग का केस नहीं है। यह कोई बच्चा नहीं है, 40 सालों का यह नौजवान है, कारोबार करता है। जोकि एक बार नहीं, तीसरी बार गया है। वह अपने ही लैवल पर जाता है। वह मैन्टली ठीक नहीं है। और उसके फादर को भी ये अपोजीशन के लोग बरगलाते हैं। उसको ये कहते रहते हैं कि आप इनके खिलाफ दरख्वास्त दो। उसने तो मेरे खिलाफ भी दोष लगाया है कि गुप्ता जी का भी उसको मिसिंग करने में हाथ है। चेयरमैन महोदया, मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें किसी का भी हाथ नहीं है। वह खुद ही जाता है। पहले वह जब गया तो दो महीने के बाद आया, फिर साल डेढ़ साल के बाद आया और अब भी पता नहीं वह कितने दिनों में वापिस आ जाएगा। मैं नहीं कह सकता कि इसमें कोई गल्त बात हुई है। (शोर)

श्री0 रामबिलास शर्मा : चेयरमैन महोदया, वे लोग कल ही मुझे मिले हैं। (शोर) उन्होंने मुझे बताया है। जिस तरह ये सरकार अब कह रही है, उसी तरह सुशीला कांड के बारे में भी कहती थी। (शोर)

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : चेयरमैन महोदया, मैंने जो बात कही है, वह पूरी इंफर्मेशन के आधार पर ही कही है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई गल्त बात हुई होगी। मैं तो राम बिलास जी को कहूंगा कि जो आप देखते हैं वही सब दुनिया नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी है। आज ये लोग यहां पर क्योड़क के हरिजन परिवारों की

बात कहते हैं । अब अगर राजनीतिक बात मैं उठाऊंगा तो बात बहुत लम्बी हो जाएगी (शोर) । मैं तो यही कहूंगा कि यह न तो मिसिंग है, न ही किडनैपिंग है और न ही इसमें किसी का हाथ ही है । पुलिस ने पूरी तरह से जांच कर ली है । अच्छे से अच्छे इज्जतदार आदमियों का नाम इस केस के बारे में उस लिस्ट में रखा गया था और पुलिस ने उनकी तसल्ली करने के लिए इन सारे इज्जतदार आदमियों को पूरी तरह से इंटेरोगेट किया है और कोई इस में अन्याय की बात नहीं हुई है । ये लोग खुद भी इस बात की जांच जाकर करें कि आखिर यह माजरा क्या है तो इनको तसल्ली हो जाएगी । जितने आप और आपकी पार्टी गरीबों की हमदर्द है, वह हमें पता है । किस तरह से आपने मेवात में वातावरण को खराब करने की कोशिश की थी । किस कदर आपने अपने भाषणों में बातें कही थी ।

प्रो0 राम विलास शर्मा : चेयरमैन महोदया, चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने फरमाया है कि मेवात में हमने वातावरण खराब किया । हमने वातावरण कैसे खराब किया ? वहां पर एम0 एल0 ए0 तो आपके हैं और मन्त्री आपके हैं । वहां पर जब मन्दिर तोड़े गए तो इनके मन्त्रियों पर वह बात आई। वहां पर 595 आदमियों के खिलाफ मुकदमें दर्ज हुए थे ।

श्री अजमत खां : चेयरमैन महोदया, अच्छा यह होगा कि यहां पर मेवात का जिक्र न करें वरना इनके दिए हुए घाव तो अभी भरे नहीं हैं ।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : तो चेयर पर्सन साहिबा, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब मैंने लिबरलाइजेशन की बात की तो मैंने शुरु में यह कहा कि सरकार की कंसेप्ट को बदलना होगा । ये कहते हैं कि हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी थी अलावा और बड़ी जिम्मेदारी थी जिसको हम समाजवाद के तहत निभाते थे और अब भी हम कायम हैं । लेकिन चाहे दुनिया के अन्दर लिबरलाइजेशन की बात चले, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी तीन बातों पर है । सबसे पहले ला एण्ड आर्डर, दूसरी शिक्षा के बारे में और तीसरी स्वास्थ्य के बारे में । मैं फाइनैंस मिनिस्टर साहब को कहना चाहता हूं कि इन तीन बातों पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है । आज शिक्षा का स्तर क्या है । माफ करना हम यहां जोर और से कहते हैं कि हमारे यहां कितने स्कूल अपग्रेड होंगे, दस से 12 कितने होंगे । अभी गुहला चीका के भाई कह रहे थे उनके यहां दस से 12 का स्कूल बन गया । देखने की बात यह है कि आज शिक्षा का स्तर क्या है । हरियाणा का बच्चा अगर दस या 12 जमात पढ़कर अगर अर्जी भी न लिख सके तो वह क्या शिक्षा है । यह ठीक है कि वह दस जमात पढ़कर कहेगा कि मुझे क्लर्क लगा दो, पुलिस में भर्ती कर लो या चपरासी लगवा दो । लेकिन आज हमारी जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है । इस बदलते हुए समाज में अगर हम बच्चों को सिर्फ चपरासी लगाएंगे या पुलिस में भर्ती करवाएंगे या छोटी नौकरियां देंगे तो कौन आदमी हमारे ऊपर राज करेगा । राज वह करेगा जो अच्छे स्कूलों में पढ़ते

[चौधरी बीरेन्द्र सिंह]

हैं। अगर हम आज हरियाणा के बच्चों को शिक्षा में पीछे रख देंगे तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों से सब से बड़ी गद्दारी करेंगे। इसलिए जरूरी है कि जो प्राइमरी शिक्षा है उसके लिए यह एनश्योर करें कि गांव में पढ़ाने वाले जो अध्यापक हैं उनका कैलिबर हो और उनकी अपनी सोच हो। वह टीचर उतना ही विद्वान हो जितना शहर में पढ़ाने वाला टीचर है। इसको हम तभी कर सकते हैं जब हम अध्यापकों की सिलैक्शन के बारे में सोचेंगे। आज फर्स्ट और सैकिंड डिवीजन वाले भाग रहे हैं कि मैं जे0बी0टी0 बन जाऊंगा। आज सब से ज्यादा पढ़े लिखे बच्चे एम0बी0ए0 के बारे में सोचते हैं। उसके बाद मैडिकल के बारे में सोचते हैं, उसके बाद इंजिनियरिंग के बारे में और उसके बाद आई0ए0एस0 के कम्पीटीशन के बारे में सोचते हैं। अभी पीछे खबर आई थी कि देश की फौज में दस हजार से ज्यादा अफसरों की कमी बढ़ गई है। लड़के वहां जाना पसन्द नहीं करते। लेकिन बुद्धिजीवियों का क्रेज एम0बी0ए0 में है।

12.00 बजे

जो एम0बी0ए0 की ट्रेड है उसमें हरियाणा प्रदेश का बच्चा नहीं आ सकता क्योंकि उसको यह पता ही नहीं है कि एम0बी0ए0 क्या है और आई0ए0एस0 क्या है? मैं कोई जातिपाति की बात नहीं करता। सवाल आता है कि हरियाणा प्रदेश की जो 30 हजार पुलिस फोर्स है उसमें 25 हजार सिपाही हैं अगर उनमें कोई जैन जाति से हो तो आप बता दें अगर है तो मैं गलत राजनीति कर रहा हू लेकिन जैन जाति से कोई नहीं हैं। आज हमारे समाज में हरिजन कब तक पिसते रहेंगे, दलित वर्ग के लोग कब तक पिसते रहेंगे और बैकवर्ड क्लासिज के भाई कब तक पिसते रहेंगे। जब कोई लोन लेने की बात हो तो कह दिया जाता है कि नहीं साहब आपको बैंक से इतना लोन नहीं मिल सकता क्योंकि आप इतनी बड़ी नई फैक्टरी नहीं लगा सकते लेकिन जिस किसी ने पहले से बड़ी फैक्टरी लगाई हो या उसके बाप दादा ने बड़ी फैक्टरी लगाई हो उसको पूरी इजाजत है कि वह जितना मर्जी कर्जा ले ले। आज हमें सोचना पड़ेगा कि वह हरियाणा का गरीब आदमी जिसको गरीबी के रेखा से ऊपर उठाने की बात करते हैं चाहे वह किसान हो, चाहे वह दलित वर्ग हो और चाहे वह हरिजन हो उसको गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने की बात करते हैं। मैंने इस बारे में मुख्य मंत्री जी को एक डेढ़ साल पहले सलाह दी थी लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन मेरी उस बात में सत्यता थी। मैंने मुख्य मंत्री से यह कहा था कि आप दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दें। एक हरिजन वर्ग से और एक बैकवर्ड क्लास से।

श्री सभापति : चौधरी साहब, आप वाइंड अप करें आपको बोलते हुए आधा घंटा हो गया है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : चेयरमैन साहिबा, मैं आपके माध्यम से चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी को सुझाव दूंगा। वह हरिजन और बैकवर्ड क्लास की बात करते हैं, मैं कहूंगा कि एक महिला को भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाना चाहिए।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : महिलाएं तो टू इन वन भी हैं और हमारी बहन करतार देवी जी तो थ्री इन वन हैं। वह हरिजन भी हैं, मंत्री भी हैं । और पढ़ी लिखी भी है। उन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही है कि एक महिला भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बननी चाहिए। एक बात मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे बच्चों को इस किस्म की शिक्षा मिल रही है जिसके कारण वे आगे नहीं बढ़ रहे हैं । मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारी तरक्की की जो रफ्तार है, जो तरक्की की दौड़ है, उसमें हमारे हरियाणा प्रदेश के बच्चे, गांवों के बच्चे पीछे रह जाएंगे। सारा पैसा चन्द हाथों में सिमट कर रह जाएगा। चाहे वह कोई राजनीतिक हो और चाहे कोई सामाजिक हो उसके पास पैसे की ताकत रह जाएगी । मैं सरकार से यह पुरजोर सिफारिश करता हूं कि सरकार शिक्षा पद्धति को सुधारे । चाहे वह टीचर्ज की सिलैक्शन है और चाहे वह बच्चों के एडमिशन हैं । इन बातों के बारे में पुनर्विचार करने की जरूरत है । बहन करतार देवी स्वास्थ्य मंत्री हैं । मैं इनकी बात कहना चाहूंगा कि गांवों के अन्दर जो पी0एच0सीज0 हैं अगर उनमें किसी डाक्टर का ट्रांसफर कर दिया जाता है तो वह यही कोशिश करेगा कि वह वहां न जाए और वह दो महीने का डैपुटेशन करवाना चाहता है जैसे रोहतक जिले के डिग्गल गांव के पी0एच0सी0 में किसी डाक्टर का ट्रांसफर कर दिया जाता है तो वह रोहतक डैपुटेशन करवाने की कोशिश करता है । राजौन्द के पी0एच0सी0 में किसी डाक्टर की ट्रांसफर की जाती है तो वह कोशिश करके कैथल डैपुटेशन करवाता है। आप इस बारे में विचार करें कि ऐसा क्यों है । गावों में बहुत ज्यादा मौतें होती हैं और आजकल तो खास करके गांवों में यह सिस्टम चल गया है कि गांवों में सलफास की गोली खा करके अनेकों लोग मरते हैं। अगर किसी जगह पर अच्छा डाक्टर हो तो और अच्छी देखभाल करने वाला डाक्टर हो तो उस सलफास की गोली खाने वाले लोगों को बचाया भी जा सकता है । जो हम एक स्वस्थ समाज की संरचना करना चाहते है। वह समाज भी कायम कर सकते हैं । एक बात मैं पुनर्विचार के लिए कहना चाहता हूं । मुख्य मंत्री उस पर गौर करें । आप हरियाणा के अन्दर ऐसे अदारे कायम करें जिसमें बच्चों को ऋण दिया जाये। उसको छोटी मोटी फैक्टरी लगाने के लिए और बड़ी फैक्टरी लगाने के लिए धन की उपलब्धता करायी जानी चाहिए ताकि वह अपना काम अच्छी प्रकार से कर सके । सरकार को इसे पूर्ण सहानुभूति के साथ देखना होगा । जो मान्यताएं आज तक हमारी कायम हैं, उनको एक परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है ताकि हरियाणा में औद्योगिक क्रांति हरियाणा से बाहर जाने की बजाये यहीं पर रह सके और यहीं के बच्चे लाभ उठा सकें । यही मैं आपसे कहना चाहता था । धन्यवाद ।

चौधरी भजन लाल : चेयरमैन साहिबा 5–10 मिनट एक दो मैम्बर को बोलने देने के बाद मुझे भी बोलने का समय दे दीजिए क्योंकि पूरा जवाब तो कल वित्तमंत्री जी देंगे लेकिन कुछ मुद्दों पर मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा, इसलिए आध घण्टा मुझे भी समय चाहिए ।

अनेक आवाजें : हमें भी बोलने का समय चाहिए ।

श्री सभापति : आपको मौका देंगे, आप बैठिये । अगर जरूरत हुई तो हम समय बढ़ा लेंगे ।

श्री जय सिंह राणा (नीलोखेड़ी) : आदरणीय सभापति महोदया, 13 मार्च को जो बजट हरियाणा के वित्त मंत्री महोदय ने सदन में पेश किया है इस पर उसी दिन से चर्चा चल रही है । सभी सदस्यों ने इस पर अपने विचार व्यक्त किए हैं । मैं भी अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार बधाई की पात्र है और वित्त मंत्री भी बधाई के पात्र हैं कि इस बजट में कोई भी नया कर नहीं लगाया । जो राहत, सुविधाएं किसानों को व्यापारियों को मिल रही थी उनको जारी रखा गया है । किसी पर किसी प्रकार की सबसिडी हटायी नहीं गई । चेयरमैन साहिबा, बहुत से सदस्यों ने इस बजट को जनविरोधी बजट बताया है । इस बजट में कोई जन विरोधी बात नहीं है ।

इस बजट में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो जनता के हित में न हो । यह सारे का सारा बजट दर्शाता है कि इसमें जनता के हितों का तथा हर वर्ग के कल्याण का ध्यान रखा गया है । हमारा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है और इस प्रदेश की 82% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है । इस बजट में किसानों का पूरा ध्यान रखा गया है 70% बजट ग्रामीण इलाकों में खर्च करने का प्रावधान बजट में रखा गया है । इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों का खासकर ध्यान इस बजट में रखा गया है । चेयरमैन साहिबा, जहां तक किसानों का सवाल है, किसान की जो जरूरतें हैं चाहे वह बिजली है, चाहे वह खाद है या किसान के काम आने वाली कोई दूसरी सामग्री है, इस बजट में उसका पूरा ध्यान रखा गया है । नहरों के लिए बजट में 19.9% कुल बजट का हिस्सा दिया गया है । इसी तरह से खाद तथा कृषि उपकरणों पर जो सबसिडी पहले से ही मिली हुई है, वह सबसिडी जारी रखने का प्रावधान इस बजट में है । चेयरमैन साहिबा, पानी की बात नम्बर एक पर आती है क्योंकि कृषि प्रधान प्रदेश में नहरों का पानी होना बहुत जरूरी चीज है और इस बजट में इसका पूरा ध्यान और विचार रखा गया है । मैं मुख्य मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने यमुना जल समझौता करके एक महान कार्य किया है । यह समझौता एक ऐतिहासिक समझौता है जिससे प्रदेश को बहुत लाभ पहुंचेगा । इस समझौते की आधारशिला हथनीकुण्ड में रखी गई । यह बहुत ही अच्छा फैसला हुआ है जिससे किसान के खेत में और अधिक पानी पहुंचेगा और उसकी उपज अधिक बढ़ेगी जिससे किसान के खेतों में हरियाली होगी और उसके चेहरे पर रौनक होगी । चेयरमैन साहिबा, एस0वाई0एल0 का जिक्र बार-बार सभी सदस्य सदन में करते रहे हैं, सभी राजनैतिक पार्टियां करती रही हैं । चेयरमैन साहिबा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है । एस0वाई0एल0 का पानी हरियाणा की धरती पर आना बहुत जरूरी है ।

असल में तो इसकी शुरुआत ही गलत ढंग से हुई। चाहे कोई भी मुख्यमन्त्री रहे हो या सरकार रही हो उस वक्त उसने गौर नहीं किया। इस नहर की शुरुआत टेल से की गई जब कि इसकी शुरुआत हैड की तरफ से की जानी चाहिए थी। यदि इसकी शुरुआत टेल की बजाय हैड की तरफ से की गई होती तो आज यह समस्या पैदा ही न होती और ये दिन न देखने पड़ते। एस0वाई0एल0 का पानी कई वर्ष पहले ही हरियाणा में आ चुका होता। चेयरमैन साहिबा, 1987 में हरियाणा में जो सरकार बनी थी उसने हरियाणा की जनता को यह नारा दिया था और इस नहर को बनाने का वायदा किया था इसी वायदे पर वह सरकार बनी थी। उस सरकार ने लोगों से वायदा किया था कि एस0वाई0एल0 का पानी हरियाणा में ला कर देंगे। चेयरमैन महोदया, जैसे कि आप स्वयं भी जानती हैं कि उस समय जैसा नहर बनाने का अच्छा मौका शायद हरियाणा में कभी दोबारा न आए। उस वक्त केन्द्र में भी वही सरकार थी और हरियाणा प्रदेश में भी वही सरकार थी। जिसका पिता केन्द्र में डिप्टी प्राईमिनिस्टर था और स्टेट में बेटा प्रदेश का मुख्य मन्त्री था। (विघ्न) उस समय पंजाब की बागडोर गवर्नर के हाथ में थी, जो मर्जी कर सकते थे लेकिन उनकी नीयत साफ नहीं थी कि हरियाणा की धरती पर पानी आए। अगर वे चाहते तो ले सकते थे, लेकिन इन्होंने यह कोशिश नहीं की क्योंकि पानी आने से मुद्दा ही खत्म हो जाता है और वोट मांगने का यह साधन ही खत्म हो जाता। (विघ्न) चेयरमैन महोदया, आज वर्तमान सरकार ने प्रयास किया है और कर रही है कि हरियाणा के किसानों को पानी मिले। अगर इन प्रयासों में ये हमारे सहयोगी बनते और पूरा सहयोग देते तो काम हो सकता था। इनकी तो खुद की नीयत ठीक होनी चाहिए थी कि हरियाणा की धरती पर एस0वाई0एल0 का पानी आए। यह सब कुछ हो सकता था और हो सकता है। लेकिन इनकी तो सहयोग देने की नीयत ही नहीं रही है। सिंचाई के बारे में मैं और भी कहना चाहता हूं, वित्तमंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं जिन्होंने बजट में नहरों के लिए काफी फण्ड एलाट किए हैं, फिर भी मेरा इनसे अनुरोध है कि टेल तक पानी पहुंचाने के लिए, नहरों की खुदवाई के लिए और फण्ड दें ताकि टेल तक पानी पहुंच सके। बाढ़ के वक्त भी फसलें नष्ट हो जाती हैं, इसलिए ड्रेनों की खुदवाई के लिए भी ये फण्ड दें। चेयरमैन महोदया, पिछले दिनों निगटू में मुख्यमंत्री जी ने अनाज मण्डी का शिलान्यास किया है, मगर वहां पर ड्रेन नहीं है। अगर ड्रेन नहीं बनी तो वहां पर रखी फसल का काफी नुकसान हो सकता है, व्यापारी भी वहां पर नहीं बैठ सकते हैं। इसलिए मेरा इनसे अनुरोध है कि निगटू से पुण्डरी तक ड्रेन ले जाएं।

चेयरमैन साहिबा, बिजली मंत्री भी यहां पर बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने सोच-समझकर एक योग्य व्यक्ति को यह महकमा दिया है। (विघ्न) इनका इस बारे में पहले भी तजर्बा है और उनमें योग्यता भी है। इन्होंने जब से इस कार्यभार को सम्भाला है तो इनका ज्यादा से ज्यादा प्रयास यही रहा है कि सबको बिजली मिले, विशेषकर किसानों को ज्यादा से ज्यादा बिजली मिले। (विघ्न) किसानों को

[श्री जय सिंह राणा]

बिजली मिली भी है। मेरा बिजली मंत्री जी से भी अनुरोध है कि मेरे हल्के में दो सब-स्टेशन्ज ऐसे हैं जो 33 के.वी. के हैं, उनको तो 132 के.वी. का बनाने का काम कुछ तो हो चुका है और कुछ पड़ा हुआ है। हमारा जीरी और पैडी का सीजन आ रहा है, इसके शुरु होने से पहले ही 132 के0वी0 का सब-स्टेशन बनाने का कार्य कर दें ताकि किसानों के ट्यूब-वैल्ज को बिजली मिल सके। चेयरमैन महोदया, कृषि के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जब से यह सरकार आई है तो कृषि के क्षेत्र में किसानों को ठीक भाव मिले हैं, अच्छी फसलें हुई हैं। मैं भी खुद किसान हूं, खेती के अलावा मैंने कोई दूसरा काम ही नहीं किया है। मेरा खेती का ही काम है। (विघ्न) चेयरमैन महोदया, लोग तो गुमराह भी करते हैं।

श्री सभापति : राणा जी, आप लोग आपस में बात न करें और आप जल्दी ही वाईडअप करें।

श्री जय सिंह राणा : जहां तक किसानों की आर्थिक स्थिति का सवाल है, चार साल में फसलों के भाव की वजह से और अच्छी फसल होने की वजह से आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। मार्केटिंग बोर्ड ने भी किसानों को राहत पहुंचाने के लिए काफी कार्य किए हैं, जैसे सड़कों का काम ही मार्केटिंग बोर्ड ने काफी किया है। किसानों की फसलों को मंडी तक लाने के लिए जो रास्ता बनाने का काम मार्केटिंग बोर्ड ने किया है वह बहुत सराहनीय है। इस बोर्ड ने ऐसे ऐसे रास्ते बनाए हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था लेकिन मार्केटिंग बोर्ड ने उन रास्तों को बनाकर किसानों को सुविधा पहुंचाई है। आज किसान भी इस बात को मानते हैं। लेकिन मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि अब भी काफी रास्ते ऐसे हैं जिनमें किसान अपनी फसल तो क्या, पशुओं के लिए चारा भी नहीं ला सकते हैं, इसलिए ऐसे रास्तों को भी सरकार को बनाना चाहिए। जिन मार्केट कमेटियों में अपने फंड हैं, वे किसानों की भलाई के लिए ही हैं इसलिए इस पैसे को किसानों की भलाई में लाने के लिए किसी किस्म की देरी नहीं करनी चाहिए और उस काम को पूरा करना चाहिए। यह मेरा एक सरकार को सुझाव है (विघ्न)

चेयरमैन साहिबा, अब मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने बड़े भारी कार्य किए हैं। मैं पिछली बार भी इस सदन का सदस्य था इसलिए मुझे पूरा पता है कि जब यह वर्तमान सरकार आयी थी तो उस समय हर तरह के स्कूलों में हर कैटेगरी के टीचर्ज के खाली पद पड़े थे जिनको भरने की कोशिश पिछली सरकार ने नहीं की थी। मुझे पता नहीं कि उसका क्या कारण रहा होगा। उसका कारण तो ये स्वयं ही जानते होंगे। लेकिन वर्तमान सरकार आने के बाद चौधरी भजनलाल जी ने जब इस प्रदेश की बागडोर संभाली तो उसके बाद बहुत से खाली पदों को भरा है और बाकी भी जो खाली पद पड़े हुए हैं उनको भी भरने की कोशिश की जा रही है। यह कोई छोटी बात नहीं है क्योंकि यह तो बहुत बड़ा

कार्य है । खासतौर पर देहातों के स्कूलों में तो टीचर्ज के पद बिल्कुल ही खाली पड़े थे जहां दस टीचर होने चाहिए थे तो वहां पर दो ही मिलते थे । इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने कन्याओं के लिए बी०ए० तक की शिक्षा मुफ्त की है । चेयरमैन साहिबा, यह बहुत बड़ा निर्णय इस सरकार ने लिया है। ऐसा करने से शिक्षा का बहुत प्रसार होगा । मैं सरकार से यह भी चाहूंगा कि दस जमा दो स्कूलों की आज बड़ी जरूरत है । मेरे अपने हल्के में ही नीलोखेड़ी और तरावड़ी दो बड़े कस्बे हैं । वहां तो स्कूल हैं लेकिन देहातों में किसी भी गांव में दस जमा दो का स्कूल नहीं हैं इससे बड़ी भारी असुविधा बच्चों को होती है क्योंकि वे दसवीं पास करने के बाद कहां जाएं । इसलिए मैं सरकार से कहूंगा कि वह ऐसा क्राईटेरिया बनाए कि देहाती क्षेत्रों में पांच किलोमीटर के अंदर अंदर कम से कम एक दस जमा दो का स्कूल जरूर खोला जाए जिससे विद्यार्थी को शिक्षा प्राप्त करने के लिए 5 कि० मी० से दूर न जाना पड़े । मैं अनुरोध करूंगा कि मेरे हल्के में शामगढ़, अमीन और तरावड़ी में एक हाई स्कूल है, उसका दर्जा बढ़ा कर 10 जमा दो का किया जाए । [घण्टी] चेयरमैन साहिबा, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद ।

चौधरी बलवन्त सिंह भावना : चैयरमैन साहिबा, मैंने अपनी बात कहनी है मुझे भी बोलने का टाइम दीजिए ।

श्री सभापति : आपको भी बोलने का समय मिलेगा ।

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल) : चेयरमैन साहिबा, हरियाणा के वित्त मन्त्री की तरफ से पिछले दिनों जो बजट प्रस्ताव रखे गए थे वह झूठ का पुलिन्दा था। हमारे माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने इस तरीके से हरियाणा के इस महान सदन में कागजों का पुलिंदा रखा जिसमें अखबारों के जरिए स्वयं भी इस बात का इजहार किया कि हरियाणा में कोई कर नहीं लगाया गया, जो सुविधाएं दिखा सकते थे, दिखाने की कोशिश की लेकिन मैं यह बात दावे से कह सकता हूं कि जब से मौजूदा सरकार ने हरियाणा के लोगों की कमान संभाली है, हरियाणा के लोगों की दिक्कतें व समस्याएं बढ़ती जा रही हैं । हरियाणा के लोगों का जीवन स्तर नीचे गिरता जा रहा है। मैंने इस सदन में बार बार एक बात कही है, आप सभी जानते हैं कि जो प्रजातन्त्र की नींव रखी गई थी, उसका जो मूलभूत सब्जैक्ट मैटर था, वह यह था कि खून का जो रिश्ता है, वह विचारों के रिश्ते से पतला है । विचारों का संबंध गाढ़ा है, खून का रिश्ता इतना गाढ़ा नहीं है । हरियाणा के लोग न जाने कितनी उम्मीदों से लोगों को, नुमाइंदों को चुनकर इस विधान सभा में भेजते हैं कि वे जाकर उनकी समस्याएं वहां उठाएंगे । लेकिन आप जानती हैं कि हरियाणा में जो नुमाइंदे हैं, खासकर सत्ताधारी पक्ष के भाई हैं, वे किस तरीके से प्रजातन्त्र का मजाक उड़ा रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री जी ने नहरों के बारे इस बजट में जिक्र किया है । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हमारे जिला फरीदाबाद के लोगों ने ऐसा क्या कसूर कर

[श्री कर्ण सिंह दलाल]

रखा है कि उनका बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता । वित्त मन्त्री जी चौथा, पांचवां बजट इस सदन में रख रहे हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं और मुख्यमन्त्री को मेरी बात बुरी लगती है । फरीदाबाद और मेवात में बिश्नोई की एक भी वोट नहीं है, वहां की जनता की तारीफ करनी पड़ेगी कि इनको वहां से संसद सदस्य चुना । हमारे जिला फरीदाबाद की और मेवात की कोई समस्या ऐसी नहीं जिसके लिए इन्होंने वायदा न किया हो ।

(इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य श्री मनी राम केहरवाला पदासीन हुए ।)

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : सभापति महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है । मैं आपके माध्यम से इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि चौधरी भजन लाल जी के नेतृत्व में पिछले चार साल में, फरीदाबाद जिले में जितना काम हुआ है, उतना तो जब से हरियाणा बना है तब से नहीं हुआ था । मुख्यमन्त्री जी पिछली 26 तारीख को मोहना ग्राम में यमुना के पुल का शिलान्यास करके आए हैं, जिसकी कास्ट 10 करोड़ रुपए है । मैं मुख्यमन्त्री जी को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं । फरीदाबाद जिले में जितना हमारा हिस्सा बनता है, इससे ज्यादा विकास के काम करवा दिए हैं, किए हुए काम के लिए धन्यवाद करना चाहिए, अहसान मानना चाहिए । आप विपक्ष के सम्मानित सदस्य हैं, विपक्ष का भी रोल बड़ा जरूरी है। जो काम इन्होंने किए हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद करना चाहिए ।

श्री कर्ण सिंह दलाल : सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से और सारे सदन से प्रार्थना करता हूं कि बजट में जो एस0 वाई0एल0 नहर का जिक्र हुआ है, एस0 वाई0 एल0 हमारे जिला फरीदाबाद की किसी नहर के माध्यम से नहीं जाएगी । हमारे फरीदाबाद और मेवात एरिया को किसी नहर से अगर फायदा होगा तो वह आगरा नहर से होगा । सभापति महोदय, मुझे इतना दुःख है कि जो बजट इन्होंने पेश किया है उसमें इन्होंने नहरों का जिक्र किया है लेकिन हमारे मेवात और फरीदाबाद इलाके की जितनी नहरें हैं, वे सारी की सारी सूखी पड़ी हैं। अगर सरकार इस इलाके के प्रति चिंतित हो तो क्यों न इस इलाके की बहबूदी के लिये पैसा खर्च करे लेकिन सरकार का इस ओर ध्यान ही नहीं है यह भी पता चला है कि यू0 पी0 सरकार तो आगरा कनाल का नियन्त्रण हरियाणा को देना चाहती है लेकिन हरियाणा सरकार इसके लिये इच्छुक नहीं है (शोर) हरियाणा सरकार ही आगरा कैनाल का प्रबन्ध अपने हाथ में नहीं लेना चाहती । सारे का सारा पैसा हिसार, सिरसा और खासतौर से आदमपुर में ही सरकार खर्च कर रही है । दूसरे इलाकों के बारे में सरकार चिंतित नहीं है ।

सिंचाई मन्त्री (चौधरी जगदीश नेहरा) : चेयरमैन महोदय, दलाल साहब यूंही इधर उधर की बातें कह कर हाउस को मिस-लीड कर रहे है कि हरियाणा सरकार

आगरा कैनाल का नियन्त्रण अपने हाथ में नहीं लेना चाहती और यू. पी. सरकार हमें इसका नियन्त्रण देना चाहती है। आगरा कैनाल का नियन्त्रण हमारे हाथ में आए, इस बारे में 1975 में मीटिंग हुई, और उनका उत्तर भी मैंने इनको पढ़ कर सुनाया था। उसके बाद फिर 1988 में मीटिंग हुई, फिर 1989 में हुई, और फिर मुख्य मन्त्री की 1992 में मीटिंग हुई। हम तो लगातार यह कोशिश करते रहे हैं कि आगरा कैनाल का प्रबन्ध हरियाणा सरकार के पास आ जाए तो फिर ये किस आधार पर यह कह रहे हैं कि हम आगरा कैनाल का प्रबन्ध लेने में इच्छुक नहीं है। यह सब निराधार बातें हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : चेयरमैन साहब, मैं आपके माध्यम से मुख्यमन्त्री महोदय, वित्तमन्त्री व सिंचाई मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि अगर वे सचमुच में फरीदाबाद के इलाके के साथ सहानुभूति रखते हैं तो आगरा कैनाल का नियन्त्रण अपने हाथ में ले कर के हमारे इस इलाके के किसानों के खेतों को पानी दिलवाने की व्यवस्था करें ताकि किसानों को थोड़ी सी राहत मिल सके। उस आगरा कैनाल का पानी हमारे सामने से हमारी छाती से होकर गुजरता है, हमारा किसान बेचारा सामने खड़ा देखता रहता है लेकिन हमें उस पानी को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। किसानों के खेत इस पानी के बगैर सूख रहे हैं। जब तक हमारी सरकार इस आगरा कैनाल का नियन्त्रण अपने हाथ में नहीं लेती तब तक इस इलाके का विकास नहीं हो सकता। मैं एक बात और बताता हूं कि हमारे इलाके में होडल व हसनपुर डिस्ट्रीब्यूट्रीज हैं और जो अधिकारी इनसे सम्बन्धित हैं, वे दोनों एक्सीयन व एस0-डी0 ओ0 मथुरा में बैठते हैं और लोगों को अपनी प्रोब्लमज के लिए मथुरा जाना पड़ता है।

चौधरी जगदीश नेहरा : ये दोनों डिस्ट्रीब्यूट्रीज आधी उधर पड़ती हैं इसलिये वे वहां बैठते हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : मैं आपको बताता हूं कि गुड़गांव कैनाल की पानी की कपैसिटी इस समय 2,240 क्यूसिकस की है, जोकि फरीदाबाद के एरिया को भी फीड करती है और इस समय वहां पर केवल 300 क्यूसिकस पानी ही चल रहा है, उसमें से भी 100 क्यूसिकस पानी थर्मल प्लांट को चला जाता है। इतनी बुरी हालत है। इस को देखकर सरकार खुद ही अन्दाजा लगा सकती है कि हमारे फरीदाबाद जिले के साथ कितना भेदभाव हो रहा है। वहां के किसानों के खेतों के लिये पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा है, जिस के कारण किसान बुरी तरह से दुखी है।

इसके साथ मैं सरकार से यह भी कहूंगा कि आगरा कैनाल और गुड़गांव कैनाल की जो डिस्ट्रीब्यूट्रीज हैं, उन पर जो पुल बने हुए हैं, उनकी मुरम्मत की भी आवश्यकता है। धतीर डिस्ट्रीब्यूट्री मेरे हल्के में है और वहां से जो चान्दपुर सब-माईनर के लिये स्कीम इन्होंने बनाई है, वह एक लिफ्ट इरीगेशन की स्कीम है। वहां से जब बिजली चली जाती है तो पानी पीछे की ओर धक्का मारता है जिससे सिकन्दरपुर

[श्री कर्ण सिंह दलाल]

गांव में पानी भर जाता है और वह गांव डूब जाता है । हरिजनों के वहां पर हजारों गांव हैं । वे बेचारे बनाते रहते हैं और उस डिस्ट्रीब्यूट्री का पानी उन्हें डूबो देता है मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार चैनल बनाकर उस पानी को गोछी ड्रेन में डाल दे ताकि वहां के लोग इस पानी के खतरे से बच सकें । इससे बड़ेर का जो इलाका है, उसको भी पानी मिल जाएगा ।

इसके बाद मैं चेयरमैन साहिब वित्त मन्त्री महोदय को यह कहूंगा कि यहां पर पंचायत संस्थाओं का भी जिक्र आया । रोजाना इस बारे में बड़े लेख आते रहते हैं कि जो पैसा पंचायत के लिये सरकार से चलता है, वह सही जगह पर नहीं पहुंचता क्योंकि उसका बांटने का अधिकार ए० डी० सीज० व डी० सीज० को सरकार ने दे रखा है । मेरा सुझाव है कि क्यों न उस पैसे को सीधा ही पंचायतों को देने की सरकार व्यवस्था करे ताकि वह पैसा ठीक समय पर पंचायतों के पास पहुच सके और उस का सदुपयोग हो सके । वहां पर एक ए० डी० सी० का आफिस या ब्लाक का दफ्तर है । हो सकता है कि वे एक काम पर एक लाख रुपए लगा दें, और उसी काम को पंचायत 50-60 हजार रुपए में कर दे । अखबारों में रोज लिखा होता है कि अगर एक रुपया यहां से चलता है तो वह पहुंचते पहुंचते 15 पैसे रह जाते हैं । तो इसी तरीके से यहां पर एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि फरीदाबाद का बहुत विकास हुआ है । पिछले दिन से ले कर आज तक आठ हजार सिपाहियों की भर्ती हो चुकी है लेकिन हमने आज तक किसी मुख्यालय में भर्ती होती नहीं देखी । (विघ्न) चेयरमैन साहब, मेरा आपसे अनुरोध है कि पिछले दिनों महेन्द्रगढ़, के इलाके को बिजली के मामले में सुविधा दी जाती थी । वहां पर पानी बहुत नीचे है इसलिए इन्होंने वहां के लिए बिजली की दरों में रियायत की घोषणा की थी । सुना है अब ये उस रियायत को बन्द करने जा रहे हैं । अगर ऐसी बात है तो यह गल्त बात है । हमारे बिजली मन्त्री हमारे पूरे इलाके को नहीं जानते । हमारे बुड़ेल के इलाके में पानी नहीं है । जो खादर का इलाका है उसमें जल स्तर बहुत नीचा है । मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारे इलाके में रहने वाले किसानों के लिए भी बिजली की रियायती दरों की घोषणा करें । बुड़ेल में रहने वाले किसानों की एक ही फसल होती है । एक फसल से वे बिजली के बिलों का भुगतान नहीं कर सकते हैं । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस बारे में उनके लिए भी सरकार गौर करे । चेयरमैन साहब, हमारे फरीदाबाद जिले में एक होडल शहर है । उसके साथ यू० पी० का एक कोसी शहर है । आप वहां जा कर देखें या सरकारी अधिकारियों को भेज कर पता करवाएं कि कितने उद्योग वहां पर लग रहे हैं । इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार भी उत्तर प्रदेश की तरह रियायत दे कर होडल में उद्योग लगवाएं । अगर सरकार रियायत देगी तो इंडस्ट्रियलिस्टस कोसी की बजाए होडल में अपने उद्योग लगाएंगे । इसी तरीके से चेयरमैन साहब, मैं आपके द्वारा सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस हरियाणा के खजाने पर सारे हरियाणा

की जनता का हक है लेकिन आज जो विकास के काम हो रहे हैं वे चुने हुए क्षेत्रों में ही हो रहे हैं । हमारे फरीदाबाद में कोई गवर्नमैंट टैक्नीकल एजूकेशन का सैंटर नहीं है, हमारा इतना बड़ा जिला है लेकिन वहां पर कोई ऐसा हस्पताल नहीं है जहां हमारे लोग ठीक तरह से ईलाज करवा सकें । वहां पर एक बादशाह खां हस्पताल है लेकिन अगर आप वहां जाते हैं तो क्या आपको उचित दवाइयां मिलती हैं ? उचित दवाइयां बिल्कुल नहीं मिलतीं । चेयरमैन साहब, इसी तरीके से हमारे पलवल का जो शूगर मिल है, पिछले से पिछले साल उसका 50 लाख रुपया भूना शूगर मिल को दे दिया गया । चेयरमैन साहब, दो साल गुजर चुके हैं उस पैसे का कहीं कोई जिक्र नहीं है । मैं मुख्य मंत्री जी से और वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जो भूना में आपने 50 लाख रुपया भेज दिया है वह वापिस आना चाहिए ।

श्री सभापति : वह सारा पैसा फार्मर्ज की भलाई के लिए है । जितना पैसा हरकों बैंक से जा रहा है वह सारा फार्मर्ज की भलाई के लिए जा रहा है । किसी दूसरे काम के लिए नहीं जा रहा है । यह बात प्रोसिडिंग्ज में भी है ।

श्री कर्ण सिंह दलाल : चेयरमैन साहब, पलवल की अनाज मंडी एक मानी हुई अनाज मंडी है । वह सारे हरियाणा प्रदेश में एक सबसे बड़ी जानीमानी अनाज मंडी मानी जाती है । उस मंडी का जितना पैसा इकट्ठा होता है वह सारा पैसा वहां से दूसरी जगह पर ले जा कर खर्च कर देते हैं । पलवल मार्किट कमेटी ने पिछले तीन चार साल में वहां पर एक भी पैसा खर्च नहीं किया है । अगर किया है तो फरीदाबाद जिले के जो दूसरे मैम्बर हैं वह बता दें । (विघ्न)

श्री सभापति : दलाल साहब, आपका टाईम समाप्त हो गया आप बैठ जाएं ।

श्री कर्ण सिंह दलाल : चेयरमैन साहब, मुझे आप दो मिनट का टाईम और दे दें ।

श्री सभापति : नहीं, अब आप बैठिए । अब श्री बलवंत सिंह जी बोलेंगे । (शोर)

वाक आउट

श्री कर्ण सिंह दलाल : चेयरमैन साहब, आप मेरी बात सुनने की कृपा करें । (शोर)

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : चेयरमैन साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि दलाल साहब पलवल हल्के से विधायक हैं इसलिए इनको पलवल हल्के तक ही सीमित रहना चाहिए, इनको सारे फरीदाबाद जिले का ठेका नहीं लेना चाहिए । वैसे ये मेरे छोटे भाई हैं, उस नाते से मैं इनको सुझाव देना चाहूंगा कि जो धर्मेन्द्र कुमार एक्टर है उनसे इनकी शक्ल मिलती जुलती है इसलिए ये फिल्म इंडस्ट्रीज में चले जाएं और वहां जा कर एक्टिंग करें । (हंसी)

श्री कर्ण सिंह दलाल : चेयरमैन साहब, आप मुझे बोलने के लिए एक मिनट का टाईम दे दें ताकि मैं अपनी स्पीच वाईड-अप कर सकूं । (शोर)

श्री सभापति : दलाल साहब आप कृपा करके बैठ जाएं । अब श्री बलवंत सिंह मैना बोलेंगे ।

श्री कर्ण सिंह दलाल : चेयरमैन साहब, अगर आप मुझे बोलने के लिए समय नहीं दे रहे हैं तो हम एज ए प्रोटैस्ट सदन से वाक आउट करते हैं ।

(इस समय हरियाणा विकास पार्टी के उपस्थित माननीय सदस्य सदन से उठ कर बाहर चले गए ।)

वर्ष 1995-96 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

चौधरी बलवंत सिंह मायना (हसनगढ़) : चेयरमैन साहब, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया । माननीय वित्त मंत्री श्री मांगे राम गुप्ता जी ने 13 तारीख को जो बजट पेश किया है, मैं उसके विरोध में बोलते हुए कुछ कहना चाहूंगा । मुझे एक बात याद आ गई । हमारे वित्त मंत्री श्री मांगे राम गुप्ता जी ने माननीय सदस्य श्री राम कुमार कटवाल की बुआ के पास बैठ कर यह बजट तैयार किया है इसलिए इन्होंने सिन्दूर, मंगलसूत्र और चूड़ियों पर टैक्स माफ कर दिया । इन्होंने यह नहीं सोचा कि हरियाणा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है, इसलिए हरियाणा प्रदेश के किसानों को टैक्स में राहत दी जाए । हरियाणा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश होते हुए भी इन्होंने किसानों को पानी देने के लिए पैसे का पूरा प्रावधान नहीं किया । जैसे एस0 वाई0 एल0 नहर की बात करते हैं । आज हमें एस0 वाई0 एल0 नहर के बारे में चर्चा करते हुए पौने चार साल हो चुके हैं और उसकी हर बजट सैशन में बात उठती है तो सरकार की तरफ से जवाब दिया जाता है कि उसको 6 महीने के अन्दर पूरा किया जाएगा । इस बजट में इस सरकार ने एस0 वाई0 एल0 नहर के लिए 16.66 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है । इस पैसे के बारे में मैं यह कहता हूं कि यह तो ऊंट के मुंह में जीरा डालने वाली बात है, इतने पैसे से एस0 वाई0 एल0 नहर बनने वाली नहीं है । भाखड़ा नहर की सफाई के लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्य मंत्री थे, उन्होंने इसकी पटरी बनाने के लिए और गाद निकालने के लिए 1 करोड़ 90 लाख रुपये रखे थे । इस सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया जिस वजह से ये वहां से अपना पूरा पानी इस भाखड़ा नहर में नहीं ला सके । हरियाणा प्रदेश के अन्दर रोहतक जिला है, डब्ल्यू0 जे0 सी0 का पानी उसमें आता है । इस डब्ल्यू0 जे0 सी0 की हालत बहुत ही खराब है क्योंकि उसमें बहुत अधिक गाद भरी हुई है । गाद भरे होने के कारण उसमें पूरा पानी कभी भी नहीं आ पाता । अब मेरी प्रार्थना है कि वर्ल्ड बैंक से जो पैसा

आया है, उससे इसकी सफाई कराई जाये। हमारे वहां पर जे0 एल0 एन0 और जे0 एस0 बी0 साथ साथ चलती है। उनमें भी रेती और गाद भरी हुई है। इसी प्रकार से वहां पर चाहे दुरेहड़ा, सुसाना या भालोट माईनर हैं, सब में रेती भरी हुई है। इन की टेलों पर कभी भी पानी नहीं जाता। हर सैशन में मैं इसकी आवाज उठाता हूं और हर बार सवाल करता हूं, क्वैश्चन लगता है, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। मैं सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं कि हसनगढ़ के जोहड़ में पानी डालने के लिए भी पानी नहीं मिला, आबपाशी की तो बात ही छोड़िए। इसी प्रकार से पीने का पानी भी नहीं जाता। कसरेहटी में पीने का पानी कभी नहीं जाता। आज रोहतक में जे0 एस0 बी0 और जे0 एल0 एन0 पैरलल चलती है, वहां पर इनकी सीपेज की वजह से 20 हजार एकड़ रकबा खराब हो चुका है और किसान बर्बाद हो चुके हैं। कारण यह है कि झज्जर सब-ब्रांच में मिट्टी भरी हुई है। मोरियां जो बनी हुई हैं, वे पहले की हैं और रेत से वे दब चुकी हैं जिसके कारण पानी की कैपेसिटी कम हो गई है मैं कह रहा था कि वहां पर सीपेज की वजह से किसानों की 20 हजार एकड़ का रकबा खराब हो चुका है, उसकी तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही। नेहरा साहब जब ब्रिवेंसिज कमेटी की मीटिंग में जाते हैं तो उस समय भी यह मामला उनके साथ उठाया जाता है। डिच ड्रेन बनाने की बात कई बार आई लेकिन नहीं बनाई जा रही। नेहरा साहब अपने हल्के में पूरे जोर शोर से डिच ड्रेन बना रहे हैं लेकिन रोहतक जिले की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। इससे साफ पता चलता है कि सरकार रोहतक जिले के साथ भेदभाव कर रही है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वर्ल्ड बैंक से जो पैसा आया है, उससे सभी हरियाणा की नहरों की, माइनरों की और नालों की गाद निकाली जाये ताकि हरियाणा की चप्पा-चप्पा जमीन को पानी मिल सके। हरियाणा सरकार ने अपने बजट में से तो इस काम के लिए कोई पैसा नहीं रखा। लेकिन वर्ल्ड बैंक से जो पैसा इस काम के लिए आया है, मेरा अनुरोध है कि जिन किसानों का 20 हजार एकड़ का रकबा सीपेज की वजह से खराब हो चुका है और किसान अपना रकबा बोने से महरूम हो जाते हैं, सरकार उसका एक सर्वे करवाये और जितने भी गांव इस सीपेज के अन्दर आते हैं, उनकी फसल का मुआवजा सरकार दे। चेयरमैन साहब, ओलावृष्टि से किसानों की जो फसल बरबाद होती है, वह कुछ परसैंट ही होती है, लेकिन इन बेचारे किसानों की तो पूरी फसल बोई ही नहीं जाती। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि इन बेचारे किसानों की क्या गलती है जो सरकार ने आज तक उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। चौधरी भजन लाल जी तो किसानों के बड़े हितैशी बनते हैं। अगर ये उनके हितैशी बनते हैं तो उनके हित की बात की तरफ तो ध्यान दें जो डिच नहर बनाई जानी है, वह बनाई जाए ताकि जो पानी वहां पर खड़ा है उसको निकलवाने का प्रबन्ध किया जाए। चेयरमैन साहब, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहूंगा कि यह पानी कब तक निकलवा देंगे और किसानों को फसल के नुकसान का कितना मुआवजा देंगे और कब तक

[चौधरी बलवंत सिंह मायना]

देंगे ? इस बारे में ये हाउस में आश्वासन दें । सिंचाई के बारे में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि भालौठ माईनर, सिसाना माईनर और दुल्हेड़ा माईनरज की तरफ भी ध्यान दें ।

चेयरमैन सर, अब मैं शिक्षा की बात कहना चाहता हूं । शिक्षा मन्त्री जी ने कहा कि हमने नकल को रोकने के लिए पग उठाए हैं । हम इस बात को मानते हैं कि नकल को कुछ हद तक रोका भी है, लेकिन ग्रामीण शिक्षा की ओर सरकार ध्यान नहीं दे रही है । गांवों के अन्दर 10 जमा 2 के स्कूल्ज़ हैं, उनका रिजल्ट बहुत ही पूवर रहा है । ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों के स्कूल फेल हो गए हैं । साम्पला गवर्नमैंट हाई स्कूल के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि वहां का एक आध बच्चा पास हुआ हो तो अलग बात है, पूरे के पूरे स्कूल में एक भी विद्यार्थी पास नहीं हुआ । जहां तक मैं समझता हूं इसका एक कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में जो अध्यापक हैं, वे पूरे नहीं हैं कहीं पर साईंस टीचर नहीं, कहीं पर गणित का टीचर नहीं है और कहीं पर अंग्रेजी का टीचर नहीं है । दूसरा इसका जो कारण मैं समझता हूं वह यह है कि गांवों में अच्छे अध्यापकों को भेजा नहीं जाता । इस मामले में गांवों के साथ भेदभाव किया जाता है । गांवों के स्कूलों की हालत बहुत ही बुरी है । मैंने पिछले सैशन में अपने हल्के के अटायल गांव के स्कूल की छत के बारे में बताया था कि उसकी छत गिरने वाली है और मुझे यहां पर यह आश्वासन दिया गया था कि बरसात से पहले उसकी मुरम्मत करवा दी जाएगी लेकिन बड़े शर्म की बात है कि इस स्कूल की छत पर अभी तक किसी ने गौर तक नहीं किया है । उस छत के नीचे न तो कोई बच्चा और न ही कोई अध्यापक बैठ सकता है (घण्टी) चेयरमैन साहब, अगर इस प्रकार की हालत गांवों के स्कूलों में होगी तो बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिल पाएगी । इसी तरह से कलावड़ गांव मेरे हल्के में पड़ता है । इस गांव में दस जमा दो का लड़कियों का स्कूल है । इस स्कूल के पीछे एक जौहड़ है जिसका पानी बरसात होने के कारण स्कूल की दीवारों तक आ गया है । सीलन होने के कारण उसकी छत गिरने तक की नौबत आ गई है । इस बारे में किसी ने कोई सुनवाई नहीं की तालाब का पानी बाउंडरी-वाल तक लग रहा है । लोगों की यह मांग है कि इस पानी को सरकार निकलवाए । गांव वाले मुझ से कहते हैं कि अगर सरकार पानी निकलवा देगी तो ठीक बात है, बड़ी मुश्किल से स्कूल की बिल्डिंग बनी है, अगर पानी नहीं निकला तो वह गिर सकती है । गांव वालों का यह भी कहना है कि अगर पानी निकलवा दिया जाए तो वे जौहड़ को अपने खर्चे पर अपने तरीके से खुदवा लेंगे और दीवार के साथ पुश्त करवा देंगे ताकि यह समस्या खत्म हो सके । इसके साथ ही गांव की कुरड़ियों का पानी गांव के अन्दर फैला हुआ है, जिसके कारण बदबू उठती है और बच्चों को कई बीमारियां हो रही हैं । इस बारे में ये बताएं कि इस पानी को कब तक निकलवा देंगे ? नकल रोकने में कुछ काम हुआ है और हम इसको मानते भी हैं । शिक्षा के अन्दर नकल रोकने की

आज बात हो रही है और नकल रोकने वालों को इनाम दिये जा रहे हैं । पहले मिनिस्टर साहिबान तो चाहती थीं कि नकल बन्द हो जाए । लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी की नाक के नीचे नकल को रोकने के लिए शीला बहन का उनके घर में ही मर्डर कर दिया जाता है और मर्डर करने के बाद उसको नहर में फैंक दिया जाता है ।

सभापति महोदय, 1966 से शहरों के अन्दर अध्यापकों को मकान भत्ता मिलता था । आज इस सरकार ने वह भी बन्द कर दिया है बल्कि यहां तक कर दिया कि जो चिट्ठी उनको लिखी गई है, उसमें यह लिखा है कि जो पिछले चार साल भत्ता लिया है, वह भी वापिस दिया जाए । सभापति महोदय, मकान मालिक तो किराया ले गया है, अब अगर वह अध्यापक अपनी तनख्वाह से वह पैसे भी देगा तो वह गरीब अध्यापक क्या करेगा ? इसलिए सरकार को इस फैसले को भी वापिस लेना चाहिए ।

इसी तरह से सांपला गांव है । वहां पर पी0 एच0 सी0 है और डाक्टर वहीं पर नहीं रहता है क्योंकि रोहतक वहां से 25 किलोमीटर पड़ता है । अगर किसी को चोट भी लग जाए तो वहां पर पट्टी करने का सामान तक नहीं मिलता है, सिर दर्द हो तो गोली भी नहीं मिलती है । इसी तरह से बलियाना में भी कोई नहीं होता । मेरे कहने का मतलब है जहां पर पी0 एच0 सी0 और सी0 एच0 सी0 हैं, वहां दवाईयां मिलनी चाहिए । वैसे इस सरकार का दिल नहीं है कि वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था की जाए । (इस समय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए ।)

अध्यक्ष महोदय, अब मैं सड़कों के बारे में कहना चाहूंगा । सड़कों की बहुत ही बुरी हालत है । मैं अपने हल्के की बात कहूंगा । सांपला से लेकर डीगल तक, सांपला से लेकर अटायल, सीमली से कालहोरा और मसूड़ से मोरखेड़ी तक चारों तरफ सड़कें टूटी पड़ी हैं । उन पर कोई भी आ-जा नहीं सकता है । मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि हमने सब सड़कों की मरम्मत कर दी है और इस बारे में अमर सिंह जी ने भी दावा किया है । अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले सैशन में हसनगढ़ से लेकर खेरनपुर तक सड़क बनाने के लिए कहा था और बालंद से करोंथा तक भी कहा था, लेकिन आज इनको चार साल हो गए हैं, वहां पर एक टोकरी मिट्टी भी किसी ने नहीं डाली है और वहां पर कुछ काम ही नहीं हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं बसों के बारे में कहता हूं । इन्होंने 363 नई बसें खरीदीं और उस पर 25 प्रतिशत ज्यादा किराया लगा दिया । यह सब सरकार के लिए पैसा कमाने का तरीका है । उन बसिज में न कोई पुलिस का कर्मचारी, न पास वाले बैठ सकते हैं और न ही आम आदमी बैठ सकता है । सरकार को उन बसिज में कर्मचारियों को, पुलिस के कर्मचारियों को और पास वालों को अलाऊ करें । इस बारे में सरकार को चाहिए कि उन बसिज में भी आम आदमियों को बैठने की सुविधा मिल सके ।

[चौधरी बलबंत सिंह भायना]

इसी प्रकार से वाटर वर्क्स के बारे में भी मैं कहना चाहूंगा । सर, मैंने 13.00 बजे पहले भी कहा था कि वाटर वर्क्स की बहुत बुरी हालत है । हसनगढ़ गांव में पीने का पानी नहीं जाता । इसी तरह से किसरैदी, नवाबास, अटायल, खेड़ी सांपला, खरावड़, रटौली और करौथा गांवों में भी पीने का पानी नहीं जाता है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि जहां भी ट्यूबवैल का प्रावधान हो तो वहां पर सरकार को जरूर इसका प्रावधान करना चाहिए, ताकि लोगों को उन गांवों में पीने का पानी मिल जाए । स्पीकर सर, इसके अलावा मैं बिजली के बारे में भी कहना चाहूंगा क्योंकि माननीय बिजली मंत्री यहां पर बैठे हुए हैं । आज इन्होंने बिजली के रेट तो बढ़ा दिए । कभी तो ये बिजली के रेट दो रुपये से दस रुपये और कभी दुकानदार के दो रुपये से चालीस रुपये और कभी 65 रु० प्रति हार्स पावर मोटर के हिसाब से बढ़ा देते हैं, लेकिन फिर भी बिजली समय के मुताबिक लोगों को नहीं मिलती है । जब लोग सो जाते हैं तब जाकर बिजली आती है जिसके कारण पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती और जब लोग सुबह सोकर उठते हैं तो उससे पहले ही बिजली गायब हो जाती है । मैं मंत्री जी से एक बात जानना चाहूंगा कि मेरे हल्के के सिमप्ली गांव में एक बहुत पुराना ट्रांसफार्मर है । उस गांव की आबादी आज चौगुनी बढ़ चुकी है लेकिन फिर भी आज तक वहां दूसरा ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया । इसी तरह से रटौली गांव के रणधीर सिंह को अपना ट्यूबवैल लगाने के लिए कनैक्शन की जरूरत थी लेकिन चार साल से उसको बिजली का कनैक्शन नहीं मिल पाया । कनैक्शन लेने के लिए उसके ट्यूबवैल का फासला केवल पांच फुट का है । लेकिन उसको इन्होंने कनैक्शन नहीं दिया है तो स्पीकर सर, यह तो स्थिति बिजली के बारे में है । मैं इनको एक बात बताना चाहूंगा वैसे तो यह मजाक की बात है । एक डाक्टर ऐसा था कि उसको आता जाता कुछ नहीं था । एक बार कोई आदमी डाक्टर के पास गया और उससे कहने लगा कि मेरे पेट में दर्द है तो वह डाक्टर उससे कहने लगा कि तू कपड़े उतारकर कमरे में अन्दर जाकर बैठ जा । जब दूसरा आदमी उसके पास आया और उसने उस डाक्टर से कहा कि मेरे सिर में दर्द है तो उसने उस आदमी से भी कहा कि तू भी अपने कपड़े उतारकर कमरे में अंदर जाकर बैठ जा । इसी तरह से जब तीसरा आदमी उस डाक्टर के पास आकर कहने लगा कि मेरे माथे में दर्द है तो उसने उस आदमी से भी यही कहा । जब वे तीनों अंदर जाकर बैठ गए तो वे कहने लगे कि यह कैसा डाक्टर है जो सभी को एक ही तरह से कहता है । जब उन तीनों ने देखा कि वहां पर पहले से ही एक और आदमी टेबल के नीचे बैठा हुआ है तो उन्होंने उससे पूछा कि तू यहां क्यों बैठा है तो वह कहने लगा कि मैं तो बिजली का बिल जमा करने आया था लेकिन इस डाक्टर ने मुझसे कहा कि तू अपने कपड़े उतारकर अंदर कमरे में जाकर बैठ जा । तो स्पीकर सर, यही हाल इस सरकार का है, यह लोगों से झूठे वायदे करती है । (विघ्न) सर, मैं इस पूरे बजट का विरोध करता हूं । यह

सारा बजट किसान विरोधी है तथा हरियाणा की जनता के विरुद्ध है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हुआ आपका धन्यवाद करता हूं ।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो बजट का जवाब वित्त मंत्री जी ने देना है लेकिन कुछ प्वायंट ऐसे हैं जिनके बारे में क्लैरिफाई करना जरूरी है । अध्यक्ष महोदय, बजट पर बहस में हिस्सा लेते हुए कुछ सदस्यों ने कुछ प्वायंट रेज किए हैं उनके बारे में मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं । सबसे पहले तो मैं ओम प्रकाश चौटाला जी के द्वारा उठाए गए प्वायंट के बारे में कहना चाहूंगा । उन्होंने कहा कि देश की गलत नीतियों की वजह से, गलत पोलिसीज की वजह से साउथ में कांग्रेस हार गयी है । वे आज इस सदन में नहीं है जबकि उनको आज होना चाहिए था, लेकिन किसी काम से शायद चले गए होंगे । लेकिन उनकी पार्टी के अपोजीशन के लीडर्ज यहां बैठे हैं । मैं उनको बताना चाहूंगा कि जब चौधरी देवी लाल हार गए थे तो उस समय ऐसी कौन सी पोलिसी या नीति थी वह कैसे हार गए । अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं कि प्रजातंत्र में हार जीत तो लगी ही रहती है लेकिन जहां तक देश की नीतियों का ताल्लुक है, पिछले चार साल में इस देश का नाम संसार में ऊंचा ही हुआ है, चाहे वह विदेश नीति हो, चाहे वह उद्योग नीति हो चाहे वह किसानों के लिए अच्छा भाव देने की बात हो चाहे खाद पर सबसिडी देने की बात हो, हर लिहाज से इस देश का नाम प्रधानमंत्री की रहनुमाई में ऊंचा हुआ है । इस बारे में जितनी बार भी बधाई दें उतनी थोड़ी है । आप बाहर जाकर देखें । बाहर की कंट्रीज के लोग हिंदुस्तान की बहुत तारीफ करते हैं, कितनी शानदार इकोनोमी ठीक हुई है । अगर हमारे मुल्क की इकोनोमी ठीक नहीं होती तो बाहर के देशों में हमारे देश की कदर कम हो जाती । रशिया जैसा मुल्क, बहादुर मुल्क टूट गया, 15 टुकड़े हो गए । अगर समय पर देश की इकोनोमी ठीक न होती तो हिंदुस्तान की भी रशिया से बुरी हालत हो सकती थी । तारीफ करने की बजाय ओम प्रकाश चौटाला जी ने गलत नीतियों की वजह से क्रीटीसाइज किया है । स्टेट के मामले में, स्टेट सब्जैक्ट्स के आधार पर जनता वोट देती है । अगर हमारा काम ठीक नहीं होगा तो लोग हमें वोट नहीं देंगे । साल-सवा साल के बाद चुनाव होंगे अगर हमारा काम ठीक नहीं होगा तो जनता हमारे खिलाफ जनमत देगी, काम ठीक होगा तो लोग हमें चुनेंगे । लेकिन इसका राज भी जनता खूब देख चुकी है, चौधरी बंसी लाल का राज भी देख रखा है, जनता जानती है कि किसका शासन ठीक है । जनता ने फैसला करना है । इस्तीफे की बात कहते हैं क्या किसी के कहने से इस्तीफा होता है ? यह सरकार बजट का 71 परसेंट देहात पर खर्च करने जा रही है जिसमें किसान, हरिजन, मजदूर, बैकवर्ड, नौजवान, महिलाओं सबको इसमें कवर किया है ताकि इस बजट का ज्यादातर भाग लोगों की भलाई के लिए खर्च किया जाए । अध्यक्ष महोदय, कह दिया इतना कर्जा हो गया सरकार के ऊपर । हम आएंगे तो हमें देना पड़ेगा कर्ज तुम दोगे, तुम झूठे वायदे तो कर सकते हो कि लोगों के कर्जे माफ कर देंगे । लोगों का सत्यानाश करके रख दिया । ब्याज की

[चौधरी भजन लाल]

रकम हमको माफ करनी पड़ी यह प्रदेश के लोग जानते हैं लेकिन लोगों को गुमराह करने के कोई मायने नहीं हैं । इसी तरह चौधरी बंसी लाल ने कुछ भद्दे रेज किए । एक तो कहा कि शाहबाद से किसान गन्ना पंजाब में ले जा रहे हैं और यहां के लोग रोकते हैं । 90 रुपये में पंजाब के मिल वाले गन्ना लेते हैं इस बात में कोई सच्चाई नहीं है और सच्चाई इसलिए नहीं है कि यू0 पी0 से गन्ना हरियाणा प्रदेश में आता है । जितना अच्छा भाव गन्ने का पिछले तीन साल में हरियाणा ने दिया है किसी भी राज्य ने इतना बढ़िया भाव नहीं दिया । (थम्पिंग) गन्ना बाहर ले जाने पर कोई बैन नहीं है कोई पाबन्दी नहीं है अच्छा भाव मिले तो गन्ना, गेहूं, जौरी सारे हिन्दुस्तान में कहीं भी जा सकती है कोई बैन की बात नहीं है बाहर से भी आ सकता है यहां से भी जा सकता है जहां अच्छा भाव किसान को मिले वह ले जा सकता है । इसी तरह से चौधरी बंसी लाल ने शीरे के बारे में कहा कि मौलेसिस का भाव बहुत कम है । ऐसा लगता है कि इनको अपने जमाने का भाव याद रह गया । अब जो हमने तय किया है 45 रुपये, 29 रुपये, ए, बी, सी, क्लास-I, क्लास-II, क्लास-III हमने अलग-अलग रेट तय किए हुए हैं । पहले 1992 में भाव बढ़ाया और फिर 1994 में भाव बढ़ाया ताकि भाव बढ़ने से किसानों को अच्छा दाम मिल वाले दे सकें और दूसरे, इन्होंने कह दिया कि शीरा 180 रुपये के भाव में लेते हैं, उसका भी हमने 200 रुपये भाव कर दिया है । उसमें से जो मिलों को लगता है, डिस्टीलरीज को देते हैं, जो रेट जब तय करते हैं, जिस भाव में शीरा देते हैं, उसका हिसाब लगाकर बाद में प्रूफ लीटर के पीछे क्या रेट होना चाहिए वह तय करते हैं । सारे भाव लगाकर के उसी के हिसाब से आगे ठेके नीलाम होते हैं । जब ठेके नीलाम हो जाएं तो बीच में बढ़ा नहीं सकते और आज हरियाणा प्रदेश में किसी भी मिल की तरफ किसी भी किसान का पैसा बकाया नहीं है । 15 दिनों के अन्दर-अन्दर पेमैंट करने का हमारा कायदा है । भूना मिल की एक शिकायत इस बारे में आई थी और फौरन ही दूसरी जगह के बैंक से पैसा भिजवा दिया गया ताकि किसानों को ठीक समय पर पेमैंट हो जाए ।

इसके साथ-साथ अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस वक्त हरियाणा के अन्दर 10 कोआपरेटिव मिलें हैं और एक प्राईवेट है, वे सभी ठीक तरह से चल रही हैं, वहां कहीं पर भी कोई पेमैंट की दिक्कत नहीं है । लेकिन बिना सोचे समझे यह कह देना कि इससे ज्यादा रेट गन्ने के मिल सकते हैं, मिल वाले चुकवा लेंगे । स्पीकर साहब, हम भली भांति जानते हैं कि किसान को कितना पैसा मिलना चाहिये और सारे देश में हमने पहल करके, हरियाणा ने अच्छे भाव देकर के सारे देश को एक रास्ता दिखाया है और सोइंग होने से पहले पांच रुपये का रेट हमने बढ़ा दिया ताकि किसान का गन्ना ज्यादा आए और किसान इसी कारण से भाव को देखकर ज्यादा गन्ना बोए ।

दूसरी बात इन्होंने शीरे के बारे में भी कही कि किसी एक फैक्टरी को ज्यादा

फायदा होता होगा । साथ में इन्होंने आडीटर जनरल की रिपोर्ट का भी जिकर कर दिया । मैं इनको बताना चाहता हूं कि पहले इसके लिये पुराने नार्मज बने हुए थे । उन नार्मज को लगभग सभी प्रदेशों ने रिवाईज कर दिया और रिवाईज भी ऐसे नहीं किया । उन्होंने बाकायदा कमेटियां बना करके और नार्मज फिक्स करके कि किस प्रदेश में सीरे में से कंटैन्ट्स के मुताबिक कितनी सप्रिट बन सकती है । अब सब कुछ माडर्नाइज हो गया कुछ नई मिलें भी लग गयीं । आज में और पहले में बड़ा अन्तर है । मैं अब यह कहना चाहता हूं कि पंजाब में जो नार्मज थे, उनके अनुसार वहां पर 30.5, 30.6, 30.25 की सप्रिट की ऐवरेज निकली है और इन्होंने यहां पर पानीपत व हिसार की डिसटिलरी के बारे में भी कह दिया । मैं इनको बताना चाहता हूं कि 1991-92 में पानीपत में जो डिसटिलरी है वहां 30.04 और हिसार में जो असोसीऐट डिसटिलरी है उसकी फिगर सीरे की है, 31.77 । इसी तरह से 1992-93 में पानीपत की 30.26 और हिसार की 32.24 और 1993-94 में पानीपत की 26.14 और हिसार की 29.50 है यह रिकार्ड की बात बता रहा हूं । यूं ही फिजूल की गल्लबयानी करना यह कोई मुनासिब नहीं है । ये जो फिगर्ज मैं दे रहा हूं, कहो तो इसकी एक कापी आप लोगों को भी दे दूं, कहीं जा कर मिला लेना ।

इसी तरह से चौधरी बंसी लाल जी ने फरीदाबाद, आनन्दपुर, बड़खल और पाली क्षेत्रों में माइनिंग की बात भी कह दी । साथ में यह कह दिया कि सीरे की परसैन्टेज दूसरी स्टेटों में जैसाकि यू0पी0 है कहीं नहीं ले रहे हैं । मैं इनको बता देता हूं कि पंजाब में 65 परसैन्ट और हरियाणा में 50 परसैन्ट है । 65 परसैन्ट सैन्टर गवर्नमैंट लेती है और हम 50 परसैन्ट लेते हैं । यह भी रिकार्ड की बात है ।

दूसरे अध्यक्ष महोदय, जब चौधरी बंसी लाल जी मुख्य मन्त्री थे, उस वक्त का बताता हूं । वैसे जो उन्होंने कहा, वह ठीक है कि सारे एच0एम0एल0 को चलना चाहिये । एच0एम0एल0 के लिये उन्होंने इस तरह का फैसला किया था और उसके बाद में लोग कोर्ट में चले गये और उसके बाद राज्य सरकार को 10-12-86 को फिर लीज वापिस करनी पड़ी क्योंकि कोर्ट ने यह कह दिया था कि आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते । मैं यह रिकार्ड की बात कह रहा हूं । दिल्ली हाई कोर्ट में इसके लिये अपील की गई और उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 4-12-86 में, जबकि चौधरी बंसी लाल जी मुख्यमंत्री थे, माइनिंग लीजों को समाप्त करने के आदेशों को अवैध घोषित किया और 10-12-86 को राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के आदेशों पर रोक लगाने की अपील को लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया । तदनुसार लीजियों को खानों के कब्जे दिनांक 18-12-86 को वापिस किये गये । भारत सरकार ने जनवरी 1994 को माइनज एण्ड मिनरलज रेगुलेशन एक्ट और डिवैल्पमैंट एक्ट 1987 में संशोधन करके उन खनिजों को जो पहले सरकारी उपक्रमों को दी जाती थी अब निजी क्षेत्र में देने के लिये छूट दे दी । भारत सरकार ने यह भी कह दिया कि चाहे निजी क्षेत्र हो, चाहे सरकारी क्षेत्र हो,

[चौधरी भजन लाल]

सब को एक बराबर का दर्जा दिया जाना है । मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस लीज से कितना फायदा हुआ है । वर्ष 1986 में खनिजों से 5 करोड़ 12 लाख रुपए की आय थी तथा 1991-92 में 9 करोड़ 93 लाख रुपए की आय थी । यह बाद में बढ़ कर 1993-94 में 18 करोड़ 27 लाख रुपए हो गई और 1994-95 में 22 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी । तो कहां तो पांच करोड़ और कहां 22 करोड़ । यह रिकार्ड की बात है । अध्यक्ष महोदय, एक इन्होंने लिबर्टी सीड कार्पोरेशन का जिक्र किया । अध्यक्ष महोदय, यह ठीक बात है कि उनके सीड की शिकायत आई । हमने बाकायदा 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया और तीन को गिरफ्तार किया । 1580 एकड़ जमीन में यह सीड बीजा गया था और 238 किसान इससे प्रभावित हुए थे । जो हमें आंकड़े उपलब्ध करवाए गए हैं, उनके मुताबिक सीड में मुक्स था । अरली वैरायटी और लेट वैरायटी का सीड मिक्स हो गया था । उसकी वजह से एक वैरायटी पहले पक गई और दूसरी पकी नहीं, किसान को कच्ची काटनी पड़ी । उसके लिए बाकायदा डी0 सी0 की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई । उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया और तीन आदमी गिरफ्तार किए गए । कमेटी ने किसानों को कहा कि आप हमारे पास बैठ कर बात करें । किसानों के नुमायंदों ने बैठ कर बात की । उन्होंने कहा कि हमें तीन हजार एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए । अन्दाजे के मुताबिक उनका नुकसान एक हजार रुपए एकड़ के हिसाब से हुआ है । हमने कहा नहीं किसान को ज्यादा मुआवजा दिया जाए । डी0 सी0 और किसानों की आपस में बात चल रही है । हम चाहते हैं कि किसानों को पूरा मुआवजा मिले और बल्कि ब्याज समेत मिले । अगर किसान का एक हजार रुपए एकड़ का नुकसान हुआ है तो हम उसे दो हजार रुपए देंगे और अगर दो हजार का हुआ है तो चार हजार रुपए देंगे और जिन्होंने गल्त बीज बेचा है उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे । आपने कह दिया कि हमने उनका लाइसैंस क्यों नहीं कैंसिल किया । हमने उनका लाइसैंस कैंसिल कर दिया है और उनको आगे लाइसैंस देने का सवाल ही पैदा नहीं होता । अध्यक्ष महोदय, इन्होंने चार नदियों का जिक्र किया । ये राजस्थान की नदियां हैं । इनके बारे में हम अब क्या कह सकते हैं । एक तो ये हमारे सामने बैठे हैं, जिन्होंने मसानी बैराज शुरु करवाया था । उसके बाद बंसी लाल जी का राज आ गया । उन्होंने तो इसको स्टार्ट किया था और बंसी लाल जी ने उसको रोका नहीं और वह आगे बनता चला गया । ठीक है उसकी जरूरत नहीं थी । क्यों जरूरत नहीं थी कि साहबी और कृष्णावती नदियों का पानी राजस्थान से आता था और दोहन नदी का पानी तो पूरे एरिया में फैलता था । उससे कोई नुकसान का सवाल नहीं था । बल्कि पानी के साथ नई मिट्टी आती थी । जहां कहीं पानी का बहाव आता है तो फसलें टेढ़ी हो जाती हैं लेकिन कहीं भी कोई नुकसान की बात नहीं हुई । एक बार इत्तफाक से पानी ज्यादा आ गया था और वह दिल्ली की तरफ चला गया । उस समय दिल्ली की सरकार में भी चौधरी देवी लाल

सर्वो सर्वा थे और इधर भी उनका राज था । लेकिन मैं इतनी बात कह सकता हूं कि उस बैराज को बनाने से बहुत भारी नुकसान हुआ है । यह बात ठीक है कि राजस्थान ने भी छोटे छोटे बांध बनाए हैं, हमें पता लगा है । हमने उसके बारे में बात की । राम बिलास शर्मा जी ने भी कहा कि वह भी मेरे साथ राजस्थान जाने के लिए तैयार हैं । मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने हमारे साथ चलने के लिए कहा क्योंकि यह हरियाणा प्रदेश के हितों का सवाल है । राजस्थान के सी० एम० श्री शेखावत ने यह कहा था कि चौधरी भजन लाल जी आप आएं हम चल कर उस जगह को देखेंगे । अगर उन बांधों से हरियाणा प्रदेश को नुक्सान होता है तो वह नहीं होने देंगे ।

श्री अध्यक्ष : मसानी बैराज पर किवाड़ लगे हैं या नहीं लगे हैं ।

चौधरी भजन लाल : जी नहीं, अभी तक किवाड़ नहीं लगे हैं ।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है । आपने यह बात सही पूछी है कि उसके किवाड़ लगे हैं या नहीं लगे हैं । स्पीकर साहब, वहां पर किवाड़ नहीं लगे हैं । अभी तक वहां पर रैगुलेटर नहीं लगे हैं । जब तक उस बांध पर रैगुलेटर नहीं लगेंगे तो राजस्थान से जो पानी आएगा उसमें रुकावट कैसे होगी । स्पीकर साहब, पानी आने में जो रुकावट है वह राजस्थान वालों ने जो बांध बांध रखे हैं उनसे है हरियाणा वालों ने जो बांध बांध रखे हैं उनसे कोई रुकावट नहीं है । जिस समय हरियाणा के अन्दर बहुत भयंकर फ्लड आया था उस समय वह डैम बनाने की अरजैंसी थी इसलिए वह बांध बना था । हम बार-बार यह कह चुके हैं कि वह डैम वाजिब नहीं है और ये भी कह चुके हैं कि वह बांध वाजिब नहीं है लेकिन ये यह बात नहीं कह रहे कि राजस्थान वाले इन बांधों को कब तक हटाएंगे ?

प्रो० राम विलास शर्मा : स्पीकर साहब, मुख्य मन्त्री जी ने यह बात ठीक कही है कि साहिबी नदी पर जो बांध है उससे कोई फायदा नहीं है । वह बनाने से 40 करोड़ रुपए का नुक्सान हुआ है । जिस समय यह बांध बनाया गया उस समय सम्पत सिंह जी की पार्टी की सरकार थी । उस मामले के बारे में हमारे मुख्य मंत्री जी की और राजस्थान के मुख्य मंत्री जी की वार्ता हो रही है लेकिन यह सरकार जो काम शुरु करती है वह पूरा नहीं हो सकता लेकिन हमारी पार्टी की सरकार जो काम शुरु करती है वह पूरा होता है । हमारी पार्टी की सरकार ने तो अयोध्या में मन्दिर बना दिया था आप साहिबी बांध का काम पूरा नहीं कर सकते ?

चौधरी भजन लाल : राम बिलास जी आप मेरे छोटे भाई हैं । आपने वह काम करके अयोध्या का भट्ठा बिठा दिया । उस समय वहां पर कितनी जानें चली गई इस प्वायंट को मैं टच नहीं करना चाहता । (शोर)

प्रो० राम विलास शर्मा : रघुकूल रीत सदा चली आई प्राण जाई पर वचन न जाई। अयोध्या में मंदिर बनने पर ही गुजरात में हमारी पार्टी की सरकार बनी। (शोर)

चौधरी भजन लाल : उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी और हिमाचल प्रदेश में भी आपकी पार्टी की सरकार बन गई। आपका क्या मुकाबला है। (शोर)

प्रो० राम विलास शर्मा : आपने नैशनल इन्टेग्रेशन कमेटी की मीटिंग में हमारी पार्टी की सरकार बनने पर बधाई दी थी।

चौधरी भजन लाल : आप मंगलसूत्र, चूड़ियों और सिन्दूर की बात कर रहे थे। मैं इस प्वायंट को कहना नहीं चाहता था। बी० जे० पी० के आधे से ज्यादा लीडर कंवारे हैं इसलिए इनको क्या पता सिन्दूर कैसा होता है, मंगलसूत्र कैसा होता है और चूड़ियां कैसी होती हैं। मैं गिरजाघर, गुरुद्वारे और मंदिरों में कोई फर्क नहीं समझता। यह सब भगवान की पूजा के स्थल हैं। राम विलास जी राम की ठेकेदारी केवल आपकी नहीं है, सब की है। अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी ने नहरों की सफाई के बारे में बात कही। नहरों की सफाई करने के बारे में जितने भी माननीय सदस्यों ने सवाल पूछे, उनके तफसील से जवाब दिए गए। जहां तक फ्रीडम फाइटर्ज का सवाल है कि उनका मान और सम्मान होना चाहिए, यह बात ठीक है कि उनका मान और सम्मान होना चाहिए क्योंकि फ्रीडम फाइटर्ज की मेहरबानी से आज हम यहां पर बैठे हुए हैं। उन्होंने हमारे देश को आजाद करवाया इसलिए हमारा धर्म बनता है कि उनका मान और सम्मान होना चाहिए। हरियाणा सरकार ने फ्रीडम फाइटर्ज को पूरी सुख और सुविधा दी है। जितनी सुविधाएं एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर्ज को आज की सरकार ने हरियाणा प्रदेश में दी हुई हैं, उतनी सुविधाएं किसी भी प्रदेश में नहीं हैं। जहां तक रिजर्वेशन के कोटे की बात है। हमारे यहां 50 परसैंट रिजर्वड कोटा है। हम 50 परसैंट से ज्यादा उसको बढ़ा नहीं सकते, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। बंसी लाल जी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि ये वकील हैं इसमें 20 परसैंट हरिजन, 17 परसैंट एक्स सर्विसमैन, 10 परसैंट बैकवर्ड और 3 परसैंट फिजिकली हैन्डीकैप्ड लोगों को यह रिजर्वेशन दी गई है। मेरे कहने का मतलब यह है कि रिजर्वेशन 50 परसैंट से ज्यादा नहीं हो सकती।

श्री अध्यक्ष : अदर बीसीज को कहां खपाओगे ?

चौधरी भजन लाल : इसके लिए एक कमीशन बनाया गया था, उसकी रिपोर्ट आ गई है, उसको एग्जामिन किया जा रहा है। अदर दैन बीसीज के बारे में पूरी तरह से सोचना पड़ेगा। जल्दी में हम एक कम्युनिटी को शामिल कर लें कोई दूसरी रह जाये, दिक्कत आ सकती है इसलिए सारा मामला कैबिनेट में जायेगा और जो भी कैबिनेट में फैसला होगा वह यहां पर हम बताएंगे।

अध्यक्ष महोदय, यहां एक बात कर्मचारियों के बारे में कह दी । कर्मचारियों का कमीशन हमने बैठाया है । इसके अलावा पहले भी जब मैं मुख्यमन्त्री था तो जितनी सुविधाएं हम दे सकते थे दी हैं, इतनी सुविधाएं पहले किसी सरकार ने नहीं दी । बंसी लाल जी को कर्मचारी अब भी याद करते हैं कि कैसे दिल्ली में उनके साथ किया गया था, उनके जख्म अब भी हरे हैं, जब जून 87 में चुनाव हुए तो बंसी लाल जी का खुद का पता नहीं लगा कि ये कौन सी हवा में उड़ गए । मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे कर्मचारी और अधिकारी बहुत काबिल है दूसरे प्रदेशों में जाओ तो पता चलेगा कि कैसा राज उनका है और कैसा हमारा है । क्या उन कर्मचारियों का रोल है और किस ढंग से वे काम कर रहे हैं, यदि उनका मुकाबला हमारे कर्मचारियों के साथ करेंगे तो हमें बड़ा फख्र होगा कि हमारे मुलाजिमों का रोल सबसे अच्छा पायेगा । यहां पर एक बात कह दी कि शराब के ठेके पर लाठी चार्ज कर दी । वहां एक नेता था । मेरे को जहां तक पता है श्री जगन्नाथ जी और मनीराम जी थे । दोनों रोज रात को एक-एक बोतल पी जाते थे और उस दिन भी पी रखी थी । वे पहले हमारे साथी रहे हैं । बंसी लाल जी जान सकते हैं कि शराब पी गई थी या नहीं, क्योंकि ये खुद शराब तो नहीं पीते, बीड़ी नहीं पीते, हां लोगों का खून जरूर पीते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर एक बात कह दी कि एस0एस0एस0 बोर्ड के सदस्यों ने इन्टरव्यू देने वाले कैन्डीडेट्स से सवाल पूछे कि तूने ये कमीज कहां से सिलवाई, सलवार कहां से सिलवाई । ऐसी बात इन्टरव्यू पर बोर्ड या कमीशन को पूछनी नहीं चाहिए । मजाक में कोई बात हो जाए तो अलग है । अध्यक्ष महोदय, धीरपाल सिंह जी ने झज्जर और एस0वाई0एल0 के बारे में कहा । एस0वाई0एल0 के बारे में काफी चर्चा हो चुकी है, उन सभी बातों को बार-बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है । राम विलास शर्मा जी ने यहां पर एक बात कह दी । (विघ्न)

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय 15 मिनट बढ़ा दिया जाए ।

आवाजें : ठीक है ।

श्री अध्यक्ष : हाउस का समय 15 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है ।

वर्ष 1995-96 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

चौधरी मक्खन लाल : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि प्रस्ताव करने में क्या हर्ज था । अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसा प्रस्ताव हमने पहले ही

[चौधरी भजन लाल]

अपने राज में किया हुआ है और इसी सदन में किया हुआ है । अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात कहना नहीं चाहता था लेकिन बार-बार जब ये बात उठाई जाती है तो उसका जवाब तो देना ही पड़ता है । इसी काम्पलैक्स में, इसी बिल्डिंग की दूसरी साईड में पंजाब का सैशन भी चल रहा है । अगर हमने कोई ऐसा प्रस्ताव पास कर दिया और वे भी ऐसा ही कोई प्रस्ताव ले आएं कि हम यह नहर नहीं बनने देंगे तो हम क्या कर लेंगे ? अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिससे स्टेट के हितों को नुकसान पहुंचता हो । इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि यह बात स्टेट के हित में नहीं है इसलिए मेहरबानी करके बार-बार इस बात को न उठाएं । आखिर उनकी भी सरकार होगी, वे लोग भी अपने इन्ट्रस्ट की बात कर सकते हैं । अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो फिर हरियाणा प्रदेश का क्या बनेगा ? इसी प्रकार से ये लोग हर बात को उलझाने की कोशिश करते हैं ताकि कोई ऐसी स्थिति पैदा न हो जाए कि हम एस0वाई0एल0 बनवाने में कामयाब हो जाएं । ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से बिगाड़ पैदा हो ये किसी मसले को सुलझाना नहीं चाहते हैं । अध्यक्ष महोदय, यमुना जल के बारे में कितना शानदार समझौता हुआ है । वे लोग 1970 से लगे हुए थे, लेकिन इस बारे में 24-25 साल में कोई समझौता नहीं करवा सके और अब जब कि हमने समझौता करवा दिया है तो इनको तकलीफ हो रही है । एस0वाई0एल0 का फैसला करके 95 प्रतिशत नहर बनका दी है तो इनको तकलीफ हो रही है । अध्यक्ष महोदय, चाहे एस0वाई0 एल0 का मामला हो या यमुना जल समझौते का मामला हो, बहुत ही शानदार फैसला हुआ है और प्रदेश के हित में हुआ है । श्री राम भजन अग्रवाल जी ने बिजली की कमी के बारे में कहा और यह भी कहा कि खम्बे लोहे के हैं जो कि गल गए या खराब हो गए और बिजली ठीक नहीं पहुंचती है । इसके साथ ही उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है कि डिस्ट्रीब्यूशन और बिजली पैदा करने के महकमे अलग-अलग हो जाएं तो ज्यादा अच्छा है । उनका यह सुझाव विचार करने योग्य है । यह ठीक है कि बिजली कोई पैदा करे और बिजली डिस्ट्रीब्यूट कोई करे । इससे यह हिसाब लगाया जा सकता है कि मान लो अगर महकमे ने एक लाख यूनिट बिजली दी तो डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले महकमे से उसका हिसाब पूछा जा सकता है । यह बात बिल्कुल ठीक है । अध्यक्ष महोदय, लाईन लासिज भी पहले के मुकाबले में काफी कम हुए हैं । अध्यक्ष महोदय, जहां तक सेल्ज टैक्स की बात है इन्होंने कहा कि सेल्ज टैक्स सलैब्ज होनी चाहिएं । सेल्ज टैक्स के बारे में मैं सारे सदन को बताना चाहूंगा कि सारे नार्दन इण्डिया में या देश को चार हिस्सों में बांट कर ऐसी नीति बनाई जानी चाहिए कि सेल्ज टैक्स और मार्कीट टैक्स का रेट एक जैसा होना चाहिए ताकि उसमें टैक्स की चोरी न हो पाए या कोई बेईमानी न कर सके । अध्यक्ष महोदय, इस बारे में हरियाणा ने सबसे पहले पहल की है और हरियाणा की अगुवाई में और स्टेटों के मुख्य मन्त्रियों की एक बैठक हमने हरियाणा भवन, नई दिल्ली में

बुलाई थी । हमने इस बारे में प्रधान मन्त्री जी से प्रार्थना की और उन्होंने उस मीटिंग में केन्द्रीय वित्त मंत्री को भाग लेने के लिए भेजा । 4-5 मंत्री भी हमारे साथ थे । उस मीटिंग में अच्छी डिस्कशन हुई । उसके बाद चीफ सैक्रेटरियों से हमारी मीटिंग हुई । इससे पहले चीफ सैक्रेटरियों की भी एक बैठक हुई थी । अब यह मामला काफी नजदीक लगा हुआ है और हम चाहते हैं कि सारे देश में सेल्ज टैक्स एक जैसा हो जाए ताकि कहीं पर भी कोई बेइमानी न कर पाए । माईनोरिटीज के साथ एट्रोसिटीज का कोई सवाल ही नहीं है । एस0वाई0एल0 के बारे में डा0 राम प्रकाश जी ने कहा और शिक्षा के बारे में भी कुछ सुझाव उन्होंने दिए और यह भी कहा कि एस0सीज0 और बी0 सीज0 को रोस्टरवाईज रखना चाहिए । यह बात ठीक है, रोस्टर सिस्टम हमने अपनाया हुआ है । उन्होंने एक बात सूर्य ग्रहण के बारे में कही । इस मेले के लिए जितना भी प्रबन्ध हम कर सकते हैं करने की कोशिश करेंगे । इसके अलावा ब्रह्म सरोवर पर भी काम लगा हुआ है और अगर कोई सड़क वगैरा ठीक नहीं है तो उसको भी ठीक करवा देंगे । श्री राम बिलास शर्मा जी ने भी एस0वाई0एल0 नहर का जिक्र किया और प्रस्ताव का भी जिक्र किया इस बारे में मैंने अभी बता दिया है। बीज के बारे में भी मैंने बताया है हत्या तथा बलात्कार की बात भी आई । सका कारण कुछ भी रहा हो लेकिन ला-एण्ड आर्डर जितना शानदार हरियाणा प्रदेश के अन्दर है उतना कहीं नहीं है । आप बाहर जा कर देखेंगे पड़ौसी राज्यों में तो आपको पता चलेगा कि सबसे शानदार ला-एण्ड आर्डर अगर कहीं है तो वह हरियाणा प्रदेश के अन्दर है । अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कहता कि राम राज्य हो गया है । राम राज्य तो राम चन्द्र जी के वक्त में भी नहीं था । उस जमाने में भी राक्षस थे और सीता जी का हरण हो गया था । (विघ्न) ऐसे राक्षस राज्य में आज भी हैं जो कि ऐसे काम कर सकते हैं । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : डा0 राम प्रकाश जी ने नहर के बारे में कहा था कि कहीं कहीं से नहर टूटी हुई है, उसके बारे में भी अगर बता दें तो ठीक रहेगा ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, नहरें तो बार-बार टूटती रहती हैं । इस बारे में इन्होंने पिछली बार भी बताया था और मेहरा साहब वहां पर गए भी थे और देखकर आए थे । वहां पर हम साईकल बनाने जा रहे हैं और आने वाली बरसात से पहले ही उम्मीद है कि हम उसको ठीक कर देंगे ताकि वहां पर पानी फिर से न आए ।

अध्यक्ष महोदय, एक इन्होंने संस्कृति की बात कर दी और सुशीला कांड की बात कही है । यह केस हमने सी0बी0आई0 को दिया है । कुछ भाई तो यह कह रहे थे कि उसमें भजन लाल के किसी रिश्तेदार का हाथ था । भजन लाल के गांव के आदमी का हाथ है और कोई बिशनोई है । इनको तो पता नहीं जाति से क्या फोबिया हो गया है । क्या जाति-पाती से काम चलेगा ? अध्यक्ष महोदय, हमारे

[चौधरी भजन लाल]

दिमाग में न तो कभी जाति-पाती की बात आई है और न ही कभी आएगी । हमारे लिए 36 बिरादरी के भाई सब एक समान हैं । जो सियासी आदमी सबको एक साथ लेकर नहीं चलता है वह जिन्दगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता है । एक बात और कर्ण सिंह दलाल ने कह दी कि मैं फरीदाबाद से एम0पी0 बन गया । यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है । यह कोई छोटी बात नहीं है । बाकी लोग तो जात-पात देखकर ही टिकट मांगते हैं कि यहां पर फलाना बिरादरी के इतने लोग हैं इसलिए मैं तो यहां से इलैक्शन लड़ूंगा । अध्यक्ष महोदय, जहां पर एक वोट भी मेरा न हो और वहां से डेढ़ लाख वोटों से लोग भजन लाल को जिता दें तो यह कोई छोटी बात नहीं है । यह इसलिए है क्योंकि भजन लाल सैकुलर आदमी है और सबको साथ लेकर चलता है । यह उसी का नतीजा है । मेवात में भी चार सैगमैंट हैं और वहां का मेल कैंडीडेट मेरे मुकाबले में हो और मैं वहां पर भी सभी जगहों पर जीता और मैं डेढ़ लाख वोटों से जीता था । (विघ्न) आप सुनिए तो सही । हमने बहुत काम किए हैं और जिस मिल की बात आप कर रहे हैं यह भजन लाल के जमाने की ही लगी हुई है । यह आपको याद होना चाहिए । इसके अलावा पिछले 3–4 सालों में और भी जितने विकास के काम हुए हैं, वह भी हम आपको बता देंगे ।

अध्यक्ष महोदय, चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने औद्योगीकरण के बारे में कहा और बेरोजगारी को दूर करने के लिए कहा । अध्यक्ष महोदय, हमने तो बहुत पहले ही संकल्प किया है कि इन्डस्ट्री को हरियाणा प्रदेश में लगाएंगे । बहुत से लोग तो बाहर से आ रहे हैं । हमने यह फैसला किया है कि इसमें जितने भी उद्योग लगेंगे उनमें हमारे हरियाणा के नौजवानों को रोजगार मिलेगा । अगर कोई बहुत बड़ा टैक्नीकल आदमी हरियाणा में नहीं मिले तो वह कम्पनी अखबार में तीन बार एडवर-टाईज करेगी और इसके बाद भी उन्हें कोई आदमी हरियाणा का नहीं मिलता है तो वे बाहर से ले सकते हैं । अगर वे ऐसा करेंगे तो ही हम उसको लाईसैंस देंगे, जमीन देंगे, बिजली और पानी देंगे और तभी उसको लोन देंगे ।

चौधरी बलवन्त सिंह मायना । अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है । अध्यक्ष महोदय, बहादुरगढ़, सांपला और रोहतक के अन्दर फैक्टरियां लगी हुई हैं और फैक्टरियों वालों ने लोगों की जमीन ली हैं । वहां पर रहने वाले गरीब लोगों को नौकरी नहीं दी जा रही है ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, वही तो मैं बता रहा हूं । हमने दो लाख के करीब हरियाणा प्रदेश के कुछ पढ़े-लिखे और कुछ अनपढ़ लोगों को रोजगार दिया है ।

अध्यक्ष महोदय, बिजली के बारे में भी कहा गया कि इसको प्राईवेट सैक्टर में दे दिया जाए । इस बारे में हमने अढ़ाई-तीन महीने पहले ही फैसला कर दिया है

और बाकायदा इस बारे में एडवरटाईज भी किया था । पहले तो इसकी मियाद 28 फरवरी तक थी और इसको बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दिया है । इसमें कोई भी आदमी 75 मैगावाट से 100 मैगावाट तक प्लांट लगा सकता है । चाहे वह डीजल से लगाए या चाहे वह कोयले से लगाए । वह किसी भी शहर में अपना प्लांट लगा सकता है, इस बात की हमने छूट दे रखी है । इसके लिए हमने टैण्डर भी इन्वाईट कर रखा है ताकि प्राईवेट लोग भी आएं और यहां पर आकर प्लांट लगाएं ।

अध्यक्ष महोदय, एक इन्होंने यह भी कह दिया कि हमने लोन महंगे रेट पर ले लिया । हमने बाकायदा एडवरटाईज किया है और दो बार तो इसकी मियाद भी बढ़ाई कि हरियाणा बिजली बोर्ड को पैसे की आवश्यकता है । यह आवश्यकता क्यों है क्योंकि हम किसानों को सबसीडाईज करके बिजली देते हैं । इसलिए बिजली बोर्ड को साल में साढ़े तीन करोड़ रुपए का घाटा हो जाता है । हमें भारत सरकार से 2.30 रुपए प्रति यूनिट पर बिजली मिलती है और हमें घर की बिजली जो है वह 1.55 रुपए में पड़ती है और किसानों को हम बिजली 50-60 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से देते हैं । हरियाणा में आप यह समझ लीजिए कि बिजली बोर्ड को कम से कम 1.20 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से किसानों को सबसीडाईज करके बिजली देने में घाटा होता है । इन्होंने कह दिया कि 16.50 परसैन्ट में लोन लिया लेकिन हम तो कहते हैं कि नहीं 18 परसैन्ट में भी हमने लोन लिया है और मैं यह भी कहता हूं कि अगर इससे भी ज्यादा परसैन्ट में कोई हमें लोन देने वाला हो तो हम उस से लोन लेने के लिए तैयार हैं । हम उसका लोन वापस कर देंगे । हमने यह कंडीशन रखी है कि जब हमारे पास पैसा हो जाएगा तो हम आपका लोन वापस कर देंगे । अगर कोयला लेने के लिए पैसे न हों, सामान लेने के लिए पैसे न हों तथा इसके अलावा हम जो बिजली भारत सरकार से 50 करोड़ रुपये की लेते हैं तो वह महीने में 25 करोड़ यानी आधा हो जाता है क्योंकि बिजली का पैसा वहां से कम मिलता है । अगर हम भारत सरकार को पैसा नहीं देंगे तो वह हमें बिजली नहीं देंगे । एक बार जब उन्होंने बिजली काट दी थी तब हाहाकार मच गया था । तब हमने बड़ी मुश्किल से उनसे कहकर दोबारा से कनैक्शन जुड़वाया और उनसे वायदा किया कि हम आपको बिजली का पैसा देंगे । अध्यक्ष महोदय, अगर रेल के किराए के लिए पैसे न हों, कोयले के लिए पैसे न हों तो क्या बिजली जादू से बनती है इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसी बातों के कहने का कोई फायदा नहीं है । हमने बहुत ज्यादा बिजली का उत्पादन किया है और किसानों को भी हमने बिजली दी है । हम चाहते हैं कि किसानों को पूरी बिजली मिले, कारखाने लगें, फैक्ट्री लगें । 1989-90 में जब सम्पत सिंह जी के पास यह महकमा था तो उस समय लाइन लौसिज 29.19 था लेकिन हमने इनके मुकाबले में लाइन लौसिज को कम किया है । 1990-91 में लाइन लौसिज 27.59 था लेकिन बाद में जब हमारा राज आया तो लाइन लौसिज 27.27 तथा 1992-93 में

[चौधरी भजन लाल]

25.22 और 1993-94 में लाइन लौसिज 24.53 था । अध्यक्ष महोदय, हमने लाइन लासिज को भी कम करने की कोशिश की है, लेकिन मैं इस बात से भी इंकार नहीं करता कि लाइन लौसिज और भी कम होने चाहिए और बिजली की चोरी भी कम होनी चाहिए । हमने बिजली की पहले के मुकाबले में ज्यादा पैदावार की है और किसानों को दी है । अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि पिछले दो तीन महीनों में ही बिजली की हमको कोई शिकायत नहीं मिली है और हम जहां पर भी जाते हैं तो लोग तारीफ करते हैं और कहते हैं कि बिजली में काफी हद तक सुधार हुआ है । हमारी आगे भी पूरी कोशिश होगी कि बिजली में सुधार किया जाए ।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है । सारे, हरियाणा में बिजली नहीं है बच्चों के पढ़ने के लिए बिजली नहीं है*****

श्री छत्तर सिंह चौहान : स्पीकर सर * * * * (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : इन्होंने बिना इजाजत से जो कुछ कहा है, वह रिकार्ड न किया जाये ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक बात और कह दी । मैं अपनी बात दो मिनट में पूरी कर लेता हूं । मैं बंसीलाल जी से कहूंगा कि वे अपने मैम्बर्ज को पढ़ाया करें, सिखाया करें, । इनको हाउस को चलाने का तरीका सीखना चाहिए । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, यह भी जिक्र किया कि कैथल जिले में क्योड़क में 25 परिवार नाफ्स नहीं गए । राम बिलास जी ने भी कहा कि ये उनको वहां पर जाकर देख आएं । बड़ी गजब की बात है । शर्मा जी, आप तो ब्राह्मण हो, इसलिए ब्राह्मण तो गलत नहीं बोलता क्योंकि वह डरता है कि कहीं ऊपर से शिवजी महाराज न आ जाएं । आपको तो यह बात शोभा नहीं देती ।

श्री अमर सिंह ढांडे : स्पीकर सर, * * * * * *

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए । यह रिकार्ड न किया जाए । (व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, लोग मेरे पास भी आए थे । वहां हरिजनों में आपस में झगड़ा था ।

प्रो० राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मैंने गलत बोला ।

चौधरी भजन लाल : मैंने गलत बोलने के लिए नहीं कहा बल्कि मैंने कहा कि आपने ठीक नहीं कहा ।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया ।

प्रो0 राम विलास शर्मा : स्पीकर सर, मैंने इस सदन में बड़े ही आग्रहपूर्वक यह बात कही थी कि 19 तारीख को मैं इन लोगों से कैथल में क्योड़क में मिलकर आया हूं। आज भी 25 परिवार कैथल में हैं और वह वापस क्योड़क में नहीं गए। कुछ परिवार तो जरूर वापस चले गए हैं लेकिन 25 परिवार आज भी क्योड़क में नहीं गए।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय 5 मिनट के लिए और बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : जी हां।

श्री अध्यक्ष : हाउस का समय पांच मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है।

वर्ष 1995-96 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, डर की वजह से कोई परिवार नहीं गया। डिप्टी कमिश्नर, डी0आई0जी0, कमिश्नर और एस0पी0 सब ने मौके पर जाकर गांव में जाकर लोगों से बात चीत की और कहा कि किसी आदमी के साथ ज्यादती, जुल्म, अन्याय हो गया तो हमारे से बुरा कोई नहीं होगा। हरिजनों को पूरा विश्वास देकर के आए। हरिजनों का आपस का झगड़ा था कत्ल हो गया और कत्ल की बिनाह पर ऐसा मामला हो गया इसमें भी हम जात-पात को ले आएंगे तो कोई अच्छी बात नहीं।

श्री अमर सिंह डांडे : अध्यक्ष महोदय, हम तो यह कहते हैं कि जो 25 परिवार चले गए हैं उनको बसाने की कोशिश करें। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : शुरु में आए थे लेकिन चले गए। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, राम विलास जी ने पृथला कांड की बात कही थी। इस मामले में दो आदमी पकड़े हैं और सी0बी0आई0 ने जांच की और जांच करने के बाद उसमें कुछ मिला नहीं। आज से लगभग दस दिन पहले बाकायदा कोर्ट ने जमानत ले के छोड़ दिया। जो बातें कहीं थीं उनका मैंने जवाब दिया है बाकी बातों का जवाब विस्तार से कल वित्त मंत्री जी देंगे। बहुत शानदार बजट पेश किया है, इसकी सराहना सबकी करनी चाहिए।

Mr. Speaker : Now the House is adjourned till 9.30 A.M. tomorrow, the 22nd March, 1995.

*13-47 hrs. (The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. on Wednesday, the 22nd March, 1995.)

26773—H.V.S.—H.G.P., Chd.